खण्ड-07 सत्र-04 (भाग-3) / अंक-45

बुधवार 16 अगस्त, 2023 / 25 श्रावण, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-04 में अंक 45 से अंक 47 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 (भाग-3) बुधवार, 16 अगस्त, 2023/25 श्रावण, 1945(शक) अंक-45

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	4-7
3.	माननीय उपराज्यपाल के पत्र द्वारा विधान सभा के चौथे सत्र के तीसरे भाग को बुलाने पर आपत्ति जताने पर माननीया अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	8-12
4.	सदन में अव्यवस्था	13-15
5.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	16-36
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात	37-38
7.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	39-147
8.	विशेषाधिकार प्रश्न (नियम-66) एवं उस पर चर्चा	148-202
9.	धन्यवाद प्रस्ताव	203-211

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 (भाग-3) बुधवार, 16 अगस्त, 2023/25 श्रावण, 1945 (शक) अंक-45

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अमानतुल्ला खान
6. श्री अब्दुल रहमान
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. सुश्री भावना गौड़
9. श्री बी एस जून
10. श्री धर्मपाल लाकड़ा
11. श्री दिनेश मोहनिया
12 श्री दुर्गेश कुमार
13. श्री गिरीश सोनी
14. श्री गुलाब सिंह
15. श्री हाजी युनूस
16. श्री जय भगवान
17. श्री जरनैल सिंह
18. श्री करतार सिंह तंवर
19. श्री कुलदीप कुमार
20. श्री महेंद्र गोयल

21. श्री मुकेश अहलावत
22. श्री मदन लाल
23. श्री नरेश बाल्यान
24. श्री नरेश यादव
25. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
26. श्री प्रवीण कुमार
27. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
28. श्री राजेश गुप्ता
29. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
30. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
31. श्री राजेश ऋषि
32. श्री रोहित कुमार
33. श्री शरद कुमार चौहान
34. श्री संजीव झा
35. श्री सोमदत्त
36. श्री शिवचरण गोयल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्री सही राम
39. श्री एस के बग्गा
40. श्री सुरेंद्र कुमार
41. श्री विनय मिश्रा
42. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
43. श्री अभय वर्मा
44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
45. श्री अजय कुमार महावर
46. श्री जितेंद्र महाजन
47. श्री मोहन सिंह बिष्ट
48. श्री ओम प्रकाश शर्मा
49. श्री पवन शर्मा
50. श्री प्रलाद सिंह साहनी
51. श्री प्रकाश जारवाल
52. श्री ऋतुराज गोविंद
53. श्री रघुविंदर शौकीन
54. श्री शोएब इकबाल
55. श्री विजेंद्र गुप्ता
56. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्रा-4 (भाग-3) बुधवार, 16 अगस्त, 2023/25 श्रावण, 1945 (शक) अंक-45

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.10 बजे समवेत हुआ ।

माननीय उपाअध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं ।

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्

माननीया अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के तीसरे भाग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। यह सत्र विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया गया है। अत: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनतापूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब न होने दें। साथ ही, कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना न उठायें। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में मुझे सहयोग करेंगे।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीया अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आपको विदित है कि दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में पांच जवान शहीद हो गये जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एक कायरतापूर्ण तथा बर्बरतापूर्ण हमला था और घात लगाकर किया गया था। इसकी जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। शहीद हुए पांचों सैनिकों में से चार पंजाब के और एक ओडिशा का रहने वाला था। देबाशीष बस्वाल ओडिशा के अलगुम सामिल खंडायत के निवासी थे, जबकि मनदीप सिंह पंजाब के चानकोईयां काकन गांव के, हरकृष सिंह तलवंडी बारथ गांव के, कुलवंत सिंह चारिक के और सेवक सिंह बाघा के रहने वाले थे। देश की सुरक्षा के लिए इन जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस तरह की बढ़ती घटनायें देश की सुरक्षा के लिए चिंताजनक हैं। मैं जम्मू-कश्मीर में शहीद जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण, आपको ज्ञात होगा कि दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में जिला रिजर्व गार्ड के दस जवान और एक ड्राईवर शहीद हो गये। नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट से उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उस जगह पर दस

फुट गहरा गडढ़ा हो गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों पर नक्सलियों द्वारा किया गया यह बहुत बड़ा हमला था। इस हमले में हेड कांसटेबल जोगा सोढी, मुन्ना राम कड़ती, संतोश तामो, नव आरक्षक दुल्गो मंडावी, लखमू, मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करतम, जयराम सहित कई अन्य जो सैनिक हैं वो शहीद हो गये। इस कायरतापूर्ण हमले की जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत अनमोल है। मैं छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 02 जून, 2023 को ओडिशा के बहानागा में तीन ट्रेनों की टक्कर होने से भयानक दुर्घटना में 288 लोगों की जान चली गई और कम से कम 1175 लोग घायल हो गये। यह गत तीन दशकों के दौरान होने वाला सबसे भीषण रेल हादसा बताया जा रहा है। इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस रेल दुर्घटना के मृतकों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करती हूं। माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों उतराखंड और

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा आवागमन अवरू) हो गया। मैं प्राकृतिक हादसे के कारण जान गंवाने वाले लोगों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं।

मणिपुर हिंसा और नूंह हिंसा में भी माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 03 मई, 2023 को मणिपुर में दो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक इस हिंसा में कम से कम 152 लोग मारे गये हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना और पुलिस के संघर्ष के कारण साठ हजार से ज्यादा लोगों को अपने घर से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह हरियाणा के नूंह में भी दिनांक 31 जुलाई, 2023 को एक धार्मिक रैली के दौरान दो समुदायों के बीच टकराव होने से पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग से ज्यादा घायल हो गये। इस घटना के बाद नूंह और आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों ने हिंसा को अंजाम दिया तथा आगजनी और तोड़फोड़ करने लगे। इससे सामाजिक सद्‌भावना को ठेस पहुंची और उस क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया। वहां हिंसा पर अब तक रोक लग गई है लेकिन सामाजिक तानेबाने को बहुत क्षति

पहुंची है। हिंसा की कोई भी घटना हल्के में नहीं ली जा सकती। हिंसा और साम्प्रदायिक तनाव की आग बहुत खतरनाक होती है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही मणिपुर में जनजीवन सामान्य होगा और इसके लिए वहां का प्रशासन पुरजोर प्रयास कर रहा है। मैं मणिपुर हिंसा और नूंह हिंसा के मृतकों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी मैं कामना करती हूं। माननीय सदस्यगण यह दुखद सूचना है कि त्रिलोकपुरी के क्षेत्र से विधायक रोहित कुमार महरौलिया जीके पिता जी श्री ओम प्रकाश महरौलिया जी का गत 10 अगस्त, 2023 को लम्बी बीमारी के कारण देहावसान हो गया। वे 68 वर्ष के थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि श्री रोहित कुमार महरौलिया जी और उनके पूरे परिवार को इस अपार दुख को सहन करनी की शक्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्यगण, कल 15 अगस्त, 2023 को भारत में शौचालय क्रांति के जनक सफलभ इंटरनेशनल के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक का निधान हो गया। उन्हें टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता था। खुले में शौच और खराब सार्वजनिक शौचालयों को हटाने के लिए उन्होंने वर्ष 1970 में सफलभ इंटरनेशनल की शुरूआत की। उनमें सर पर मैला उठाने की परम्परा को समाप्त

करने के प्रति गहरा जुनून था। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें 50 से अधिक सम्मान मिले थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री बिंदेश्वर पाठक को श्रद्धांजलि देती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति दें। अब दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

माननीया अध्यक्षः ओम शांति। माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी का जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देती हूं तथा कामना करती हूं कि वो दीर्घायु हों और अपने राजनैतिक जीवन में नई ऊंचाईयां प्राप्त करें तथा देश की निरन्तर सेवा करते रहें। माननीय सदस्यगण, माननीय उप-राज्यपाल ने 11 अगस्त, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसकी प्रति विधान सभा सचिव को भी भेजी गई है। माननीय उप-राज्यपाल ने चौथे सत्र के तीसरे भाग को बुलाने पर आपत्ति जताई है। उनका विचार है कि सभी सत्रों का सत्रावसान कर दिया जाना चाहिए तथा फिर, उनकी अनुमति से सत्र बुलाया जाना चाहिए और एक वर्ष में तीन सत्र होने चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 17 अप्रैल, 2023 को आयोजित सदन की बैठक के

संबंध में भी इसी तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ था। मैंने सदन में व्यवस्था भी दी थी और स्पष्ट किया था कि सदन, नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया गया है और उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था। इसके अलावा संसद और अन्य विधानमंडलों में भी ऐसे आंशिक सत्र बुलाए जाते रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूं कि दिल्ली विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम–17के तहत, अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है। लोकसभा सहित सभा विधानमंडलों में यही प्रथा है। लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के नियम–15 में भी लोकसभा अध्यक्ष को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। रामदास अठावले बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सत्र के दूसरे भाग की कार्यवाही की वैधता को बरकरार रखा था, जिसे 29 जनवरी, 2004 को फिर से बुलाया गया था। सदन को स्थगित करना और बुलाना, पूरी तरह से सरकार का विशेषाधिकार है। यदि मंत्रिपरिषद सदन का सत्रावसान करने की सिफारिश करती है तो अगला सत्र नियम–03 के तहत माननीय उप–राज्यपाल की मंजूरी के साथ बुलाया जाता है। यदि सदन का सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो इसे नियम–17 के तहत अध्यक्ष की मंजूरी के साथ फिर से बुलाया जाता है। पूरे भारत में यही प्रथा है और संविधान तथा विधान सभा नियमों में भी

यही प्रावधान किया गया है। माननीय उप-राज्यपाल ने यह भी कहा है कि सत्र के दौरान किसी भी प्रस्तावित विधायी कार्य का कोई भी संकेत नहीं है। मैं बताना चाहती हूं कि नियम-15(।) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्यक्ष ही है जो माननीय मुख्यमंत्री के परामर्श से सदन के कार्य का निर्णय करेंगे। इन मामलों में माननीय उप-राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। सभी बैठकों में विधायी कार्य होना भी आवश्यक नहीं है। दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए वर्ष 1993 से अब तक कई बार सदन बुलाया गया है। माननीय उप-राज्यपाल ने गंभीर आरोप लगाया है कि माननीय अध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसले की घोर उपेक्षा करते हुए, पांचवें सत्र को बुलाने की बजाय चौथे सत्र के दूसरे भाग को फिर से बुलाने का एकतरफा फैसला किया। मैं फिर दोहराना चाहती हूं और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि कैबिनेट ने सदन के सत्रावसान की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए सदन को नियम-17 के तहत फिर से बुलाया गया था। माननीय उप-राज्यपाल को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट इसकी सिफारिश नहीं करती, तब तक नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें इस तरह के निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। माननीय उप-राज्यपाल ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई है कि सदन को कैबिनेट के फैसले के बिना फिर से बुलाया गया है और यह न केवल कार्य संचालन नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(संशोधान) अध्यादेश, 2023 की धारा 45-जे की उप-धारा (4) के खंड (vi) के साथ पठित एनसीटी एक्ट की धारा-6 की भावना का भी उल्लंघन है। माननीय सदस्यगण, धारा-6 में कहा गया है कि माननीय उप-राज्यपाल समय-समय पर विधान सभा को बुलाएंगे। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा केवल मंत्री परिषद की अनुशंसा पर ही किया जा सकता है। हालांकि यह केवल पिछले सत्र के सत्रावसान के बाद, नए सत्र पर ही लागू होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नियम-17 के तहत अध्यक्ष द्वारा सदन को किसी भी समय फिर से बुलाया जा सकता है, यदि सत्रावसान नहीं किया गया हो। दिनांक 08 अगस्त, 2023 को मुझे माननीय विधि और विधायी मामलों के मंत्री से, सदन को 16 अगस्त, 2023 को फिर से बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ एक नोट मिला और मैंने यही किया। लोकसभा में आंशिक सत्र को बुलाने की यही स्थिति और परिपाटी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधान) अध्यादेश, 2023 की धारा-45-जे की उप-धारा (4) के खंड (vi) का भी कोई उल्लेख नहीं है, जैसे ही अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधान) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस खंड में कहा गया है कि विधान सभा को बुलाने और सत्रावसान करने का मामला, कोई भी आदेश जारी करने से पहले, सरकार के सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल को उनकी राय के लिए भेजा जाएगा। यह खंड नए सत्र को बुलाने से संबंधित है, न

कि आंशिक सत्र को बुलाने से, क्योंकि आंशिक सत्र को दोबारा बुलाने में माननीय उप-राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा यह उन आदेशों से संबंधित है, जिन्होंने विभाग के सचिव को जारी करना होता है और यह विधान सभा सचिवालय पर लागू नहीं होता है और न ही हो सकता है। माननीय उप-राज्यपाल इस बात से भी व्यथित नजर आ रह हैं कि संसद और अन्य विधानमंडलों में एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं, (बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र) जबकि दिल्ली विधानसभा में केवल एक। मैं सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना चाहूंगी कि हमारे संविधान या एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून या शीतकालीन सत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह औपनिवेशिक युग की मात्र शब्दावली है, जिसका उपयोग आम बोलचाल में आसानी से समझने के लिए किया जाता है। अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि सदन की यह बैठक संविधान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम और प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई है और इस विषय पर की गई आपत्तियां, पूरी तरह से योग्यताहीन हैं और कानून की सरासर गलत व्याख्या पर आधारित है। 280।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): माननीया अध्यक्ष महोदया, दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय ने जो पत्र लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीया अध्यक्षः मैने उस सम्बन्धा में अपनी रूलिंग दे दी। इसके अलावा आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं कहना चाहता हूं। आप मुझे पूरे देश में एक राज्य विधान सभा बता दीजिए जहां क्वेश्चन ऑवर ना किया जाता होउस में।..

माननीया अध्यक्षः मैंने ..

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब विधान सभा में क्वेश्चन ऑवर नहीं होगा। विधान सभा में वे मुद्दे उठाये जायेंगे जो विधान सभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जो दिल्ली की समस्याएं हैं।

माननीया अध्यक्षः आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जी।

माननीया अध्यक्षः आपने आज का बुलेटिन पढ़ा, आज का आपने देखा है.

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं बुलेटिन, मैंडम आप मुझे बताईये इसके लिए भी बिजनेस एडवाईजरी कमेटी है। शार्ट डयूरेशन डिस्कशन यदि हाउस में होगा तो बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में तय होगा, सारे नियमों का उल्लघंन करके दिल्ली विधान सभा चलाई जा रही है। आखिर इसकी उपयोगिता क्या है?..

माननीया अध्यक्षः इसकी उपयोगिता आपने आज का देखा नहीं। जो बुलेटिन आपके पास आया है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हमने बारह नोटिसेज दिये हैं।..

माननीया अध्यक्षः हाँ तो बारह नोटिसेज मैं पढ़ देती हूं। आपके नोटिस पहले पढ़ देती हूं आप बैठिये। आपके नोटिस पर मैं रूलिंग दे देती हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा कई अन्यमाननीय सदस्यों से नियम 55 के अन्तर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। धन्यवाद। 280 श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये। मोहन सिंह बिष्ट जी 280।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः 280,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मोहन सिहं बिष्ट जी 280 में आप बोलिये। बैठ जाईये अजय महावर जी अगला नम्बर आप ही का है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अगला नम्बर आप ही का है बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी अगला नम्बर जो है अजय महावर जी का है। उसके बाद अगर आप लोग समय देंगे तो जिस-जिस का विषय है सबको पता है। अगर सब लोग सहयोग करते हैं तो मैं सबको बोलने का मौका देती हूं। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो नहीं बोल पाता है। अब ये आपको तय करना है, राजनीति करनी है या अपने क्षेत्र का विषय यहां उठाना है या सदन को डिस्टर्ब करना है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाईये। सदन में आप राजनीति करने आये हैं। जनता के विषय उठाने नहीं आये हैं। जनता के विषय नहीं उठायेंगे आप। सदन आपको राजनीति का अखाड़ा लगता है। ये सदन आपको राजनीति का अखाड़ा लगता है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नहीं आप अपने शब्द वापिस लीजिए, राजनैतिक अखाड़ा है। राजनीति आप सदन के बाहर करियेगा। आप राजनीति सदन के बाहर करियेगा। सदन राजनैतिक अखाड़ा नहीं हो सकता है। यहां पर जनता के विषयों पर चर्चा होगी। जनता के विषयों पर चर्चा होगी। दिल्ली वासियों के विषय पर चर्चा होगी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप सोचिये आपने क्या बोला है। ये राजनैतिक अखाड़ा लगता है आपको सदन का पटल। बैठिये बिधूड़ी साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं बैठिये। बोलिये जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी विधान सभा करावल नगर की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदया मेरी विधान सभा के अन्तर्गत दो बंध बने हुए हैं। एक ओर एल एफ बंध और दूसरी और मर्जनल बंधा। खजूरी से लेकर के सहारनपुर तक मर्जनल बंध है और है एल एफ बंध जोकि नानकसर से लेकर ट्रोनिका सिटी तक है और मर्जिनल बंध से सहारनपुर तक जाने वाले मर्जनल बंध के अन्तर्गत और एलएफ बंध के यमुना नदी, यमुना नदी होने के कारण पिछले दिनों के अंदर यहां पर पूरी तरह से जल मग्न हो गया। और दूसरी और मर्जिनल बंध है वो खजूरी से ले करके सहारनपुर तक हैं, वहां ऐलिवेटिड रोड का काम चल रहा है। अध्यक्षा जी ऐलिवेटिड रोड की वजह से वहां पर कई जगह सब-वे बनाये जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का आना जाना लगा रहे। जब पिछले दिनों के अन्तर्गत बाढ़ आ गई महोदया, तो बाढ़ आने के बाद ये जो नानकसर से ले करके ट्रोनिका सीटी तक एलएफ बंध बना हुआ था उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से पानी उसके ऊपर से क्रॉस करने लगा। जिसकी वजह से नानकसर और सोनिया विहार

थाने के पास दो जगह एलएफ बंध को नुकसान पहुंचा और जिसकी वजह से वो जलमग्न हो सकता था लेकिन बड़ी सतर्कता के साथ हमने और अधिकारियों द्वारा नानकसर और सोनिया विहार थाने के पास वो दोनों को पूरी तरह से उसमें कट्‌टे वगैरह लगा दिये गए जिसकी वजह से वो पानी अंदर कालोनियों में नहीं गया। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि यदि इस बंध को या बंध की ऊंचाई एक मीटर हाईट नहीं की जाती है और इस एलएफ बंध को चौड़ा नहीं किया जा सकता है, करावल नगर के इर्द-गिर्द की कालोनियां तो पानी में जरूरी डूबेंगी ही लेकिन इसकी मार सीधा हिंडन एयरपोर्ट तक पहुंच सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बंध को तुरंत एक मीटर इसकी हाइट बढ़ा जी जाये और उसको चौड़ा कर दिया जाये जिससे पूरे क्षेत्र के अंदर ये पानी भरने से बच सके। ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि मैने मंत्री जी को टेलीफोन लगाया, वास्तव में उन्होंने गम्भीरता से उस विषय को समझा और तुरन्त अधिकारियों को कहा और वहां मेरे ख्याल से गए भी होंगे जो ये काम हुआ। यदि यही गम्भीरता इस पुश्ते को एक मीटर और हाइट कर देंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा। करावल नगर की जनता आपकी आभारी रहेगी। सधन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री महोदय का ध्यान अपनी घोंडा विधानसभा की अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो सीवर से सिल्ट निकलती है उस सिल्ट के निस्तारण की व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है और ये अधिकारियों के लिये भी बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। सिल्ट निकाली जाती है निकालकर के साइड में रख दिया जाता है और वो महीनों दिनों तक पड़ी रहती है उसके बाद धीरे-धीरे या तो छिज करके सड़क पर फैल जाती है या वापिस चली जाती है तो दिल्ली जल बोर्ड निस्तारण के लिये सिल्ट निस्तारण के लिये एक प्रोपर व्यवस्था गाइड लाइन करे ये मेरा एक तो मंत्री जी से निवेदन है। दूसरा मेरी यमुना विहार यूजीआर जो मेरी विधानसभा में आता है उससे अन्य विधानसभाओं को भी सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद को भी पानी जाता है उस यूजीआर से, उसकी साढ़े सात एमजीडी की कैपेसिटी है जबकि मिनिमम 11 से 12 के बीच में उसकी कैपेसिटी मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं निवदेन करूंगा कि जल मंत्री जी उस यूजीआर की कैपेसिटी बढ़ायें उसी क्षेत्र में उसी स्थान पर बढ़ सकती है। आप अगर इसमें करेंगे तो क्षेत्र की जनता आभारी रहेगी। इसी में पानी की आपूर्ति क्योंकि सीवर बहुत जाम रहते हैं, मेरी दो मेन सीवर लाइन हैं एक घोंडा से भजनपुरा मार्किट की दूसरा यमुना विहार की मेन लाइन है, दोनों मुख्य सीवर लाइन लगभग-लगभग जाम पड़ी हुई हैं और जिसके

कारण सीवर का पानी ओवरफ्लो होता है और वो फैल जाता है जिसके कारण जो शुद्ध पेयजल है उसमें उसकी मिक्सिंग हो जाती है वह भी एक बड़ा कारण है हमारी दो-तीन-चार विधानसभाओं में, उसमें गोपालरॉय जी की बाबरपुर भी है, रहमान जी की सीलमपुर भी है और हाजी युनूसजी की मुस्तफाबाद भी जाती है वो सब पानी मिक्स होकर के दुषित पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या है कि मेरे यहां जो सीवर लाइन है वो 30 से 35 साल पुरानी हो चुकी है, जर्जर हालत में है, जगह-जगह से पूरी तरह से धवस्त हो चुकी है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप हमारी विधानसभा की जो भी जर्जर हालत की सीवर लाइन है जो 30-30, 35-35 साल पुरानी हो चुकी हैं उस पर ध्यान दें, संज्ञान लें, अधिकारियों को निर्देश देकर उसको बजट करके उसकी बदलने की व्यवस्था पूरी तरह से की जाये और इस पर एक सार्थक चर्चा भी हो। मेरे को लगता है कि सत्ता पक्ष से भी बहुत से विधायक होंगे जिनको पानी की समस्या, सीवर की समस्या होंगी। एक दिन का विशेष सत्र अगर आप चर्चा के लिये इस पर बुलायेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का भला होगा। जिस प्रकार के हालात हैं उस हालात से हमें निबटने की दिल्ली के हित में जनहित में बेहद आवश्यकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्ष: राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आज मैं आपका, सदन का और सरकार का ध्यान Delhi SC/ST/OBC/Minority/Handicap Development Finance Corporation की जर्जर हालत की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, 1983 में जिस वक्त ये दिल्ली विधानसभा नहीं होती थी उस वक्त भारत सरकार ने डी.एस.एफ.डी.सी. का गठन किया था और इसी तरह के विभाग का गठन पूरे देश की राज्य सरकारों में भी हुआ है। उस वक्त केवल एससी/एसटी के लिये किया था बाद में उसमें Delhi SC/ST/OBC/Minority/Handicap इन कैटेगरिज़ को भी शामिल किया और लगभग दिल्ली की 90 परसेंट जनता इसमें कवर हुई लेकिन 1983 से 1997-98 तक दिल्ली की सरकार के द्वारा ग्रांट इन एड मिलती थी जिससे कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिल जाती थी और साथ ही साथ जब इसका गठन हुआ तो इसमें 100 करोड़ रुपया corpus fund देने का सरकार ने तय किया था जिसमें 51 परसेंट राज्य सरकार ने देना था, दिल्ली ने देना था और 49 परसेंट केन्द्र की सरकार ने देना था। उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया उस वक्त दिया गया जिसमें से 38 करोड़ 12 लाख रुपया दिल्ली सरकार ने और 11 करोड़ 86 लाख रुपया केन्द्र सरकार ने दिया लेकिन उसके बाद बाकी का जो 50 करोड़ मिलना था 51 परसेंट केन्द्र सरकार के द्वारा और 49 परसेंट दिल्ली की सरकार के द्वारा, बाद में ये बाकी का 50 करोड़ ना केन्द्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दी और ना ही दिल्ली की सरकार ने अपनी हिस्सेदारी

दी। बार-बार मांगने के बावजूद फाइल अफसरशाही घुमाती रहती है। मंत्रीगण चाहते हैं, कैबिनेट चाहती है कि वो पैसा मिल जाये लेकिन कभी भी वो फाइल सेक्रेटरिएट स्तर से और फाइनांस डिपार्टमेंट के स्तर से कभी आज तक क्लीयर नहीं हुई और हालात और खराब हुये पहले जो ये पैसा corpus fund जो एफडी में कराया गया था, एफडी में ब्याज की दर ज्यादा हुआ करती थी तो पैसा ब्याज से काफी मिल जाता था और इसके साथ-साथ जो डी.एस.एफ.डी.सी. की बिल्डिंग किराये पर उससे भी आमदनी होती थी। इससे क्या था कि सैलरी भी चली जाती थी और उसके बाद लोन भी चले जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि ब्याज की दर देश में कम होती चली गई तो एक तरफ ब्याज की दर कम हो गई, ऊपर से छठा और सातवां पे-कमीशन आया, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, अधिकारियों की सैलरी बढ़ी तो इस विभाग की इन्कम कम हो गई और 1997-98 के बाद जो ग्रांट इन एड मिलती थी जिससे सैलरी जाया करती थी, दिल्ली की सरकार ने, हमारी सरकार तो अब बनी है पहले ही 1997-98 के बाद सरकार ने उनको ग्रांट इन एड देना बंद कर दिया जबकि बाकी बहुत सारे बोर्ड हैं जिनको अभी भी ग्रांट इन एड सरकार देती है। हमारे डी.एस.एफ.डी.सी. के इस प्रस्ताव को एससी/एसटी/ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने काफी कोशिश की कि ये ग्रांट इन एड मिले लेकिन फाइनांस डिपार्टमेंट के द्वारा बार-बार उसमें ऑब्जेक्शन लगते रहे, लगते रहे और साल दर साल निकल गईं आज हालात इतने ज्यादा बुरे हो

गये। बदनामी सरकार की हो रही है जबकि फाइलें घुमती हैं अफसरशाही के बीच, अफसरशाही फाइल को क्लीयर करती नहीं है। फाइनांस डिपार्टमेंट एससी/एसटी/ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजता है, एससी/एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डी.एस.एफ.डी.सी. को भेजता है, डी.एस.एफ.डी.सी. Query reply करता है उसके बाद फिर फाइल डिपार्टमेंट में आती है, डिपार्टमेंट फिर फाइनांस में भेजता है और वो फिर से ऑब्जेक्शन लगते हैं। आज हालात ये है लगभग पिछले पांच महीनों से डी.एस.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है और साथ ही साथ दु:ख की बात ये है चूंकि जो 50 परसेंट जो बाकी का यानि 50 करोड़ मिलना था वो ना मिलने की वजह से डी.एस.एफ.डी.सी. के पास लोन देने के लिये भी पैसा नहीं है। जिस विभाग के माध्यम से छोटे-छोटे गरीब लोगों को SC/ST/OBC/ Minority/ Handicap इन लोगों को जो लोन मिल जाया करता था 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वो लोन मिलना बिल्कुल बंद हो गया है और विभाग लगभग खत्म होने के कगार पर है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, विशेष रूप से फाइनांस मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस समस्या का समाधान करायें। ये केवल डी.एस.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों की सैलरी का मामला नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ देश की दिल्ली की 90 परसेंट जो पोपुलेशन है जो SC/ST/OBC/ Minority और उसके साथ-साथ handicap उन सबको जो अपने

रोज़गार शुरू करने के साधन मिल जाया करते थे, जिसमें लोगों की बसें चलीं, टैक्सी चली उनको लोन मिल जाया करता था या छोटे-छोटे और बिज़नेस करने के लिये लोन मिल जाया करता था, आज वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट लगभग ठप्प है, पूरी तरह से कॉलैप्स हो गया है, बंद होने के कगार पर है। मैं माननीय फाइनांस मिनिस्टर साहब से और दिल्ली के..

माननीया अध्यक्षः हो गया।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करता हूं..

माननीया अध्यक्षः हो गया गौतम जी, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः कि आप फाइनांस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करायें और जो बाकी का पैसा जो corpus जो उनको देना था वो भी सरकार से देने का कष्ट करें, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्षा जी। मैं अपनी विधानसभा का मसला उठा रहा हूंजो शायद मेरी विधानसभा से नहीं बल्कि बाकी विधानसभाओं से भी concerned है। पिछले एक डेढ़ साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप्प पड़ा है कोई भी काम

नहीं हो पा रहा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी contaminated water पीने पर मजबूर हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग बीमार पड़ने शुरू हो गये खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे। जब भी अधिकारियों से बात हो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है और ये बात कहीं तक सही भी है। पीछे एस्टिमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े-बड़े अधिकारी आये, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है वो नैगेटिव में निल है तो कोई काम नहीं हो पा रहा है जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोटल भरकर लेकर आते हैं और वो बिल्कुल गटर का पानी है जो कोई ह्यूमनबिंग टच भी नहीं कर सकता, सूंघ भी नहीं सकता, ऐसा पानी पीने के लिये लोग मज़बूर हैं। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां वॉटर पाइप लाइन 30-30, 40-40 साल पुरानी हैं उनको रिप्लेस करना है। एस्टिमेट बन गये, वर्क आर्डर हो गया, एजेंसी एपाइंट हो गई लेकिन फंड्स नहीं हैं, काम शुरू नहीं हो पा रहा। बोरवेल sanctioned पड़े हैं, एजेंसीज हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि फंड्स नहीं है। 31.7 को इसी साल पिछले जो कान्ट्रैक्ट था इसका टेंकरों का वो खत्म हो गया। नये टेंकर इसलिये हायर नहीं हो पा रहे कि फंड्स नहीं है। तो लोग जायें तो जायें कहां अध्यक्षा जी और जवाब ये मिलता है की फाइनांस डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट रिलिज़ नहीं कर रहा। तो ये एक एसेन्शियल चीज़ है पानी जिसके बिना लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते।

लोग प्राइवेट टेंकरों से पानी रॉ-वॉटर खरीद रहे हैं जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि फाइनांस डिपार्टमेंट को इमीजेट्ली डायरेक्शन दी जायें कि वो फंड्स रिलीज़ करें ताकि लोगों का जीवन स्वस्थ रहे और लोग पोर्टेबल वॉटर जो है उनको मिल सके, नहीं तो अध्यक्ष जी ऐसी epidemic फैलनी वाली है जिसके लिये कौन जिम्मेदार होगा? फाइनांस डिपार्टमेंट तो हाथ खड़े कर देगा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन जल बोर्ड की भी मजबूरी है कि बिना फंड्स के कोई काम नहीं हो पा रहा, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद उपाधयक्षा जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं पहले तो बिन्देश्वर पाठक जी जिनको लोग सफलभ के नाम से भी जानते थे जो सफलभ शौचालय के संस्थापक थे उनकी कल मृत्यु हो गई उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने समझा कि जैसे पानी और हवा आदमी की बेसिक जरूरत है उसी तरीके से शौचालय भी उन चीज़ों में आता है जहां पर अगर ना हो तो कितना सम्मान को ध क्का लग सकता है। इस बात को उन्होंने समझा और मुझे लगता है कि बिन्देश्वर पाठक जी की उस बात को अगर किसी ने आगे बढ़ाया और जरूरी समझा तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली में सबसे ज्यादा शौचालय बनवाये जो पूरी देश में कहीं

नहीं होंगे और उनको प्रयोग में लाने को भी मुफ्त कर दिया। सोच वही थी कि अगर आप साफ-सफाई वाली जगहों पर शौचालय नहीं जायेंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं साथ में एक खासतौर से महिला के सम्मान को एक धक्का लगता है, एक डर का माहौल पैदा होता है और उसके आस-पास में रहने वाले सभी लोग परेशान होते हैं, चाहें वो कोठी के हों, बंगले के हों, झुग्गी वाले तो परेशान थे ही लेकिन आज बड़े दु:ख के साथ में मुझे ये बताना पड़ रहा है की जितने हमारे साथी यहां बैठे हैं उन सभी के यहां पर ये हालात हैं कि शौचालय एक तो बने बनाये कई जगह से तोड़ ही दिये गये क्योंकि नई-नई स्कीम लेकर आते हैं एल.जी. साहब उन्होंने उनको तोड़ा। बार-बार जब आवाज उठाई गई मैंने यहां एक विधानसभा में जब आवाज उठाई तो कम से कम इतनी मेहरबानी मुझ पर हो गई कि मुझे दोबारा जगह दे दी गईं जो शौचालय माननीय केजरीवाल जी ने 2016 में वहां बनवाये थे उन्हें तोड़ दिया गया, वहां एक बाग बनाना चाहते थे एल.जी. साहब लेकिन वो दोबारा जगह दे दी गई कि ठीक है आप बना लो। तो तोड़े ही क्यों थे भाई? लेकिन चलिये हमारी इतनी दरख्वास्त के बाद में उन्होंने दोबारा जगह दी। डूसिब की सीईओ मैडम ने मुझे कहा वो सितम्बर तक बन जायेंगे लेकिन अब उनका कहना है कि वर्क आर्डर की स्थिति है तो और दो-चार महीने लग जायेंगे, चलिये लेकिन जो बने हुये हैं उनकी भी स्थिति इतनी खराब है कोई सफाई नहीं है, वहां डिब्बे नहीं मिलते, वहां कोई साबुन नहीं मिलता

और बड़ी दयनीय स्थिति है। एक मुर्गा मार्किट मेरी यहां पर एक जगह है वजीरपुर गांव में उसमें एक शौचालय है जो गिरा पड़ा है, कोरोना टाइम में गिरा था आज तक उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, कहते हैं पैसा नहीं है। अब बताईये कि प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलायेंगे, कहां जायेंगे लोग। दिल्ली में खेत भी नहीं हैं कम से कम मेरी विधानसभा में तो नहीं है कि कोई जाकर वहां कर ले। तो कहां जायेंगे, इतनी घनी आबादी गांव की, आस-पास में कोठियां हैं वो कहां जायेंगे, आप समझिये कैसी स्थिति होगी। यही हाल जेलरवाला बाग में है जहां उन्होंने तोड़े इन्डस्ट्रियल एरिया, जे.जे. कॉलोनी और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत साथियों से बात करता रहता हूं कि दिल्ली में हर जगह शौचालयों का बुरा हाल है, बार-बार कहे जाते हैं हम नये टेंडर कर रहे हैं, कर भी दिये चार-पांच बार जो सफाई करने वाले आते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये आपसे एक प्रार्थना है कि इस विधानसभा की अथॉन्टिसिटी को बढ़ाने के लिये एक तो अधिकारी होते ही नहीं हैं, आप देखिये जब 280 में हम बोल रहे हैं यहां विपक्ष के साथियों ने दो सवाल रखे, किसलिये रखे इन्होंने? यहां कोई है ही नहीं, यहां होने तो चाहियें अधिकारी। अगर हमने कोई बात कही है, डूसिब से कोई आया हो तो कुछ संज्ञान लें, ये तो मज़ाक बनकर रह जायेगा। तो ये इनके ऊपर दबाव रहना चाहिये कि जब विधानसभा लगे तो जैसे हम घर से भागते हैं जबकि हम सबके घरों पर 11.00 बजे सभा लगने का मतलब है सदन लगने

का मतलब है कि लोग घर पर आते हैं लेकिन यहां सदन में कोई अधिकारी ही नहीं है तो आप इन्हें बुलायें, जो सवाल हम उठा रहे हैं उनका जवाब आये। ये लगातार मैं यहां चिट्ठियां लिखे जा रहा हूं इसका फायदा क्या है, बताईये? पांच-पांच, छः-छः चिट्ठियां लिख लीं, रोज़ लिखे जा रहे हैं इसका फायदा कुछ नहीं है। आप अधिकारियों को यहां बुलायें, उनकी जिम्मेदारी तय हो, वो डेट दें और वहां उस डेट के हिसाब से काम हो, आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अनिल कुमार बाजपेयी जी।..आपका विषय आ गया, व्यवस्था मिल जायेगी, बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे 280 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के दो मंत्री कानून मंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे गांधी नगर में एशिया की सबसे बड़ी गांधी नगर में रेडीमेड की मार्किट है यहां पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण यहां के निवासियों को कई-कई घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की छुट्टी हो जाती है, अगर छुट्टी साढ़े बारह बजे स्कूल की हो गई और वहां से उनको अपने घर पहुंचने में घंटों का समय लगता है। इस बारे में मैंने यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ कई बार

मीटिंग की लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं की दिल्ली माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक आदेश के अंदर दिल्ली की 16 मार्किट हैं जिनमें वन वे ट्रैफिक को शुरू करने का आदेश है जिसमें गांधी नगर मार्किट भी एक है लेकिन आज तक दिल्ली हाई कोर्ट के उस आर्डर को गांधी नगर में लागू नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी की एक रोड़ है, मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया है कि जहां से गांधी नगर स्टार्ट होता है महावीर स्वामी पाक्र से गांधी नगर मेन रोड़ के बगल में और जो पुश्ता की रोड़ है उसके बीच में एक नीचे रोड़ है वो रोड़ पीडब्ल्यूडी की रोड़ है और उस पूरी पीडब्ल्यूडी की रोड़ पर जो भूमाफिया हैं और असामाजिक तत्व हैं उन्होंने पूरा का पूरा रोड़ कब्जा कर लिया, करोड़ों रुपये की दुकानें बेच दीं। आज भी अगर कोई सरकारी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी स्तर पर अगर इसकी जांच कराई जाये तो वो रोड़ सबके सामने आपको दिखेगा कि यहां पर ये रोड़ है और अगर वो रोड़ खुल जायेगा तो मैं समझता हूं गांधी नगर में एक बड़ी जाम की समस्या से हम लोगों को उससे छुटकारा मिल सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार।

माननीया अध्यक्षः महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्षा जी, जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया जो मैं आज विषय उठा रहा हूं ये मेरी विधानसभा के साथ-साथ ये पूरी दिल्ली की भी समस्या है। बहुत से बुजुर्ग बच्चों के साथ में नहीं रह पाते या बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं। उन बुजुर्गों को अपना पेट पालने के लिये, रहने के लिये कुछ ना कुछ खर्चे की जरूरत होती है जिसके लिये सरकार ने एक पेंशन का प्रावधान बनाया हुआ है और पेंशन उन बुजुर्गों के लिये काफी समय से खुल नहीं रही है। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी को कि दिल्ली के अंदर उन बुजुर्गों के रहने के लिये, उनके खर्चे के लिये जेब खर्चे के लिये वो पेंशन जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लागू की जाये। उनको उनका हक दिया जाये ये मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, धन्यवाद अध्यक्षा जी।

माननीया अध्यक्षः गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, अध्यक्षा महोदय मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान पालम विधानसभा, उत्तम नगर विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला विधानसभा और कुछ नज़फगढ़ का भी हिस्सा है जहां से लोग जो हैं पालम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। द्वारका के अंदर जब एन्ट्री होती है तो पालम फ्लाईओवर को क्रास करने में हर रोज़ एक घंटा लगता है मात्र दो किलोमीटर का जो रास्ता है, आज सुबह मैं आया हूं 9.00 बजे घर से निकला हूं आप यकीन नहीं करेंगे नेट एक घंटा पालम

फ्लाईओवर को क्रास करने में लग गया और ये हमारी चार विधानसभा इससे परेशान हैं। भावना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं. .. बहुत सारी विधानसभायें परेशान हैं और दूसरा वहां पर अभी 15 सौ बैड का अस्पताल जो है वो चालू हो गया है दिल्ली सरकार का द्वारका के अंदर, तो लोग चारों तरफ से जायेंगे। तो मेरा निवेदन है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी यहां बैठे हैं कि आप एक दिन का वहां पर दौरा रखें, सारे सीनियर ऑफिसर्स को पीडब्ल्यूडी के जितने अधिकारी हैं उनको लेकर आयें, इसका समाधान हो सकता है लेकिन इसके लिये हमें वहां विजिट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर टनल बनेगी, जब तक टनल नहीं बनेगी इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि उस फ्लाईओवर को ही गलत बनाया गया है क्योंकि जो रोड़ जाता है फ्लाईओवर की तरफ वो चोड़ा है और आगे जाकर के फ्लाईओवर भीड़ा हो गया जिसकी वजह से रोज़ाना वहां पर जाम लगता है। मेरा निवेदन है क्योंकि द्वारका की सोसाएटिज़ में या कहीं पर भी मीटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा पिछले 8 साल में 9 साल में अगर किसी ने किसी मुद्दे को उठाया है जनता ने उन्होंने कहा भई ये समाधान दे दो, रोज़ाना एक-एक घंटा खून के आंसू रोते हैं वहां खड़े होकर, इतना बुरा हाल है वहां। तो मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाये और जो अभी गुप्ता जी ने बात कही ये हर विधायक की पीड़ा है। 280 सिर्फ कहने के लिये रह गया है, बोलने के लिये रह गया है, इसका कोई फायदा नहीं है। शर्म आनी चाहिये अधिकारियों को कि ये सदन में नहीं हैं, सारे विधायक यहां बैठे हैं, आप बैठे हो, विपक्ष

बैठा है, हम बोले जा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है। ना जाने इस तरह के कितने सारे मुद्दे इस सदन के अंदर सभी विधायक साथियों ने उठाये, कोई आज तक चिट्ठी नहीं आई रिप्लाई में, क्या फायदा ऐसे 280 का। हम आकर अपनी पीड़ा रो लेते हैं लेकिन एक लिखित में नहीं आती जबकि अध्यक्षा महोदय, अध्यक्ष महोदय ने ये हमें आश्वासन दिया था कि आपको सबको 280 का रिटन में जवाब आयेगा, कोई जवाब नहीं आता। इसलिये आप इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लें और अधिकारियों को अगले सेशन में जरूर बुलाया जाये, उनको यहां बैठाया जाये ताकि वो भी इस बात को सुनें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, मैं भी आज एक मुद्दा लेकर जो आया हूं आपके बीच में अपनी विधानसभा का है, द्वारका का भी है और उत्तम नगर का भी है। यह पंखा रोड़ और उत्तम नगर की समस्या है ये। पंखा रोड़ जो हमारी डेसू कॉलोनी से शुरू होकर उत्तम नगर तक जाती है इस रोड़ के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो एमसीडी ने 2014-15 में पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया था। इस फ्लाईओवर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और ये इसके स्लैब टूट-टूटकर गिर रहे हैं नीचे, पीडब्ल्यूडी इस पर कुछ नहीं कर रही। अभी इन्होंने पेंट करने की बात की तो मैंने उनसे कहा कि आप पेंट इसमें एक खूबसूरत पेंट करिये, ये काला सा पेंट ना करें क्योंकि जनकपुरी की जनता

की डिमांड है ये खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और लीपापोती करके पेमेंट जो उसका टेंडर था उससे भी ज्यादा अमांउट देकर उसे कम्प्लीट कर दिया। हमारी इस पंखा रोड़ की स्थिति इसलिये ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि यहां पर बसों का अड्डा बन गया है। मैं मंत्री जी बैठे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि उत्तम नगर टर्मिनल के पास पंखा रोड़ के ऊपर बहुत सारी बसें खड़ी हो जाती हैं जिससे एरिया बहुत मतलब जाने-आने का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है जिसके कारण बसें, निकल नहीं सकते लोग, साथ ही इसके चारों, इसी रोड़ के ऊपर वर्कशॉप खुल गई हैं और इसके साथ एक साइकिल पथ है जिसके ऊपर लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, कई जगह पर तो है ही नहीं, उस जगह पर रात के समय में गलत धंधे शुरू हो जाते हैं इसकी जानकारी एसएचओ को भी है लेकिन एसएचओ वो कुछ करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप जानते हो पुलिस हर जगह सैटल कर लेती है। इसी के ऊपर कुछ मीट बेचने वालों की शाम में दुकानें लग जाती हैं, वहां खुले आम शराब परोसी जाती है और पुलिस को अपना जो महीना है वो मिलता रहता है इसलिये वो रोकती नहीं है। यही कारण है कि ये पूरी रोड़ जो है हमेशा जाम रहती है। इसके बाद उत्तम नगर टर्मिनल जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस टर्मिनल के ऊपर जो वहां पर बैटरी रिक्शे लगे हुये हैं, वहां पर एमसीडी के द्वारा ठेले लगाये जाते हैं क्योंकि एमसीडी पैसे वसूलती है, हटाती नहीं है तो ये स्थिति हो जाती है कि उस रोड से क्रॉस करने वालों को उत्तम नगर टर्मिनल पर

लगभग एक एक घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है।

नजफगढ़ रोड की तो और भी बुरी हालत है कि दोनों रोड के किनारे पर इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई हटाने वाला नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं वहां पर, लेकिन वे कुछ नहीं करते। उन्होंने अपने वहां बंदे रखे हुए है, वो लाठी लेकर हांकते रहते हैं, सबसे पैसे वसूलते रहते हैं, ये स्थिति है वहां की।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि आप इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई कराई जा सके, डिपार्टमेंट को लिखकर भेजिए, उनको बुलाइये ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो, ये जाम से मुक्ति मिले, हमारी पीडब्ल्युडी मंत्री जी बैठी हैं और ये स्थिति यहां की इतनी बुरी हालत में हैं और तो और मेट्रो ने जो जगह ले ली उसकी साथ में फुटपाथ के साथ, उसके अंदर उन्होंने शराब की दुकान को दे दिया और बिल्कुल रोड के ऊपर शराब बिकना शुरू हो गयी। जब कम से कम कुछ एरिया तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग आ जा सके, उस गांव में। रोड के पास सीधी दुकान शुरू हो जाती है। तो ये उत्तम नगर टर्मिनल के हालत सबसे ज्यादा खराब है। इससे हम भी प्रभावित हैं, हमारा तिलक नगर भी प्रभावित है और उत्तम नगर विधान सभा भी प्रभावित है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली के शहरीकृत गांव में दाखिल-खारिज म्यूटेशन रोकी गयी है, जिससे ग्रामीण आंचल के लोगो को काफी परेशानी हो रही है। परिवार बड़े होते जा रहे हैं, बुजुर्गों की प्रोपर्टी उनके बच्चों के नाम पर दाखिल-खारिज नहीं हो पा रही है। अगर किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई या किसी के ईलाज या घर के किसी भी जरूरी खर्च के लिए अगर पैसों की जरूरत हो तो अपनी जमीन के आधार पर दाखिल-खारिज न होने के कारण लोन आदमी नहीं ले सकते हैं।

कृषि भूमि पर अपनी मर्जी से फार्मिंग के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं। अपनी ही जमीन पर डेयरी उद्योग, फार्मिंग उद्योग, कृषि पर्यटन के लिए भी या किसी तरह के निवेश के लिए भी ये लोग कोई कागज प्रदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूं इसलिए अक्सर मुझे लोग बाहरी दिल्ली से मदद की गुहार करते हैं जो आज मैं आप सबके समक्ष रख रही हूं। कृपया इसपर उचित संज्ञान लिजिए। इसके अतिरिक्त, किसान औरपर्यावरण के हित के लिए किसानों को अपने खेतों के लिए सोलर उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीया अध्यक्षः रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता-प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्षा महोदया, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री यहां उपस्थित हैं। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो पूरी तरह से चरमरा

गया है। उसे दुरूस्त करने की आवश्यकता है। आज डीटीसी के पास लगभग 3992 बसें हैं, जिनमें से 3504 जो बसे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया वे आउट डेटेड हो गयी हैं। आए दिन डीटीसी की बसों में आग लग रही है, ब्रेक डाऊन हो जाता है, दिल्ली के ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसपर संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिये हैं। मैं इस मौके पर जरूर सरकार को ये जानकारी देना चाहता हूं कि हम पिछले आठ-साढ़े आठ सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस नहीं खरीद पाए और उसके बावजूद भी डीटीसी लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि डीटीसी के ऊपर इस सदन में चर्चा भी हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, 2013 में भी और 2015 में भी, 2020 में भी दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डीटीसी में जितने भी कॉन्टेक्ट वर्कर्स हैं, उनको रेगुलराइज करने का वायदा भी किया था, लेकिन पिछले आठ-साढ़े आठ सालों में कारण क्या रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में जो कॉन्टेक्ट वर्कर्स डीटीसी में काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया गया। ये शिकायत भी निरंतर आती रहती है कि लगभग 21 हजार डीटीसी के जो कर्मचारी रिटायर हो गये हैं, उनको समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। डीटीसी के कर्मचारियों को उसके लिए धरना-प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। उसके बाद सरकार ने चार-पांच महीने की पेंशन जारी की और जुलाई महीने की पेंशन

अभी तक सरकार की ओर से जो बेचारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनके लिए जारी नहीं की गयी है। तो मैं आपके माध्यम से क्योंकि ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि डीटीसी के लिए सीएनजी की बसें तुरंत खरीदी जाए और जो भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं डीटीसी के उनको वायदे के मुताबिक नियमित किया जाए और जो लोग रिटायर हो गए हैं, उनको समय पर पेंशन दी जाए, यह मांग मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अब श्रीमती आतिशी, माननीय ऊर्जा मंत्री कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक 3 में दर्शाये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।

माननीया ऊर्जा मंत्री (श्रीमती आतिशी मार्लीना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक 3 में दर्शाये गये दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।

3. i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022-23/7460/26 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[1]

---

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23189 पर उपलब्ध।

ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधान) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूसचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022-23/7460/27 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[2]

iii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र, फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधान) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूसचना संख्या ए. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022-23/7460/28 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[3]

iv) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या ए. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022-23/7460/172 दिनांक 26 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[4]

v) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2020-21 हेतु 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)[5]

vi) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी)[6]

---

[2]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23190 पर उपलब्ध।

[3]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23191 पर उपलब्ध।

[4]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23192 पर उपलब्ध।

[5]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23193 पर उपलब्ध।

[6]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23194 पर उपलब्ध।

माननीया अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम 54 के तहत श्री दिनेश मोहनिया जी, माननीय सदस्य, वित्त विभाग, रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा फंड जारी न करने से दिल्ली जल बोर्ड के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण (नियम 54)

श्री दिनेश मोहनियाः माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय जल मंत्री जी का ध्यान जो अभी जल बोर्ड की स्थिति है इसके ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं और मेरे को लगता है कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि जो इस टाइम जल बोर्ड का जो काम है, वो पूरी तरह ठप्प हो चुका है। न केवल ये स्थिति है कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट्स वो तो बंद है ही हैं साथ ही साथ जो डेली के काम हैं, मेंटेनेंस के काम हैं, वो भी आज बंद हो गया। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मेरे सभी साथी विधायक सहमत होंगे। स्थिति ये है कि आज बोरिंग हो जाए, उसमें मोटर नहीं डाल पा रहे हैं, कोई कंप्लेंट आ जाए सीवर चैंज नहीं करा पा रहे हैं, टेंकर नहीं चल पा रहे हैं। स्थिति ये हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तो इतना भयंकर संकट हो गया कि टेंकर वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास डीजल के पैसे नहीं है, स्थिति इतनी खराब हो गयी है और सबकुछ देखने के बाद ये लगता है कि अभी पिछले दिनों बजट का भी सारी कॉपी देखी, बजट जितना जल बोर्ड को मिला हुआ है, जितन जितना सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि बजट की कमी

नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, इसके पीछे षडयंत्र हो रहा है और ये षडयंत्र कर कौन रहा है। षडयंत्र कर रहा है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेट्री है, वो। मैंने कई अफसरों से बात की कि भाई कारण क्या है, जब पैसा है, बजट है और इसी सदन ने माननीय सदन ने जब बजट पास कर रखा है इन चीजों के लेकर, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। अब होता क्या है कि यहां से कोई प्रोजेक्ट जाता है, कोई चीज जाती है फाइल, यहां से ग्रांट मांगा जाता है, यहां से लोन माना जाता है क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा से जल बोर्ड के अंदर थी। हमेशा क्वार्टली पैसा सरकार की तरफ से आता है जल बोर्ड को, जल बोर्ड उससे काम करता है, लेकिन पिछले कम से कम 7-8 महीनों से ये स्थिति है कि जैसे यहां से कोई फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई न कोई क्वेरी लगा देता है, कोई न कोई राइडर लगा देता है, कोई न कोई जानकारी ऐसी मांग लेता है, जिससे टाइम डिले हो और वो फाइल फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक ऐसे चलती रहती है और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं डिले हों। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि मैं कई विधायकों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं जी आफिस में बैठना मुश्किल हो गया। आफिस में हमेशा भीड़ इतनी आ जाती है कि वो पानी, पानी क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, जिसका कोई समाधान नहीं है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं हैं। आपको लोगों को देना ही पड़ेगा, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गयी है और इसकी सारी

जिम्मेवारी जो है कहीं न कहीं वो फाइनेंस सेक्रेट्री की, हमारे माननीय एलजी साहब की है क्योंकि जो पूरे सिस्टम पर एक तरह से कुंडली मारकर बैठ गए हैं। अधिकार तो सारे उनके पास है, जिम्मेवारी कोई नहीं है। जिम्मेवारी सारी इन विधायकों की, सारे मंत्रियों की, लेकिन जो सारे अधिकार हैं, वो एलजी साहब के पास हैं और एलजी साहब और जो फाइनेंस सेक्रेट्री हैं मुझे लगता है ये तो केवल छोटे-छोटे मोहरें हैं, ये डायरेक्ट कहीं और से हो रहे हैं क्योंकि इनका अपना तो कुछ लेना देना नहीं हैं, लेकिन ये पूरा जो षडयंत्र है, वो इसलिए है कि किसी न किसी तरह से ये सरकार के जो अच्छे काम पिछले आठ-नौ सालों में हुए हैं, जो पिछले आठ-नौ सालों में सरकार ने जो क्रेडिब्लिटी कमाई है, जो लोगों का प्यार पाया है, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को खत्म करने की साजिश है ये और ये दिखाता है कि ये जो छोटा सा एक राज्य है, छोटा सा दिल्ली ये प्रदेश है जिसको कहते हैं कि जी छोटा सा प्रदेश, छोटा सा मुख्यमंत्री, लेकिन उसका डर इतना बड़ा है कि यहां तक कि प्रधानमंत्री तक डर रहे हैं इस चीज से। उन्हें डर इस बात का है कि जिस तरीके के काम दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरीके की प्रसिद्धी, जिस तरीके का प्यार दिल्ली के लोग दे रहे हैं, कहीं ये पूरे देश में न मिलने लगे। देश के लोग इस मॉडल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये रोज रोज ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि जिससे कहीं न कहीं ये सारे के सारे काम रूक जाएं।

आज स्थिति ये है कि जब आप बजट की बात करें तो पूरा बजट की कॉपी मैंने निकाली जल बोर्ड की कि पूरे बजट में क्या स्थिति है, तो पूरे के पूरे बजट में कहीं पे भी ये स्थिति नहीं लगती कि पैसे नहीं हैं या कहीं पर ये स्थिति नहीं दिखती कि किसी हैड में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेट्री हैं, वो ऊपर से जैसा आदेश उनको होता है, उस आदेश के माध्यम से वो काम करते हैं। छोटी-छोटी चीजों पर ओब्जेक्शन लगाते हैं, छोटी-छोटी चीजों पर राइडर लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब इस सम्माननीय सदन ने एक बजट पास कर दिया आपके लिए और जल बोर्ड को ये बता दिया कि आप इस बजट से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर काम में मीनमेख निकालना, हर फाइल पर कुछ न कुछ लिखना और हर फाइल को रोकने की साजिश करना, मुझे लगता है इस दिल्ली की जनता से धोखा है, दिल्ली की जनता को एक तरह से षडयंत्र है इनके खिलाफ और ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि पिछले तीन बार से भारतीय जनता पार्टी पूरा कोशिश करने बाद भी, पूरा जोर लगाने के बाद भी और घर घर पर्चे बांटने के वाबजूद भी केवल 3 सीटें जीत पाई, केवल 8 सीटें जीत पाईं। अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस सरकार को जोकि इतनी लोकप्रिय सरकार है और ऐतिहासिक बहुमत इसके पास है, उसको कहीं न कहीं डिफेम किया जाए, उसको बदनाम किया जाए जिससे कि इनको राजनीतिक लाभ हो। लेकिन ये जो दिल्ली की जनता ने

आम आदमी पार्टी को, अरविन्द केजरीवाल को जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, ये उससे परेशान हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का षडयंत्र हो रहा है, आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली की जनता जवाब देगी कि जिस तरीके से आप रोक रहे हैं काम, ये पूरी तरीके से गलत हैं। मुझे लगता है कि महाभारत में भी कहा है। महाभारत का एक किस्सा मुझे याद आता है जब पांडवों ने केवल केवल यह कहा था कि दे दिजिए केवल पांच ग्राम और रखिये अपनी भूमि तमाम्। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम केवल दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए काम करने की स्थिति में हैं लेकिन उसके वाबजूद भी ये जो केन्द्र सरकार है, जो मोदी जी हैं, वो ये कहते हैं हम कुछ नहीं देने वाले, हम सारे के सारे जो अधिकार हैं, उसपर कब्जा कर लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी जैसा पहले कहते थे कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन आज ये स्थिति है न खुद कुछ करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे और पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करके रखा हुआ है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से उनको संदेश है कि इस जनतंत्र में इस लोकतंत्र में जो असली मालिक है, वो जनता है और जनता तय करेगी कि इस दिल्ली को कौन चलाएगा, इस देश को कौन चलाएगा और जिस तरीके की स्थितियां लग रहीं हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जनता इसका भरपूर जवाब देगी और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल

और मजबूती के साथ उठेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मुद्दे पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाश जारवालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जल बोर्ड के विषय पर बोलने का मौका दिया। आज जल बोर्ड की स्थिति पूरे दिल्ली में किसी भी माननीय विधायक के सामने दिख रही होगी कि केन्द्र में बैठी सरकार ने क्या हालात दिल्ली में बना दिये हैं।

मैं अपनी विधान सभा की बात करता हूं अध्यक्षा जी। मेरे यहां तीन साल पहले पानी की लाईन डली थी। आज हम उसे चालू नहीं करा पा रहे हैं। कारण है जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है। सीवर के जो काम चल रहे हैं, उनमें पैसे नहीं हैं, उन कामों को रोक दिया गया है। एक काम ब्लैकलिस्ट हो गया था, उसका टेंडर भी हो गया, वो अवार्ड के लिए रूका हुआ था क्योंकि पैसे नहीं है। छोटे-छोटे काम आपकी सीवर की लाइनें साफ कराने के लिए, जल बोर्ड के पास लेबर के लिए भी पैसे नहीं है। ये हालात पूरे दिल्ली के हैं, हर विधान सभा में हो रखे हैं। सब परेशान हैं कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। नौ साल में कभी भी जल बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जल बोर्ड में पैसा न हो, कभी पैसे की कमी नहीं आई, मगर अब क्या हालात बन रहे हैं कि जल बोर्ड में पैसा नहीं हैं।

मैं मंत्री जी मिला, कहते हैं पैसे तो बहुत हैं, मगर फाइनेंस सेक्रेट्री उसे कोई न कोई ओब्जेक्शन लगाकर रोक देते हैं। अभी गर्मियों में पानी के टेंकरों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं और हम पब्लिक को क्या समझाएं कि भाई केन्द्र में बैठी मोदी सरकार एलजी के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से ये दिल्ली की सत्ता को चलाना चाहती है और दिल्ली के तमाम् कामों को रोक रही है। मतलब पानी तो ऐसी चीज है, मूलभूत चीज है। किसी के घर अगर पानी न हों तो कैसे दफ्तर जाएं और ये हाल इनका भी होगा, भाजपा के साथियों का भी क्योंकि बजट इनके घर भी नहीं होगा तो मेरा ये कहना है कि जो फाइनेंस सेक्रेट्री इस तरह का दिल्ली के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ बदला ले रहे हैं। अमानत भाई कह रहे हैं, नाम बताओ उनका खुला। अमानत भाई हम वैसे ही पहले से बदनाम हैं, पहले ही झूठे मुकदमें लगे हुए हैं। मैं तो अध्यक्षा महोदय, आपसे यही कहूंगा मंत्री जी अगर थक गएं तो हम दोनों भाईयों को भेज दीजिए या तो काम हो जाएगा या फिर बजट आ ही जाएगा कहीं न कहीं। पहले से झूठे मुकदमे लगे हैं हमारे ऊपर तो, मगर दिल्ली का कोई काम नहीं रूकना चाहिए। ये जो अफसरशाही चला रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली चला रहे हैं, जिस तरह दिल्ली की जनता के कामों को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, अब इसे रूकना चाहिए, इतनी इंसानियत इनमें हो। अब तो जनता कभी कभार ये भी कह देती है कि आप पानी

नहीं दे पा रहे हो तो हमें जहर दे दो। तो मैं भाजपा के साथियों को कहूंगा कि हमें दे दो जहर, हम फेस करते हैं। हमें दे दो, डेली, डेली ये कलेश खत्म हो जाएगा। आप तो अध्यक्ष महोदया जी, आज दिल्ली में ये हालात हैं जल बोर्ड में पैसा बहुत है, 70 हजार करोड़ का बजट है हमारी सरकार का, मगर सारा का सारा बजट इन्होंने रोक दिया।

डूसिब में भी पैसा नहीं हैं। एक साथी कह रहे थे शौचालय साफ करने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा। आप ये लगा लिजिए पेंशन तक इन्होंने रोक दी। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों की, विधावाओं की पेंशन नहीं आ रही, एक शेयर जो केन्द्र सरकार से दिल्ली सरकार को आता था वो उन्होंने बंद कर दिया। 10 हजार करोड़ रुपया देना बंद कर दिया। ये हालात दिल्ली के इन्होंने बना दिये हैं तो मेरा आपसे निवेदन है अगर उन अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए, जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं छोटी-छोटी चीजों पर ओब्जेक्शन लगा रहे हैं और अगर आप नहीं कर सकती तो हम तो वैसे ही बदनाम हैं मुकद्मों से, आप हमें भेज दीजिए हम बात कर लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली की जनता के काम नहीं रूकने चाहिए, एक मुकद्मा और सही, मगर झूठे मुकदमें हैं सारे। तो मेरा आपसे निवेदन है उनकी रिस्पोंसिबलिटी फिक्स होनी चाहिए, उन्हें बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि आप हर चीज पर आप छोटी-छोटी, लेबर के लिए, सीवर की जो डिसिल्टिंग करनी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं, ये हालात

दिल्ली के बना रहे हैं ये अफसर। अफसरशाही से देश नहीं चलता, अफसरशाही से दिल्ली नहीं चलेगी और अगर चलानी है तो ये विधान सभा भंग कर दिजिए। इतनी तकलीफ़ यहां के एक एक साथी को है आज, एक एक साथी एक एक विधान सभा का सदस्य परेशान है। आप एक जल बोर्ड से नहीं, तमाम् जितने विभाग हैं, उनसे परेशान हैं। मगर ये सारी की सारी विपत्ति, सारे के सारे एलजी के माध्यम से अफसर जो कर रहे हैं, दिल्ली में जो हालात बना रहे हैं, होगा नहीं इनसे, जितना चाह कर लें, कितनी कोशिश कर लें मगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती हैं, इन्हें फिर मौका देगी, फिर सरकार बनेगी और चौथी बार बनेगी। आप इस संदेह में न रहे कि आप कितने भी काम रोक लें, क्या आप केजरीवाल जी को रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे, मगर आप जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का जो नुकसान कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता भी समझ रही है। किस तरह से आप लोग अफसरों के माध्यम से दिल्ली के चुने हुए विधायकों का, उनकी जनता का बजट जो रोक रहे हैं, ये बिल्कुल जनता बर्दास्त नहीं करेगी। आपने मुझे इस सदन के माध्यम से बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्दः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, पूरे दिल्ली में जैसा कि अभी 280 में भी बहुत सारे साथियों ने दिल्ली

जल बोर्ड से संबंधित इश्यूज को उठाया। अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली के अंदर में ऐसी स्थिति दिल्ली जल बोर्ड में क्रिएट हो गयी है कि पानी के टेंकर के पैसे भी देने को नहीं हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं, लेबर के पैसे नहीं हैं और मैं जिस कंस्टिट्च्वेंसी से आता हूं वहां पर पूरे क्षेत्र के अंदर ही सीवर का काम चल रहा है एक साथ। एक साथ 5 हजार गलियां और सड़कों पर सीवर का काम चल रहा है और जाहिर सी बात है कि अन-अर्थोराइज कॉलोनी के अंदर में कुछ भी प्लान नहीं हैं तो उसकी वजह से जब खुदाई होती है तो कम्पैरेटिवली दूसरी जगह से वहां पर क्या होता है कि पानी की लाइन डेमेजेज ज्यादा होते हैं और पानी की लाइन एक बार डेमेज हो गई तो सोचिए अगर आपके पास उसको रिपेयर करने का पैसा न हो और साधन न हो तो एक तरफ तो हमारी गली खुदी हुई है, एक तरफ बरसात में वाटर लॉगिंग है, दूसरी तरफ जो पीने का पानी है वो भी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है और नालियों जैसा पानी आ रहा है। इतना कंटेमिनेटिड वाटर है, तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो घर चलाती हैं, हमारे भाई तो चलो सुबह टिफिन लेकर के फैक्ट्री पर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, लेकिन वो माताएं, बहने सोचिये कि चूल्हा-चौका, बच्चों का देख-भाल, देख-रेख करके, घर का देख-रेख करके मतलब रोज का ये हो गया है कि एमएलए आफिस पर एक एक कॉलोनी से दौ दौ सौ

महिलाएं आती हैं और हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि कहें तो कहें क्या क्योंकि कोई ऐसा टाइम लाइन नहीं है कि कब तक ठीक होगा और पानी से ज्यादा तो बुनियादी चीज कोई हो नहीं सकती है। हम लोग लगातार अपने मंत्री, सौरभ भारद्वाज जी को भी तंग करते हैं, हम अपने वाईस चैयरमेन सोमनाथ भारती जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं मिल पाता है, मतलब उनके पास भी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर, पूरी की पूरी सरकार को पंगू बनाने का षडयंत्र किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय।

एक सेक्रेट्री है फाइनेंस का पिंसिपल सेक्रेट्री, वो एक फाइल में 36 ओब्जेक्शन्स लगाता है। मतलब कैसे काम न हो, इसके लिए ये अफसर लोग काम करते हैं। अरे यूपीएससी ने देश में इतने बड़े बड़े आफिसर को तैयार किया है देश का इतना पैसा लगा करके, काम कराने के लिए तैयार किया हुआ है या काम रोकने के लिए तैयार किया है। ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर हम लोगों ने कोशिश किया जानने का कि ऐसी क्या मजबूरी है इन अफसरों की कि पानी जैसी मूलभूत चीजों को रोकना चाहते हैं तो क्रोनोलॉजी को समझिए। जब निगम के चुनाव थे दिल्ली में तब मोहल्ला क्लीनिक का दवाई रोक दिया, यही लोग थे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। जब निगम के चुनाव थे तो बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया, मैं बहुत सारे बुजुगो को जानता हूं अध्यक्ष जी, जोकि पूरी तरीके से पेंशन पर डिपेंडेंट हैं। दोनों वाइफ–हसबैंड का जो पेंशन आता है चार या पांच हजार

रुपया, उसी से पूरा परिवार मतलब उनका जो गुजर बसर है, उसी से चलता है। फ्री बिजली, फ्री पानी और पेंशन से ही चलता है ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का अगर छः महीना पेंशन न दिया जाए तो आप सोच सकते हैं इससे ज्यादा अमानवीय कुछ हो सकता है?

सीसीटीवी कैमरा के लिए किस तरीके से मंत्रियों को धरना देना पड़ा था लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर, आपने देखा। ये डीईआरसी का चैयरमेन का जो झमेला किया गया, क्यों किया गया। गरीबों का सब्सिडी कैसे रोका जाए, फ्री बिजली कैसे रोका जाए या पानी को रोकना चाहते हैं। ये नगर निगम को 15 साल में पंगु बना दिया, दिल्ली जल बोर्ड को पंगु लगभग बनाने के कगार पर हैं। तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिये कि सारा मैटर है पोलिटिकल। पोलिटिकल मैटर ये है कि बहुत बड़ा धावक है, उसको बोलते हैं यूसेन वोल्ट बहुत तेज दौड़ता है। पर ससफरा तेज बहुत तेज दौड़ता है, इसका पैर ही बांध दो, दौड़ेगा कैसे। मतलब आप जिससे कम्पीटिशन नहीं कर सकते हैं, उस वोल्ट का पैर बांध दो ताकि दौड़ न पाए। अरे ऐसे कोई रूकने वाला है। 2013 में हमने इनको हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में हराया अब 2024 भी हारेंगे, 25 भी हारेंगे जो इनकी करतूत है। अरे प्रधानमंत्री का काम ये रह गया कि एक अर्धा राज्य के मुख्यमंत्री को काम न करने दिया जाए, इसके लिए रोकना। अरे उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि

हमारा पड़ोसी चाईना है, 1990 तक हमारे बराबर था और आज वो हमसे तीन गुना आगे कैसे निकल गया, उसकी इकॉनोमी कैसे निकल गयी, आज वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कैसे बन गया। हमारे पड़ोस में देश सिंगापुर है उसके पास कोई natural resource नहीं है अध्यक्ष जी। कुछ भी नहीं है उसके पास बंजर था पेड़-पौधों भी नहीं थे। वो देश आज इतनी तरक्की कैसे कर गया। जापान जो ऑलमोस्ट राख में मिल गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में हीरोसीमा, नागासाकी के ऊपर में एटमबम गिराया गया। वो देश आज कहां खड़ा है। किस तरीके से बुलेट ट्रेन चला रहा है, किस तरीके से उसकी इकोनोमी है। किस तरीके से देश डेवलप कर गया। वो जर्मनी जिसको दोषी माना गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर में जिसके तीन टुकड़े कर दिये गए थे बर्ल्ड वॉर के बाद एक शहर के अंदर दीवार खड़ी कर दी गई थी उसको वॉल ऑफ बर्लिन बोलते हैं, वो देश तरक्की कर गया। वो डेवलप देश हो गया। ये छोटे-छोटे देश तरक्की कर रहे हैं। अफ्रीकन देश तरक्की कर रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली में दंगा करायेगा। हिन्दू-मुसलमान करेगा और उसके बाद क्या करेगा जानते हैं। एक योजना चला है। देखिए फेलड लोगों की निशानी क्या होती है। आप किसी पेट्रोल पंप पे जायेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री जी सिलेंडर लेके खड़े हैं, हर पेट्रोल पंप पर। मैं एक बार लेह लद्दाख चला गया, ऐसे ही यूं घूमने के लिए तो मैंने देखा वहां पर जो सबसे टोप पे साढ़े अठारह हजार फिट के ऊपर में एक

पेट्रोल पंप था, वहां पर भी प्रधानमंत्री जी सिलेंडर लेकर खड़े थे। हमें जानने की इच्छा हुई कि भईया ये इस योजना का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। क्या उज्जवला, उज्जवला, उज्जवला तो जब हमने जानने की कोशिश करी अध्यक्ष जी तो पता लगा कि प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि 12 करोड़ गरीबों को सिलेंडर दिये थे। अरे सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि 12 करोड़ सिलेंडर में से साढ़े 9 करोड़ लोगों ने रिफील तक नहीं कराया। ये तो वही वाली बात हो गयी कि कोई आपको ओडी कार दे दे और आपकी तनख्वाह 15 हजार रूपया है तो आप उसका तेल कैसे एफोर्ड करोगे और आप उसकी सर्विसिंग कैसे कराओगे, वो तो रद्दी हो जायेगा। ऐसे ही इनकी सिलेंडर योजना है। इन्होंने एक योजना जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत करते हैं ना और दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमेशा आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में लागू नहीं करता । दिल्ली में लागू नहीं करता। उस आयुष्मान भारत के बारे में सीएजी की रिपोर्ट जो इन्ही की सरकार लोकसभा में और पार्लियामेंट के अंदर में टेबल करती है वो कहता है कि एक नम्बर है वीआईपी नंबर पहले दिल्ली में लोग बहुत वीआईपी नंबर के लिए पैसा खर्च करते थे। 999999999999 करके दस बार उस नंबर पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं आयुष्मान भारत के लिए। ये फैलड लोग, फैलड योजना चलाते हैं। एक बार एक चाईना का राष्ट्रपति था माऊ तो वहां पर भुखमरी हो गयी। साढ़े चार करोड़ लोग मर गए।

माननीया अध्यक्षः विषय पर आ जाइये।

श्री ऋतुराज गोविन्दः विषय पर ही बोल रहा हूँ। साढ़े चार करोड़ लोग मर गया तो वो सारा चिड़िया मरवा दिया बोला कि फसल खराब कर देता है। इसी तरीके से इकोनमी नहीं सुधार रही थी तो ये लोग नोटबंदी कर दिये। इकोनमी और गर्त हो गया। तो कहने का मतलब है जिस चौथी पास राजा का स्टोरी इस सदन में बहुत बार सुनाया गया है ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते और जो कर रहा है इनके नेता ही कहते थे अन्तोदय करेंगे, अन्तोदय करेंगे। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कहां रहता है दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। कच्ची कॉलोनी में रहता है। उसके लिए कोई काम कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और आप सोचिये कि पीने का पानी से ज्यादा मूलभूत कोई चीज हो सकती है। पानी ये रोकेंगे, मोहल्ला क्लीनिक की दवाई ये रोकेंगे, गरीबों का पेंशन ये रोकेंगे, बिजली सब्सिडी कैसे खत्म होये उसका शड़यंत्र ये करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को, हम लोगों को क्यों चुना है? उनकी सेवा करने के लिए चुना है। आज अगर हमारी चर्चा न्यूयॉर्क टाईम्स में हो रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा हो रही है, स्कूल अस्तपताल की चर्चा हो रही है तो ये काम के बदौलत हो रहा है। तो सर जी काम करना सीखो। कोम्पटीशन करना है तो ये करो कि ये हम भी कैसे मोहल्ला क्लीनिक भाजपा के राज्यों में बना सकें। पीने का पानी रोक करके कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा और

बद्दुआयें मिलेंगी, मिल भी रही हैं और दिल्ली की जनता को बेबकूफ मत समझना, यहां के लोग बड़े समझदार हैं और समझदार नहीं होते तो 25 साल का वनवास भाजपा को अभी तक नहीं मिलता। समझदार हैं, 25 साल से आपको सत्ता से दूर रखा है, लेकिन जो आपके कर्म है ये 25 साल और आपको दूर रखेगा। इस सड़यंत्र करने के बजाये काम करने दो। दिल्ली की जनता की सेवा करो। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीया अध्यक्षः गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया आपने नियम-54 के तहत मुझे अपनी समस्या को उठाने का मौका दिया। दिल्ली जलबोर्ड की बहुत-सी ऐसी समस्यायें हैं क्योंकि लगभग-लगभग 80 प्रतिशत जो हमारी जे.जे. कॉलोनी का हिस्सा पड़ता है और विधान सभा मादीपुर है। इसमें पहले जो प्लॉट दिये गए थे 25 गज। 25 गज के बाद 15 गज। 15 गज के बाद साढ़े बारह गज। छोटे-छोटे मकान हैं और जनसंख्या के हिसाब से काफी ज्यादा हैं वहां लोग तो उन्होंने मल्टी स्टोरी जब बनाये हैं तो उनकी पानी की डिमांड बढ़ी है। पानी की डिमांड बढ़ गयी कि भई अब मेरे को तीन कनैक्शन चाहिए। फ्लोर वाइज कनैक्शन चाहिए। उनको जिस तरह से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ वहां काफी लोग मेरे पास आते हैं और ये बताते हैं कि भई हमारे यहां पानी नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री जून साहब ने भी बताया था

अभी और हमारे और सदस्यों ने बताया है कि भई वहां ऑफिस में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि जो समस्यायें लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गई हैं कि भई वहां लोगों को पानी नहीं है। हालांकि बोर का पानी भी उनके साथ मिलाया गया है। उसके बावजूद भी पानी की कमी पूरी नहीं हो पा रही है और जो अधिकारी हैं, जो बता रहे हैं कि भई मैंने जैसे अधिकारियों से बात की, एक्सीएन से बात की। एक्सीएन वहां से हटा दिया गया है और जो छोटे-मोटे जेईई बगैरा काम कर रहे हैं उनसे पूछा भई क्या मसला क्या है, के जी फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस नहीं है इतनी बड़ी मतलब जो है जैसे-जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, फाइनेंस सेक्रेट्री साहब उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे है तो किस तरह से काम होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक तरह से लगता है कि भई एक साजिश के तहत काम हो रहा है। भई एक साजिश है ये कि भई दिल्ली के कामों को रोका जाए। ऐसी विधान सभाओं को रोका जाए, क्योंकि आपको पता है जब चार मंजिल बैलिड कर दिया गया। 25 गज में चार मंजिल बना सकते हैं, 15 गज में चार मंजिल लोगों ने बना लिया है तो उनको कनैक्शन उसी हिसाब से चाहिए। पोपुलेशन उसी हिसाब से है। फिर भी उसके अंदर ये हम कोशिश करते हैं कि भई हम पानी तो बना नहीं सकते। हम जवाब क्या दें पब्लिक को। पब्लिक को क्या जवाब देंगे। ये ही जवाब देंगे कि भई पीछे हम बात करते हैं

अधिकारियों से बात करते हैं। अधिकारी सुनने को राजी नहीं हैं और अधिकारियों का ये हाल हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक नाला पार कर रहा था वहां नजफगढ़ ड्रेन है। इसपे काम चल रहा है, दिल्ली सरकार का एक प्रोजैक्ट है इसको नजफगढ़ ड्रेन को साफ करके इसमें पर्यटक स्थल बनाने का। उस नाले को पार करते वक्त नाले को बंद किया हुआ था। मैंने कहा भई ये इस पैसेज को बंद क्यों किया है। कहते हैं ये एलजी साहब आये हुए हैं। पुलिस वाले कहते हैं एलजी साहब आये हुए हैं आप नहीं जा सकते। मतलब वहां लॉक कर दिया गया, उस गेट को लॉक कर दिया गया। एलजी साहब आये हुए हैं तो एलजी साहब सब जगह दखलांदाजी करेंगे। एलजी साहब हर जगह दखलांदाजी करेंगे। एलजी साहब जलबोर्ड में दखलांदाजी करेंगे। एलजी साहब फ्लड डिपार्टमेंट में दखलांदाजी करेंगे। एलजी साहब ही चला लें फिर दिल्ली। क्या जरूरत थी दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जो काम करना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री साहब काम करना चाहते हैं। उनके कामों को देखकर डर के मारे जिस तरह का काम हो रहा है। कितनी लाइनें वहां वेस्ट पड़ी हुई हैं। डाल नहीं पा रहे हैं के जी लाइनें तो आ चुकी हैं, फाइनेंस नहीं है। तो एलजी साहब को चुनाव लड़ लेना चाहिए। भई मैं यहां का बॉस हूँ चुनाव लड़ लेना चाहिए, चुन के बन जायें, क्या दिक्कत है। एलजी साहब फिर चलायें दिल्ली को। तो वो ही वाली बातें हैं कि ये जिस तरह की घिनौनी राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है, दिल्ली के अंदर खासतौर पे मैं देख

रहा हूँ। इतना मैंने कहीं नहीं देखा जो बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी जिस बदले की भावना से काम कर रही है दिल्ली के अंदर उसको ये सोचना चाहिए क्योंकि ये पेयजल का मामला है, पानी पीने का मामला है। पानी से संबंधित मामला है, सीवर का मामला है। मैं जैन साहब की विधान सभा के अंदर पता है क्या है, मेरा बेच मार रहा है सीवर, तो कहते हैं ये बेच क्यों मार रहा है। मैंने पूछा अधिकारियों से, कहते हैं बेच इसलिए मार रहा है कि वो ट्रंक लाइन में सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, वो बंद पड़ा है। जो बड़ी जो मेन लाइन केसवपुर को जाती है तो उसमें मेरी विधान सभा में साफ हो गया लेकिन वो जैन साहब की विधान सभा की वहां सफाई नहीं हुई है। अब हमारे अधिकारी कहते हैं हम वहां क्या कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की समस्यायें पैदा कर दी गई हैं। उन समस्याओं को देखते हुए लगता है कि मैं एलजी साहब से भी ये आग्रह करूंगा ऐसी घिनौनी राजनीति ना करें और इस तरह का काम ना करें और अधिकारियों से भी कहूंगा हो सकता है अधिकारियों को डर हो। उनको कहा जाता है तुम्हें काले पानी भेज दिया जायेगा। तुम्हें वहां ट्रांस्फर कर दिया जाएगा। असम में ट्रांस्फर कर दिया जाएगा। तुम्हें वहां ट्रांस्फर कर दिया जाएगा तो वो डर के मारे क्या करें। वो इनके इशारे पर चलते हैं तो उस इशारे को अगर मैं समझता हूँ अगर सदन के अंदर आप उनको किसी कमेटी के माध्यम से उन अफसरों को बुलायें। उनकी मजबूरियां पूछें कि भई क्या मजबूरी हैं

आपकी। किस वजह से क्यों नहीं कर रहे हो और हमारे यहां जैसे-जैसे वहां की पोपुलेशन है, और पानी के कनैक्शन चाहिए। पानी के कनैक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं आ रहा है और कई जगह कनैक्शन भी है तो पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी जितने भी हैं छोटे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। वो क्या करते हैं दो दिन इसका खोल देते हैं फिर दो दिन बाद वो खुश हो जाता है। धन्यवाद करने आता है जी खुल गया पानी। फिर दो दिन बाद इसका बंद करके उसका खोल देते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये तो जादूगर का मामला चला रखा है। दो दिन इसका खोल देते है कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। तो सबको खुश करने के लिए इस तरह का जो मामला चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम 2025 में 24 या 25 में हम 24 घंटा पानी देंगे तो मेरे को लगता है उसको रोकने की एक साजिश है ये। ये काम ना हो पाये। जलबोर्ड को कैप्चर कर लिया जाए अधिकारियों द्वारा। तो ये इस तरह की साजिशों से जो काम चल रहा है मैं एलजी साहब को ये और आपके जो अधिकारी हैं उनको बुलाके यहां समझाया जाए और ये एलजी साहब अगर इस तरह की दिल्ली में घिनौनी राजनीति करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के माननीय सदस्य भी यहां बैठे हुए हैं वो भी कम से कम हमारे साथ मिलकर काम करें। ये पेयजल का मामला है।

माननीया अध्यक्षः सोनी साहब कम्पलीट कीजिए। कम्पलीट कीजिए।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस कॉलिंग एटैन्सन में दिल्ली जलबोर्ड पर दिनेश मोहनिया जी ने जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है उस पर मेरी बड़ी स्पष्ट राय है कि दिल्ली सरकार काम नहीं करती, सिर्फ बहाना करती है और हमेशा दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना उनकी आदत सी बन गई है। कभी वो केन्द्र सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी वो एमसीडी पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ेंगे। अलग-अलग मुद्दो पर वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। प्रकाश जारवाल जी ठीक कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि भई नौ वर्ष में कभी भी पैसों की कमी नहीं थी तो नौ वर्ष में आपने क्या किया भई आपने जो दिल्ली से वादा 2013 में भी किया, 15 में भी किया। चौबीस घंटे साफ पानी देने का वायदा हर एक साल दर साल, साल दर साल आप वादा करते रहे। तब तो आपने ये बात 9 साल में नहीं रखी। स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी की सरकार जब थी 93 वाली उस समय दिल्ली जलबोर्ड 800 करोड़ रूपए के प्रोफिट में था। साढ़े 300 करोड़ की एफडी थी जो दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के

लिए ही थी, कहां गई वो एफडी? सफाचट्ट। कहां गए वो पैसे और क्या कारण है कि आज 70 हजार करोड़ से ऊपर की लायबिलटी हो गई है। आप क्यों ना ऑडिट करें, हिम्मत है अगर केजरीवाल सरकार में तो ऑडिट कराये और श्वेत पत्र इस सदन में लाये, दूधा का दूधा और पानी का पानी हो जायेगा दिल्ली वालों के सामने। दिल्ली में 675 एमजीडी हरियाणा से पानी आता है। 253 एमजीडी यूपी से पानी आता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। 9 साल में हम आज भी दो कदम नहीं चल पाये। रेन वाटर 98 परसेंट आज भी दिल्ली का बर्बाद हो रहा है। उसकी स्टोरेज का कोई प्लान हमारे पास नहीं है। 26 में से 16 सीवेज प्लांट आपकी रिपोर्ट के अनुसार ही स्टैण्डर्ड को बीटआउट नहीं करती है। 1799 कॉलोनियों में कहा था कि हम टेंकर मुक्त दिल्ली कर देंगे, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने दिल्ली में 894 टेंकर थे आज 1204 टेंकर हैं। यानि टेंकर माफियाओं को बढ़ाने के लिए, उनको फलने फुलाने के लिए टेंकर बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को पीने का साफ पानी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज जी ने कहा कि ये मुद्दा पॉलिटीकल है। पॉलिटीकल आप कर रहे हैं। आपने एक बात और कही दिल्ली को गुमराह करने के लिए आप चाईना की बड़ाई कर रहे हैं। आप जर्मनी, जापान की बड़ाई कर रहे हैं। अरे हिन्दुस्तान की वो ताकत हो चुकी है कि दुनिया हिन्दुस्तान की बड़ाई कर रही है, आप उन देशों की बड़ाई करते

रहिए। आज भारतवासी का गर्व मोदी जी के नेतृत्व में, हिन्दुस्तान की पूरी दुनिया बड़ाई कर रही है, उस ताकत के लोह को मान रही है। आप कहते हैं चाइना से सीखों, आप कहते हैं अरे चुप करो सुनने का माद्दा रखो। आप कहते हैं कि चाइना से सीखों, आप दिल्ली सदन में कह रहे हैं चाइना से सीखो। अरे हम चाइना से क्यूं सीखें, आज दुनिया भारत से सीख रही है। भारत से सीख रही है दुनिया। हमको चाइना से सीखने की जरूरत नहीं है। अभी एक बात और कही ऋतुराज जी ने कही कि भई

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी एक मिनट मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। एक मिनट आपने सुबह निवेदन किया इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस विषय पर हो रही है। साथी सदस्य ने क्या कहा, आपको जवाब देने के लिए नहीं कहा। आप विषय पर रहे। अपने विषय पर अपना वक्तव्य रखिए। ये गलत है। ये बहुत गलत है। आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री अजय कुमार महावरः मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। सदन में अगर वो उनको आपको रोकना चाहिए था फिर। वो विषय से बाहर बोलेंगे। वो भी अपने विषय पर बोलते। ठीक है।

माननीया अध्यक्षः आप सिखायेंगे क्या करना है। आप आ जाइये यहां पर आप यहां आकर बैठ जाइये। या तो चर्चा मांगते नहीं।

श्री अजय कुमार महावरः अमृत जल योजना के तहत भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को करोड़ों करोड़ रूपए दिये हैं। खाली सोनिया विहार के जो प्लांट हैं उस प्लांट के लिए भी 83 करोड़ से ज्यादा भारत सरकार ने दिये हैं। इसलिए भारत सरकार हमेशा दिल्ली सरकार की मदद के लिए तत्पर है लेकिन अभी आयुष्मान की बात कर रहे थे, अरे भई आप लागू नहीं करोगे तो क्या करेंगे। जलबोर्ड के लिए भी, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार दिल्ली को मदद करने के लिए तैयार है। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत आरोप लगाये जलबोर्ड के 360 पेज में अरविंद जी ने कहा था कि शीला जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं दिल्ली जल बोर्ड के, तब उन्होंने फिर उसपे माफी मांग ली। 360 पेज पे कोई कार्यवाही नहीं करी। इस बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। ठीक है हम चाहते हैं दिल्ली की समस्या का समाधान हो, हम चाहते हैं कि समन्वय बने। हम चाहते हैं कि सिर्फ टकराव की राजनीति से आप बाहर आइये। आप दिल्ली के जनहित में आप बार-बार कह रहे हैं कि चुनाव-चुनाव की बात अगर है हिम्मत तो सिर्फ जलबोर्ड के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इन मुद्दे पर आ जाइये चुनाव में, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। आ जाइये मैदान में। केन्द्र में 7-0 से हमने भी कई बार आपको लिटा दिया है। उसकी भी आप चिन्ता कर लीजिएगा। आपने कहा कि आज कल शिक्षा की चर्चा है इसलिए डर गई है मोदी सरकार। अरे शिक्षा की नहीं घोटालों की चर्चा हो रही है।

शराब की, शीशमहल की, पानी पटन घोटाले की, सतर्कता विभाग की, विज्ञापन घोटाले की चर्चा आज देश भर में हो रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन समन्वय के साथ मिलकर के हम समन्वय के लिए आगे आने को तैयार हैं। हम सहयोग करने को तैयार हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए दो कदम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं, दो कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। आइये मिलकर के दिल्ली की सेवा करने के संकल्प को पूरा करें ना कि जो राजनीति को आपने कहा कि राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को बंद करें। अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद। करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। आपने मुझे जलबोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो सभी साथियों ने बात रखी है किस तरह आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत बिना बजट के हो गई है मैं उससे सहमत हूँ। ये अकेला मेरा नहीं ये सभी साथियों का और दिल्ली की पूरी जनता का आज दुख है। अध्यक्ष जी पिछले 7-8 वर्ष से कभी दिल्ली में बजट की किसी भी डिपार्टमेंट के लिए चाहे वो शिक्षा विभाग रहा, चाहे डवलपमेंट का रहा, चाहे पानी का रहा कभी कोई बजट की दिक्कत नहीं हुई और मैं तो छतरपुर विधान सभा की बात करना

चाहूंगा। हर डिपार्टमेंट में क्योंकि हमारी जो विधान सभा है वो गांवों की विधान सभा है। अनॉथराइज कॉलोनियों की विधान सभा है और वहां पर 8 साल के अंदर बहुत ही डवलपमेंट के काम हुए हैं। लेकिन जब निगम के चुनाव अभी पीछे होने थे उसके बाद से दिल्ली जल बोर्ड में फंड की जो समस्या पैदा की गई है और आज जैसा अभी मोहनिया जी ने कहा मेरे सभी साथियों ने कहा आज हालात इतनी खराब हो चुकी है कि छोटे से छोटा काम उसके लिए भी बजट नहीं है। जो हमारे जल बोर्ड के अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से काम में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ विधान सभा की अगर हमारे यहां पर टयूबवेल लग गये हैं उनको लगे हुए भी दो-दो, तीन-तीन महीने हो चुके हैं। उन टयूबवेलों में हम मोटर नहीं डाल पा रहे हैं बजट की वजह से। जिन टयूबवेल्स में मोटर डल गई हैं उनमें हम कनैक्शन नहीं दे पा रहे हैं लाइन से जोड़ने के लिए और जनता परेशान है। मैं इस बात सहमत हूँ कि ये जो हालात पैदा किये गए हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, एलजी महोदय की तरफ से, चीफ सेकेट्री दिल्ली की तरफ से और बीजेपी की केन्द्र सरकार की तरफ से पैदा किये गए हालात हैं। बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अधिकारियों से जब बात होती है तो जो भी फाइलें हैं वो ऊपर से नीचे तक कभी नीचे तक फाइल आती है फिर क्यूएरी लग जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर क्यूएरी लग जाती है और लगातार जनता को परेशान किया जा रहा है। छतरपुर विधान सभा में

महोदया जी पहले से ही पानी की कमी रही है। क्योंकि विधान सभा बिल्कुल बोर्डर पे लास्ट में है। फिलटर्ड सप्लाई भी काफी कम रही है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब गर्मियां आती हैं तब तो बीजेपी की सरकार के द्वारा जो कच्चा पानी आता है उसको कम किया जाता है। जिससे कि जनता परेशान हो और जब इस बार गर्मियों में तो जनता परेशान थी ही उसके बाद पानी की कमी से और उसके बाद पानी जिस तरह से भरा गया उससे जनता को फिर मारा गया। अध्यक्षा जी, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है। दिल्ली की जनता आम आदमी सरकार को लगातार तीसरी बार बहुमत देकर चुना है। मैं अपने बीजेपी के साथी भी यहां पर बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब जनता ने आम आदमी पार्टी को अरविन्द केजरीवाल जी को चुनकर भेजा है तो आप जनता से किस बात का बदला लेना चाहते हैं। दिल्ली की जनता आज पानी के लिए इतनी परेशान है अध्यक्षा जी प्रतिदिन मुझसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग मिलते हैं और वो छोटी-छोटी चीजें कि हम एक वॉल्व नहीं लगा पा रहे हैं। हम पाईप को 10 फिट का पाईप नहीं डाल पा रहे हैं। अधिकारी सब मजबूर हैं तो बहुत ही अन्याय दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है। एक बहुत अत्याचार दिल्ली की जनता के साथ है। मैं तो ये ही कहूंगा कि जो इसके लिए मजबूर है भगवान उनको सद्बुद्धी दे। आखिर भारतीय जनता पार्टी को भी तो अगर दिल्ली की जनता अरविन्द केजरीवाल जी को प्यार करती है तो इनको भी तो दो-दो बार

सातों सांसद इसी दिल्ली की जनता ने दिये हैं, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहता हूँ जनता के बीच में काम करते हैं। मैं आज इस सदन में बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता आज बीजेपी के साथ नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जनता को सताया जा रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अभी हमारे साथी कह रहे थे चुनाव में आने के लिए। चुनाव में हम हमेशा से आते रहे हैं और बहुत समय नहीं है। 8 महीने बाद चुनाव है जो आपने जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया है। 8 महीने बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 की 7 सीटें आपसे जा रही हैं और आम आदमी पार्टी सातों सीटें 2024 में दिल्ली में जीतकर आयेगी। मैं इस बात के लिए फिर एक बार ये ही कहूंगा कि दिल्ली की जनता से किस चीज का ये बदला भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भगवान उनको सदबुद्धी दे और दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का चुनने का उसको वो जो है हमेशा के लिए उसको उनको मानना चाहिए कि दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल जी को चाहती है आप चाहे कितना भी त्रस्त कर लीजिए वो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को फिर समर्थन देगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रवीण देशमुख जी।

श्री प्रवीण कुमारः माननीय अध्यक्षा महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्षा महोदय, दिल्ली जल बोर्ड का ये लोगो है और

दिल्ली जल बोर्ड के इस लोगो पर लिखा होता है- 'जलमेव जीवनम्' मतलब जल ही जीवन है और दिल्ली जल बोर्ड का कर्तव्य होता है कि घर-घर तक पानी पहुंचाना। और पिछले 8 साल पहले जिस तरीके से दिल्ली में पानी की हालत थी, लोग टैंकरों से पानी भरते थे, टैंकरों में कई सारे सैकड़ों पाइप डले होते थे, ऐसे लगता था पता नहीं क्या बवाल है। वो सैकड़ों पाइप जो हैं वो टैंकरों में डले होते थे और नीचे बाल्टियां रखी हुई होती थी। मेरे क्षेत्र में भी इसी तरीके का हाल था लेकिन मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद इस तरीके के मेरे क्षेत्र से टैंकर वाली व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई, वहां पर पानी की लाइनें डल गईं कई सारी सीवर लाइनें हमने इस 8 साल में क्षेत्र में डलवाईं कई ऐसे बहुआयामी कार्यक्रम जो हैं वो मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेतृत्व में चले, जिसमें लोगों के पानी के बिल माफ हुए। और दिल्ली जल बोर्ड के कार्य से दिल्ली की जनता बहुत खुश थी, बहुत प्रशंसा कर रही थी लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये चीज रास नहीं आई और इन्होंने एक षडयंत्र के तहत जो है वो दिल्ली के जल बोर्ड को पूरी तरीके से धवस्त करने का प्लान इन्होंने बनाया। और इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में जिस, आज तक कभी पैसे की कमी नहीं हुई, 8 साल से जब तक हम हैं तब से आज तक जो है पैसे की कमी नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड में छोटे-छोटे कामों के लिए भी, रिपेयरिंग के लिए, मैन हॉल चेंज करने के लिए, ढक्कन

की रिपेयरिंग के लिए, मैन हॉल बनाने के लिए, इन कामों के लिए भी बजट नहीं था।

लोग मेरे पास आते, अभी एक हमारे यहां कॉलोनी है सनलाईट, वहां से कुछ लोग मेरे पास आये, उनके यहां भी गर्मी में भीषण पानी की समस्या हो गई थी। मैंने अधिकारियों को बोला, उन्होंने कहा बजट नहीं है। जैसे-तैसे करके वहां पर लोगों ने खुद के खर्चे से वहां पर पानी की लाइन डलवाई लेकिन जब खुद के खर्चे से लोग पानी की लाइन डलवाते है तब समझ लीजिए आप वहां के रह रहे एम.एल.ए. की क्या हालत होती है। वहां के एम.एल.ए. की विडंबना आप समझिये।

और इससे बड़ा एक इंसीडेंट मैं आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिये और मुझे लगता है कि, वो बात आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले मेरे पास वाल्मीकी समाज की एक माता आई, उसने मेरे को कहा कि एक महीने पहले मेरे बच्चे को मारकर सीवर में फेंक दिया गया है, मैं शॉक्ड रह गया, मैं हिल गया अंदर से मतलब ये क्या चीज है। एक महीन से सीवर के अंदर बॉडी पड़ी है। उसने बताया कि तफतीश में, पुलिस की तफतीश में अब जाकर निकलकर आया है कि सीवर में बॉडी पड़ी है और वहां से मुझे वो बॉडी निकलवाना है और मुझे पता करना है कि मेरा बच्चा अंदर है। कहती है मेरे को रोज सपने में आता है मेरा बच्चा। मैंने उसी टाइम अधिकारी को फोन लगाया, मैंने

कहा ये इंसीडेंट हो गया है और तुम्हारी जो भी, पहले तो मैंने डी.एम. को फोन लगाया फिर मैंने डी.एम. से व्यवस्था कराई कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजकर जो है वो मैन हॉल में उतरकर वहां से जो भी चीजें हों वो निकालकर लाये। लेकिन एनडीआरएफ वो, क्योंकि वो ट्रंक सीवर था, बड़ी जो ट्रंक सीवर होते हैं न 20-20 फीट के, वो ट्रंक सीवर था, वहां पर एनडीआरएफ की टीम गई, नीचे उतरी, लेकिन जो है वो ट्रंक सीवर इतना लंबा होता है कि वहां पर पूरा चैनल होता है तो उनको वहां पर कुछ, मतलब failed हो गया, मतलब कुछ ज्यादा मिला नहीं। फिर उन्होंने कहा ये सर ऐसे नहीं होगा, एनडीआरएफ वालों ने, कह रहे हैं आपको ये पूरा नाला जो है वो रूकवाना पड़ेगा मतलब जो पूरी सीवर लाइन जो है, ट्रंक सीवर वो रूकवाना पड़ेगा, उसमें रोका लगाकर फिर इसकी सफाई होगी। मैंने अधिकारी को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब ये बॉडी निकलवानी है किसी भी तरीके से, आप जो है व्यवस्था करो इसकी। उसने कहा भाई साहब इस समय दिल्ली जल बोर्ड में बजट नहीं है। मैंने कहा बजट नहीं है, एक मां रोज मेरे दरवाजे पर आकर रो रही है, उसकी आंखों से आंसू रूकते नहीं है और मैं उसको क्या बताऊं, मैं उसको ये बताऊं कि मैं ये निकाल नहीं सकता हमारे पास बजट नहीं है। इस तरीके का जवाब मैं उस मां को देता। इससे अच्छा तो, मुझे शब्द नहीं है कि इसके आगे क्या बोलूं। इस तरीके की स्थिति जो है दिल्ली जल बोर्ड की हो गई है। जिस तरीके से

मैं वहां के अफसरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि किसी तरीके से उन्होंने अपनी जो पर्सनल उनकी इतनी दिन की रेपो थी उस कारण से उन्होंने किसी तरीके से मशीन मंगवाकर, बड़ी-बड़ी जो मशीनें आती हैं और भी मशीनें आती हैं, किसी तरीके से उस सीवर लाइन में रोका लगाकर वहां से जो भी उसका, वो सीवेज आइटम्स था उसको छानकर जो है जो भी उसमें कुछ पार्टस उसमें मिले वो सारी चीजें जो हैं उन अधिकारियों के बल पर, उन्होंने पर्सनल बल पर जो है, पर्सनल रेपो जो इतने सालों में उन्होंने कमाई उस कारण से, क्योंकि उनकी भी संवेदना जो है, वो भी इंसान ही है, उनकी भी अंदर से संवेदना जो है वो जाग गईं और उन छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी नहीं छोटे अधिकारी, उन्होंने जो है उस, इस बड़े इंसीडेंट में मदद करी। हालांकि ये केस जो है वो सारा अभी तफतीश में है लेकिन ये हिला देने वाला केस जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति बयां करता है कि एक मशीन मंगवाने के लिए आपके पास जल बोर्ड के लिए बजट नहीं है।

और ऐसी स्थिति जल बोर्ड की पहली बार हुई है अध्यक्षा महोदय। जिस तरीके से, लेकिन ये सारी स्थिति जो है वो उत्पन्न क्यों हुई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली के सारे अधिकार छीनना चाहती है। इन्हें अच्छा नहीं लगता कि दिल्ली के लोग जो हैं वो खुश रहें। इन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि दिल्ली के लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करें। ये दिल्ली की जनता को दुखी देखकर खुश

होते हैं, दिल्ली की जनता रोती हैं तो ये खुश होते हैं कि और दिया था केजरीवाल को वोट, और दबाओगे झाड़ू पर बटन, ये खुश होते हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कई बार वो जो धार्मिक सीरियल चलते हैं उसमें कई सारे ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते हैं तो उसमें से कुछ जो है राक्षस आकर उसको भंग करने की कोशिश करते हैं और फिर खूब हंसते हैं, हा-हा, हा-हा। इस तरीके के माहौल जो है इन्होंने दिल्ली में बना दिया है। इस तरीके का वातावरण मतलब दिल्ली के लोग परेशान होंगे, दिल्ली के लोग जो हैं पानी को मोहताज होंगे तब ये खुश होंगे। इस तरीके की स्थिति इन्होंने यहां पर, दिल्ली में बना दी है। ये कहते थे दिल्ली जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, टैंकर घोटाला हो गया, फलाना हो गया, बहुत होर्डिंग-वोर्डिंग लगाये थे अभी दो-एक साल पहले। सारी तफतीश कर ली, इनको कुछ नहीं मिला। सारी ई.डी., सी.बी.आई. सब कुछ देख ली, कुछ नहीं मिला।

लेकिन इनके, भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी महावर जी कह रहे थे, मैं बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राज में ये महाघोटाला जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का हुआ है जहां पर 18 करोड़ में एक किलोमीटर की सड़क बननी थी वहां पर ढाई सौ करोड़ में एक किलोमीटर की सड़क बना रही है, ढाई सौ करोड़ मतलब खाने की भी लिमिट होती है यार, मतलब इतनी अंधी काटने लगे, इतनी अति मचाने लगे। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैसी सरकार चला रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, ये

लोग जो हैं दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से लाचार कर देना चाहते हैं लेकिन दिल्ली के लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। दिल्ली के लोग, ये सोचते है ऐसी टुचमुनी हरकतों से जो है वो दिल्ली के लोगों को दबा लेंगे, दिल्ली की सरकार को दबा लेंगे, अरविंद केजरीवाल की सरकार को दबा लेंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम ऐसे, और ये महा-घमंड में हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि 'तुझसे पहले जो यहां पर तख्त-नशीं था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीं था।' तो ये सरकार किसी की नहीं रही है। ये जायेंगे। और ये सोचते हैं ऐसी टुचपुंजी हरकतों से आम आदमी पार्टी सरकार डर जायेगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार डर जायेगी। मैं इनको यहां पर एक कुछ कविता के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो झुकने वाली नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार झुकने वाली नहीं है, एक शिव मंगल सिंह जी, सफमन जी, इनकी एक बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको यहां पर पढ़ना चाहूंगा, जैसे ये मोदी जी का भाषण सुन रहा था उसी टाइम जो है ये कविता मेरे दिमाग में आ गई, बचपन में पढ़ी थी, अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने ये कविता रखना चाहूंगा:

क्या हार में क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं,
क्या हार में क्या जीत में,

किंचित नहीं भयभीत मैं,
संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही,
वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
लघुता न अब मेरी छुओ,
तुम हो महान बने रहो,
लघुता न अब मेरी छुओ,
तुम हो महान बने रहो,
अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
चाहे हृदय को ताप दो,
चाहे मुझे अभिशाप दो,
कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभय वर्मा जी, पांच मिनट।

श्री अभय वर्माः बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। श्री दिनेश मोहनिया जी के कॉलिंग अटेंशन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम कॉलिंग अटेंशन किसी अधिकारी को लेकर था लेकिन चर्चा जल

बोर्ड पर हो रहा है। इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम इस हाउस में दिल्ली की जनता की जो समस्या है, पानी और सीवर उसको लेकर किसी न किसी बहाने से सरकार ने चर्चा कराईं इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद करूंगा। किसी एक अधिकारी को पकड़कर कि वो पैसा नहीं दे रहा, वो फाइल रोका हुआ है, उसके कारण नहीं हो रहा, ये सब आईवॉश है। ये सिर्फ दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। सत्य ये है कि मंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि जल बोर्ड जो प्रॉफिट बॉडी थी आज नुकसान में क्यूं है, इस पर जवाब देना चाहिए। सत्य ये है कि मुख्यमंत्री ने 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार उन्होंने कहा कि हम दिल्लीवासी को 24 घंटे पानी देंगे, उसके लिए आपने क्या-क्या प्रयास किया? दिल्ली की जनता, कम से कम मेरे विधान सभा के लोग ये कहते हैं कि हमें 20 हजार लीटर फ्री का पानी नहीं चाहिए, हमें कम से कम 2 घंटे शुद्ध पानी दे दो पीने के लिए। कभी 2 घंटे मिलते थे, फिर एक घंटे हुए, अब 15 मिनट रह गया है। बहुत गंभीर विषय है मैडम। बहुत सही कहा कि जहर पिला रहे हो क्या। और मेरा ही नहीं, मैं 70 विधान सभा की बात कर रहा हूं लेकिन हम सत्य को न ही देखना चाहते हैं, न सत्य को सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ दोषारोपण करके एक अधिकारी के खिलाफ कॉलिंग अटेंशन लाकर अपने आपको बचाना चाहते हैं। मंत्री जी बतायें न पानी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया, कितने एमजीडी पानी बढ़ाया इन्होंने?

और देखिये कमाल की बात, इस बार सीवर की बहुत बड़ी समस्या आई है। नगर निगम में आपकी सरकार आई, खूब ढोल पीटे गये। जो नालियां, गलियों की, नालियों की सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुईं बारिश का पानी आया सीवर में चला गया, अब सीवर की भी एक कैपेसिटी है वो सीवर बैठ गया, सब तरफ पानी भर गये, नल में भी सीवर का पानी आने लगा। तो अपनी गलतियों को देखना नहीं है और भविष्य के लिए उन गलतियों को ठीक नहीं करना, ये मुझे लगता है कि हाउस में चर्चा होना चाहिए। और जल बोर्ड पर चर्चा होता तो ज्यादा अच्छा लगता।

मंत्री जी से मैं एक और आग्रह करूंगा, हम भी कहते रहते हैं कि 800 करोड़ का घोटाला हो गया, 900 करोड़ का घोटाला हो गया। एक वाइट पेपर आना चाहिए, कितना रुपया जल बोर्ड कमा रहा है, कितना रुपया खर्च कर रहा है।

मैडम एक उदाहरण देता हूं। मेरी विधान सभा में 5 गाड़ियां चलती हैं सीवर लाइन को खोलने के लिए। एक गाड़ी को 70 हजार रुपया महीना जल बोर्ड पे करता है और जब भी मैंने अपनी विधान सभा में पता किया है तो पांचों गाड़ी अवेलेबल नहीं रहा है, कंडीशन यूजेबल नहीं रहा है, कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है। जल बोर्ड के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कई बार मैंने अधि कारियों पर प्रेशर बनाया कि भाई पांच गाड़ी आपने मेरी विधान सभा में लगा दिया, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर पेमेंट जा रहा है, ये क्या मामला है, इसको ठीक करो। नहीं जी, ये तो ऊपर से तय हो

रखा है। और सत्य ये है कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है, एक अधिकारी ने मुझे बताया कि अब सिर्फ 2 महीने के तनख्वाह रह गये हैं। हम अधिकारियों पर दोष लगाकर अपने आपको बचा लेंगे। अरे भई आपने 7-8 साल जल बोर्ड को चलाया है, कैसे घाटे में गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? **xxxxxxxxxxx**[7]

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मुझे ये बताइये..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं बोल रही हूं न।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

माननीया अध्यक्षः अब आप बैठिये।

श्री अभय वर्माः इसलिए तो पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली वाले को, न ही सीवर लाइन साफ हो रहा है। xxxxxx[1]

...व्यवधान...

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी,

..व्यवधान..

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी,

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः सत्य को सुनने में दिक्कत हो रहा है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी, आप बैठिये।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी,

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः जो पैसा जल बोर्ड को मिलना चाहिए..

...व्यवधान...

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीया अध्यक्षः एक सेकंड सुन ले मेरी बात। एक मिनट, दो मिनट चुप रहिए। शांत।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप सब लोग शांत होइये। इतने सारे निवेदन आये हैं जल बोर्ड पर बोलने के लिए।

श्री अभय वर्माः तो जल बोर्ड पर ही तो बोल रहा हूं मैडम।

माननीया अध्यक्षः आप जल बोर्ड पर बोलिये..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः जल बोर्ड की स्थिति क्यूं खराब हुई?

माननीया अध्यक्षः चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का, मैं मौका सबको देती हूं और जो भी विषय से भटकता है मैं सबको टोकती हूं।

श्री अभय वर्माः मैडम मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं।

माननीया अध्यक्षः आप विषय से ही भटक रहे हैं।

श्री अभय वर्माः मैं जल बोर्ड पर ही बोल रहा हूं।

माननीया अध्यक्षः मैंने सुबह बैठते ही कहा था अगर बोलने का मौका चाहिए तो राजनीति छोड़कर विषय पर बोलियेगा। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं आप विषय पर बोलिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपका बोलना बहुत जरूरी है। आप दोनों का बोलना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप विषय पर रहिये।

श्री अभय वर्माः विषय पर ही हूं।

माननीया अध्यक्षः आपको जितना समय बोलने का चाहिए होगा आठों के आठों लोगों को विषय पर बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन वो विषय संबंधित वक्तव्य ही होना चाहिए।

श्री अभय वर्माः विषय पर ही हूं मैडम।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विषय पर नहीं हैं आप।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः जल बोर्ड की इतनी दयनीय स्थिति क्यों बनी?

माननीया अध्यक्षः हां, तो आप उस पर बात करिये न।

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

...व्यवधान...

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीया अध्यक्षः आप विषय पर नहीं, मुझे आपको फिर बैठाना पड़ेगा।

श्री अभय वर्माः xxxxxx[1]

माननीया अध्यक्षः फिर मुझे आपको बैठाना पड़ेगा और आपकी वजह से फिर किसी को भी मौका नहीं मिलेगा।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः मैडम, अगर जल बोर्ड..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः तुम दिल्ली चला रहे हों न।..

माननीया अध्यक्षः एक मिनट।

श्री अभय वर्माः दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रहे हों न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी, विषय पर रहिये। बस, शांत।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शांत हो जाइये।

...व्यवधान...

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीया अध्यक्षः आपको वोटिंग कराने की..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको वोटिंग के लिए बोलने से 10 मिनट पहले ही उस पर रूलिंग दे दी।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः ये सत्य सुनना नहीं चाहते।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही उसके लिए बोल रही हूं। ये निकाला जाए कार्यवाही से जो जल बोर्ड के विषय के अलावा इन्होंने बोला है अभय वर्मा जी ने।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः मैडम,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप विषय पर रहिये। देखिये..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जल बोर्ड की जो ये दयनीय स्थिति बनी है ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कारगुजारियों के कारण बनी है।..

माननीया अध्यक्ष: हो गया, अब आगे बढ़िये।

श्री अभय वर्मा: मेरा सिर्फ इतना ही कहना है..

माननीया अध्यक्ष: आपको बस इतना ही कहना है?

श्री अभय वर्मा: कि जल बोर्ड पर पॉजिटिविटी के साथ बैठना चाहिए। जल बोर्ड घाटे में गई है इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, उस कमियों को दूर करना चाहिए और दिल्लीवासी को 24 घंटे पानी देने का जो वायदा मुख्यमंत्री जी ने किया है वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 2 घंटे पानी सुबह और..

माननीया अध्यक्ष: चलिए, धन्यवाद।

श्री अभय वर्मा: 2 घंटे पानी शाम में देने का प्रयास करें।

माननीया अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी। देखिये सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है अपने विषय पर रहें। क्योंकि ये, ये समस्या सबकी है और उसके बाद जो मैं रूलिंग दूंगी उसको आप जो है खुशी से उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो विषय से आप लोग बिल्कुल न भटके, अपने विषय पर रहें क्योंकि 70 के 70 विधायक जो है मुझे लगता है इस विषय पर बोलना चाहते हैं, अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। तो सबको अगर समय चाहिए तो ोकस अपने विषय पर रखियेगा।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आज दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर पहले तो मैं एक शायरी से शुरूआत करना चाहता हूंः

'तुम्हारी भोली सी मुस्कान में एक उम्मीद नजर आती है
और इस बेचैन से मुल्क की तकदीर नजर आती है।'

आज जो इस देश के हालात चल रहे हैं उसमें एक उम्मीद की किरण कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी ओर पूरा आज ये देश देख रहा है तो मैं देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले, बाबा साहेब अंबेडकर के विजन को सपनों को पूरा करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं बहुत-बहुत।

अध्यक्षा जी, सबसे पहले तो मुझे, अभय वर्मा जी अभी यहां बोल रहे थे, मुझे उनकी एक बात पर बहुत आपत्ति है। उन्होंने अभी यहां पर कहा कि जो सफाई की गाड़ियां लगी हुई हैं, देखिए उनकी मानसिकता देखिए आप, क्योंकि उनके, उन्होंने पहले भी एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली के अंदर अपनी विधान सभा में पीटा था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें, उनकी आप मानसिकता देखिए कि उन्होंने सदन में भी कहा कि ये जो 5

गाड़ियां लगी हुई हैं, 70 हजार रुपये जल बोर्ड उनको देता है, वो जल बोर्ड की जो गाड़ियां लगी हुई हैं अभय वर्मा और भाजपा के लोगों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल जी ने वो विजन दिया दिल्ली को कि जो लोग, सीवर के अंदर जिनकी मौत होती थी, जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी मृत्यु न हो, सीवर की सफाई उससे न हो, मशीनों से कराने का काम किया, तब उनको पेमेंट की जाती है। और उसके बाद वो मशीनें दी किसको गई, अभय वर्मा जी को बहुत दर्द है क्योंकि वो मशीनें उनको दी गई जिनके परिवार की मृत्यु उस सीवर के अंदर हुई थी, उन महिलाओं को दी गई जिनके पति की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार को दी गई वो सीवर की मशीनें इसलिए 70 हजार का भुगतान सरकार करने का काम करती है। और आज एक बात और बता दूं, जिस फाइनेंस सेक्रेटरी की आज यहां बात हो रही है, जिस एल.जी. की यहां बात हो रही है, आज 4-4 महीने हो गए उन लोगों को जिनको गाड़ियां दी गई थी, जिनको गाड़ी मुख्यमंत्री जी ने दी थी उनको आज 4 महीने से आपके फाइनेंस सेक्रेटरी ने और तुम्हारी मानसिकता के कारण उन लोगों की पेमेंट नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हमेशा दलित विरोधी लोग रहे हैं क्योंकि उनको ये दिमाग में खटकता है कि दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकी समाज के लोगों को 70 हजार का भुगतान सरकार कैसे कर रही है। अरे तुमने अडानी को पूरा देश बेच दिया, तुमने अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया, sea port

बेच दिया, एलआईसी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, देश में आपको दर्द नहीं है लेकिन किसी सफाई कर्मचारी को, गरीब को अगर 70 हजार रुपये मिल जाते हैं तो तुम्हें बहुत दर्द होता है उस बात का। तो ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को ये सदन समझे और मुझे लगता है ऐसे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इस मानसिकता से परे आये, ये देश बदल रहा है।

दूसरी बात जो अध्यक्षा जी आज जो जल बोर्ड का ये महत्वपूर्ण विषय है, आप ये समझिये कि जल बोर्ड बहुत शानदार काम कर रहा था। जल बोर्ड के अंदर जहां तक पानी की पाइप लाईन नहीं पहुंची थी वहां पानी की पाइप लाईन पहुंच रही थी, बहुत सारी विधान सभाओं में जहां सीवर कनेक्शन नहीं हुए थे, मुख्यमंत्री जी स्कीम लायें और लोगों को कहा कि आप सीवर कनेक्शन में जोड़िये क्योंकि हमें यमुना को साफ करना है तो आप लोगों को फ्री कनेक्शन दिये जायेंगे। 15 हजार रुपये का कनेक्शन जो सीवर का, एक आदमी कराता था वो मुख्यमंत्री जी ने फ्री करने का काम किया, उन लोगों को सफविधा देने का काम किया। उसके बाद दिल्ली के लोगों को जो वाटर कनेक्शन मिलता है, पहले 5-5 हजार रुपये तो दलाली देनी पड़ती थी उसके बाद फाइलों के चक्कर लगाने पड़ते थे तब भी कनेक्शन नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी स्कीम लेकर आयें, माननीय मंत्री जी स्कीम लेकर आयें, यहां जल बोर्ड के मंत्री बैठे हैं वो स्कीम लेकर आयें कि जो भी कनेक्शन कराना चाहता है, हजार रुपये दे, कनेक्शन जल

बोर्ड करके देगा, मीटर भी देगा। जनता को पैसे की सहूलियत दी। बड़ा अच्छा काम दिल्ली के अंदर चल रहा था। विजन था 2025 में यमुना को साफ करना, दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाना। अब भाजपा वालों को पता है कि अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी मिल गया तो इनकी अबकी बार तो 8 आई हैं वो भी नहीं आयेंगी अगली बार, ये जानते हैं। इसलिए बड़ी प्लानिंग के तहत जल बोर्ड के कामों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज जल बोर्ड के अंदर ये स्थिति हो गई कि अगर कहीं सीवर की लाईन बैठ जाती है, लोगों के घर में सीवर ओवरफ्लो मारता है, हम अधिकारी को कहते हैं भई सीवर का काम खत्म करो, कहता है हम पर फंड ही नहीं है। इमरजेंसी फंड तो जल बोर्ड में हमेशा होता था, पहली बार ऐसा हुआ कि जल बोर्ड के पास इमरजेंसी का फंड नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार पर फंड नहीं है, अभी एक मीटिंग थी पेटिशन कमेटी की, हमने वहां पूछा कि भई ये फंड क्यूं नहीं दे रहे हों, कि जी मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। क्या कहा मंत्री जी ने, कि फंड रिलीज करो। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, ये कहा फंड रिलीज करो। जब मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं तो भई वो आदमी है कौन जो फंड रोक रहा है, वो व्यक्ति कौन है जो फंड रोक रहा है? भई एक बात बताओ चुनी हुई सरकार के अंदर क्या कोई भी मंत्री से बड़ा है, कैबिनेट से बड़ा है? वो कौन है जो दिल्ली विधान सभा के फैसले को रोक

रहा है, जो कैबिनेट के फैसले को रोक रहा है? क्या वो आदमी, व्यक्ति संविधान का अपमान नहीं कर रहा है? तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को अध्यक्षा जी यहां सदन के अंदर बुलाना चाहिए और बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि आखिर आपने जल बोर्ड का फंड क्यों नहीं दिया, जल बोर्ड का फंड क्लीयर क्यों नहीं किया। आज दिल्ली के अंदर हा-हाकार मचा हुआ है।

मेरी खुद की विधान सभा, 5 एमजीडी का आरओ का प्लांट लगना था कोंडली विधान सभा के लोगों को पानी पिलाने के लिए लेकिन वहां का आज फंड पास नहीं है तो इसलिए वो टैंडर नहीं हो पा रहा, वो काम रूका हुआ है। मेरे यहां ए-2 में यूजीआर है, पूरा डैमेज हो चुका है, मंत्री जी ने पास कर दिया, सबने पास कर दिया लेकिन आज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां फंड नहीं है। 17-21 ब्लॉक की झुग्गियां हैं मेरे यहां पर, वहां लोग गंदा पानी पी रहे हैं, पाइप लाईन चेंज होनी है लेकिन नहीं हो पा रही क्योंकि जल बोर्ड पैसे नहीं दे रहा। अरे आखिर जल बोर्ड क्यूं काम रोकना चाहता है और ये कौन मिले हुए हैं इसमें? इसमें मिले हुए जल बोर्ड के कुछ अधिकारी और फाइनेंस के अधिकारी और किसके इशारे पर काम चल रहा है, केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इशारे पर काम चल रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो भई अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप लड़ो न, राजनीति में आकर लड़ाई लड़ो, चुनाव आकर

लड़ो। अब चुनाव मेरे सामने छोड़ो, वहां तो जीत ही नहीं पाओगे, मैं तो कह रहा हूं ये ओमप्रकाश शर्मा जी के सामने भी नहीं जीत पायेंगे एल.जी. साहब। बीजेपी वालों के सामने भी नहीं जीत पायेंगे, किसी के सामने नहीं, लड़ लें कहीं से भी, किसी भी सीट से लड़ लें, हमारी तो छोड़ दीजिए, हम तो 50 हजार वोट, एक लाख वोट जीते हुए लोग हैं, वहां भी नहीं जीत पायेंगे। तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और जो अधिकारी कर रहे हैं.. नहीं एल.जी. फिर भी नहीं जीतेगा नहीं, तुम में से कोई भी सारे प्रचार कर लेना, मोदी जी करेंगे एल.जी. का प्रचार तो भी नहीं जीतेंगे।

तो आज जो दिल्ली की हालत इन्होंने कर दी है मैं तो आपसे ये कहता हूं कि इनको यहां बुलाया जाए फाइनेंस सैक्रेट्री को बुलाया जाए और उनसे ये पूछा जाए बुला कर कि भई आप आखिर दिल्ली के कामों को क्यों रोकना चाहते हो जब विधायक चाहता है, मंत्री चाहते हैं, जनता चाहती है भई जनता को परेशान तो मत करो। हम पे सीबीआई भेजनी है, ईडी भेजनी है जो मर्जी करना हमारे साथ कर लो लेकिन लोगों को परेशान मत करो। दिल्ली के लोगों को दुखी मत करो। दिल्ली के लोगों ने तुम्हें 8 पर पहुंचाया था और मैं फिर बोल रहा हूं ये दिल्ली के लोग हैं ये सब जानते हैं अभी चुनाव आएगा तुम्हें तुम्हारी पता लग जाएगी औकात क्या है बीजेपी वालों की, ये सब पता लग जाएगा और भाजपा वाले बड़े घोटाले में बोलते हैं भ्रष्टाचार पर बोलते हैं आज

मैं गया था अध्यक्षा जी एक सोने की सड़क बनी है अभी द्वारका के अंदर सोने की सड़क है वो 18 करोड़ ही कैग ने मैं नहीं कह रहा हूं ये कैग ने उजागर किया है प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना खाउंगा ना खाने दूंगा। अटठारह करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट था एक किलोमीटर सड़क बननी थी 18 करोड़ रूपये में। इन्होंने क्या किया भाजपाईयों ने कमीशन देखो कितनी मोटी है इतनी मोटी कमीशन खोरी ये तो कर्नाटक में 40 percent को पार कर गए। इनकी कमीशन खोरी इतनी मोटी है कि 18 करोड़ से 250 करोड़ रूपये पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बना रहे हैं देख लीजिए। ये इनकी चोरी है फिर ये कहते हैं आयुष्मान की बात कर लो? भई क्या बात कर लें आयुष्मान की आयुष्मान की बात ये कर लें कि तीन मोबाइल नंबरों पे दस लाख लोग योजना का फायदा उठा रहे हैं। तीन मोबाइल नंबर पे और एक तो ऐसा हो गया कि एक महिला के डिलीवरी हुई बच्चे का इलाज यहां चल रहा है और मां का इलाज कहीं और चल रहा है ऐसा कभी दुनिया में सुना आपने आज तक, इनकी सरकार में हो रहा है ऐसा तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है पूर्ण रूप से डूबी हुई सरकार है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये अरविंद केजरीवाल जी के कामों के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते दिल्ली के माडल के मामले में मुकाबला नही कर सकते इसलिए क्या चाहते हैं दिल्ली के काम रोक दो। अरे भई अपनी लाइन को लंबा करो ना तुम भी अच्छे काम करो

जनता तुम्हें चुनेगी, बुरे काम करो जनता नहीं चुनेगी जनता तो आप को पता ही है क्या करती है आपका पहले 15 में ही क्या किया फिर 20 में क्या किया, फिर 22 में क्या किया अब 24 भी आ रहा है अभी बता दूंगा। ये कर्म 24 में लेकर डूबेंगे प्रधानमंत्री को बता देता हूं 2024 में देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और मैं कह रहा हूं मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूं अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं 2024 में। 2024 में जा रही है सरकार तुम्हारी, शर्मा जी आप बचा सको तो बचा लेना, बचेगी नहीं कितना भी कोशिश कर लेना। जैसे निगम में नहीं बचा पाये वहां नहीं बचा पाओगे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को अध्यक्षा जी मैं पुनः कह रहा हूं ऐसे अधिकारियों को यहां बुलाया जाये क्योंकि आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, जानबूझ के प्लानिंग के तहत, गंदी राजनीति के तहत दिल्ली के विकास कार्यों को, दिल्ली के कामों को रोका जा रहा है, जलबोर्ड के कामों को रोका जा रहा है और मैं सभी से कह रहा हूं मैं तो भई अगर ये काम का समाधान नहीं हुआ तो जितनी पब्लिक मेरे ऑफिस में आती है मैं सबसे कह रहा हूं जितनी पब्लिक तुम्हारे ऑफिस में आती है अब की बार फाईनेंस सेक्रेटरी यहीं लेके चलेंगे जरा। उस फाईनेंस सेक्रेटरी को बतायेंगे पब्लिक से कैसे निपटते हैं उनको वहां लेके जायेंगे। एलजी हाउस में लेके जायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं भाई तुम तो चुनाव जीत के आये हो आठ

लोग, तुम्हारी विधान सभा में बड़े काम रूके हुए होंगे जल बोर्ड के और मंत्री जी अभी ना यहां पे जितेंद्र महाजन जी ने कहा था मैं आपका ध्यान चाहता हूं उन्होंने कहा था जी हमारे यहां सब कुछ ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृप्या करके इनके यहां माहौल सब कुछ ठीक है तो इनके यहां का फंड वंड न दिया जाये हमारे यहां दे दो आप। हमारे यहां भिजवा दो जलबोर्ड में। तो जब ये खुद ही बेचारे कह रहे हैं यहां खड़े हो के तो इनके यहां फंड न देके हमारे यहां फंड दीजिये कम से कम इसपे आप ध्यान रखिये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इतने गंभीर विषय पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

माननीया अध्यक्षः शिव चरण जी।

श्री शिव चरण गोयलः माननीय अध्यक्षा जी आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार जब 2015 में बनी और ये मोती नगर विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है आजादी से लेकर 2015 तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। जो भी विधायक बने, जो भी काउंसिलर बने आज तक वहां पर किसी और का राज नहीं हो सका। जब मैं 15 में फरवरी के बाद में जनता के बीच में गया वहां से बुजुर्गों से मिलते थे, महिलाओं से तो बुजुर्ग लोग एक ही बात कहा करते थे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिये बस हमें पानी दे

दो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मोती नगर विधान सभा जहां पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और वहां भी पानी की समस्या और पूरे क्षेत्र में यानि कि ऐसा नहीं कि कहीं। अब हमें तो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि ऐसा कोई घर बचना नहीं चाहिये जहां पर पानी न मिले। घर घर गये हम। और आज पिछले साल तक आप उठा के देख लो हर घर में पानी पहुंच गया। कई जगह तो ऐसी थी हमारे यहां पर आधा आधा किलोमीटर दूर तक पानी ले के आना पड़ता था नाम बता दूं मैं आपको Furniture Block, वहां हफते में एक दिन टैंकर जाता था चूनावटी फायर स्टेशन में पानी लेने जाना पड़ता था 5/35 फन सिनेमा पे पानी भरने जाना पड़ता था ये स्थितियां थी। ये रमेश नगर, कीर्ति नगर आपके मानसरोवर गार्डन, शारदा पुरी, सरस्वती गार्डन जो रिहायशी एरिए हैं पानी नहीं था और उस समय 2015 में डेढ लाख वोटर थे आज वहां पर दो लाख वोटर हैं। संख्या बढ़ चुकी है और पानी हरियाणा जितना दे रहा है आपको पता ही है 900 एमजीडी दे रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हजार एमजीडी किया जितना भी वहां पर कट था जो माफिया था उसको सबको बंद करवाया आज घर घर में पानी देती है। आप पूरी विधानसभा में जाकर पूछ लें कि पानी आया कि नहीं आया। अब ये इस बात से परेशान है कि भई इन्होंने पानी की व्यवस्था अच्छी क्यों कर दी। पानी क्यों भिजवा दिया और 15 से लेकर 22 अक्तूबर तक जितना भी फंड चाहिए था विधानसभा को पूरा मिला। पाइप लाइन डली, सीवर

लाइन डली तो जनता बड़ी खुश थी लेकिन अक्तूबर, नवंबर 22 के बाद छोटे छोटे कामों के लिए मुझे परेशानियां आने लगी तो मेरी अधिकारियों से बात हुई भई कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जी कहीं से फंड की समस्या आ रही है फिर मैंने अपने भाई सोमनाथ भारती से बात हुई बोले जी अभी करते हैं इनका आश्वासन मिला तो बाद में पता लगा कि ये सब उपर से फंड रोका जा रहा है। हमारे अधिकारियों को किसी ना किसी राज्यपाल के माध्यम से फंड को रोका जा रहा है। हमारे उधर शास्त्रों में लिखा है जल ही जीवन है और लोग पानी को दान सबसे उत्तम मानते हैं लोग प्याउ लगाते हैं, गर्मियों में छबील लगाते हैं। घर घर लोग पानी देते हैं और ये पानी को रोक रहे हैं। ऐसी कैसी मानसिकता है इनकी और भगवान श्री राम की बात करते हैं मानते भी हैं लेकिन भगवान श्री राम की बात को नहीं मानते। भगवान श्री राम एक ही बात कहते थे हरेक को अपनाओ, हरेक को जो भी समस्या है दूर करो। राम राज्य की स्थापना की थी ना उन्होंने और ये तो भगवान श्री राम को नहीं छोड़ते और अब ये सीएजी कमेटी की रिपोर्ट आई है 7 बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं 7, अभी तीन चार दिन के अंदर। अब अयोध्या के अंदर 18 करोड़ रूपये का घोटाला हो चुका है। भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर। उसके बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हमारा पवित्र स्थान है उज्जैन का महाकाल, 700 करोड रूपये की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई, हवा में उड़ गयी। पहले वहां दर्शन फ्री में होते थे अब साढे सात सौ रूपये की टिकट लगा दी।

दर्शन भी करने हैं तो साढे सात सौ रूपये की टिकट लो। ये मानसिकता है इनकी। सबसे बड़ा धाम है हमारा केदारनाथ। उसका जीर्णोद्धार किया गया अरबों रूपये का सोना लगाया भगवान शंकर भी नाराज हो गये। वो पीतल कर दिया। तो कहां की बात करते हैं ये? वेद, धार्म की बात करते हैं आडम्बर करते हैं। ये आडम्बर चलेगा नहीं अब। जनता देख रही है। ये जो आडम्बर कर रहे हैं न ये चलेगा नहीं। अभी उस राम राज की बात कर लें। मुझे प्रभारी बनाया लखनऊ का। मैं लखनऊ 4 महीने रहा और मैं लखनऊ में घूमा तो लखनऊ के साथ में दो किलोमीटर के गांव में मैं चला गया। गांव में चला गया तो वहां पर गांव में गया तो आधे लोगों के पास मीटर के कनेक्शन नहीं हैं बिजली के। आधे लोगों के पास बिजली के मीटर के कनेक्शन नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा भई बिजली के मीटर के कनेक्शन क्यों नहीं हैं आपके पास। कहते हैं गोयल साहब आप बैठे हैं दिल्ली में, मेट्रो सिटी में, यहां पर खाने को पैसे नहीं हैं खाने को पैसे नहीं हैं आप बिजली के मीटर की बात कर रहे हैं। फिर मैं एक बारी थोड़ा समय बचा था गोमती नगर, सबसे बड़ा नगर है लखनऊ का और लखनऊ यूपी का दिल है। वहां मैं एक शोरूम में घुस गया एक ड्रेस ली। ड्रेस लेने के बाद जो हैड सेल्समैन था उससे मेरी बात हुई मैंने कहा भई ठीक चल रहा है यहां यूपी में कहता है हांजी। मैंने कहा तेरी तनख्वाह कितनी है, कहता है ये नहीं बताउंगा गोयल साहब। मैंने कहा बता दे यार। उससे चार पांच बार रिक्वेस्ट की उसने कहा

जी मुझे 5 हजार रूपये महीने के मिलते हैं 165 रूपये पर डे। गोमती नगर के शोरूम की बात कर रहा हूं मैं। जब हैड सेल्समैन को 165 रूपये मिलते हैं पर डे के तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी। यहां 5 सौ से 7 सौ रूपये पर डे हमारे मुख्यमंत्री हर परिवार को फायदा करते हैं, 500 से 700 रूपये, पानी में बिजली में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बस में। आप काउंट करके देख लो और वहां पर 165 रूपये मिलते हैं और बात करते हैं राम राज्य ऐसे स्थापित नहीं होता। राम राज्य तब स्थापित होता है जब हर घर में पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, खुशहाली हो, हर एक को छत मिले। और ये बड़े बड़े खोखले वायदे न चलने वाले नहीं हैं। और ये तो दिल्ली की बात कर रहे हैं मैं तो पूरे देश में कह रहा हूं कि अब ये जो कमल का फूल है न मुरझा गया है। और साफ कौन करेगा इसको, साफ कौन करेगा इसको? पहली बार हुआ है एमसीडी की बात करते हैं।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री शिव चरण गोयलः 14 साल के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमने तनख्वाह दी है एक तारीख को। ये बात करते हैं एमसीडी की, 14 साल का वनवास काटा है और आप तनख्वाह कर्मचारियों को मिलती है एक तारीख को। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और जो कहते हैं करके दिखाते हैं।

माननीया अध्यक्षः चलिये गोयल साहब, धन्यवाद।

श्री शिव चरण गोयलः और ये जो परेशान हो रहे हैं न ये इसी वजह से।

माननीया अध्यक्षः सही राम जी।

श्री शिव चरण गोयलः इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि ये जितना काम कर रहे हैं आने वाला समय कहीं अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जायें और इनको कोई रोक नहीं सकता। ये परेशान इस बात से हैं।

माननीया अध्यक्षः चलिये जी बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शिव चरण गोयलः एलजी परेशानी नहीं है परेशानी कुछ और है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका।

माननीया अध्यक्षः समय का ध्यान रखें, विषय का ध्यान रखें।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो टाईम मिलता है उसमें भी समय सीमा बांध दोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है।

माननीया अध्यक्षः शुरू कीजिये।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं कुछ हमारे साथी सम्मानित साथी हैं विपक्ष के उन्होंने कुछ

कटाक्ष किये सरकार के उपर तो उस विषय में मैं तो पहले यही कहूंगा सबपे लागू नहीं होता वो आठों के आठों पे पर उनमें से कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जैसे कहो आप बगैर ब्रेक की साईकिल। जैसे बगैर ब्रेक की साईकिल हो जब ये बोलें इनको जरूर टाईम बता दो भई इतने टाईम ही बोलोगे। दूसरा अभी चर्चा की मुख्यमंत्री जी के आवास के उपर। बहुत प्रचार कर रहे हैं चलो अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी का प्रचार हो रहा है पर ये कभी ये नहीं सोचते कि जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो दिन में 3 सूट बदलते हैं और वो भी 10-10 लाख रूपये के। उसका कैलकुलेशन कर लोगे तो हम तो जीरो पे हैं। तीसरा अध्यक्ष महोदय आप चर्चा अभी साथी ने कहा कि दिल्ली सरकार के failure की है उस पे चर्चा होनी चाहिए। आज दिल्ली सरकार के failure की बात नहीं है अगर दिल्ली सरकार फेल होती तो निगम में आम आदमी पार्टी ना आती। पिछले सात साल में जो दिल्ली सरकार ने पानी पे काम किया है और तरह के काम किए हैं उस पे दिल्ली में निगम में सरकार आई है और ऐसी आई है कि इनके होम मिनिस्टर तक पर्चा लेकर गलियों में घूमने पड़ा था कोई भी इनका मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का इनका कोई भी मंत्री ऐसा नहीं था जो दिल्ली में ना घूमा हो। आज एक फ्रेंड।

माननीया अध्यक्षः आप बैठ जाइए मैं बाद में आपको मौका दे दूंगी आप रिलेक्स हो जाइए।

श्री सही रामः बोलूंगा जरूर।

माननीया अध्यक्षः आपको बाद में मौका मिल जाएगा महेंद्र गोयल जी। महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्षा जी जो आपने आज दिल्ली जल बोर्ड के मुददे के उपर मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली को बसाया था भगवान कृष्ण जी के सहयोग से पांडवों ने और बहुत खूबसूरत बसाया था दिल्ली को लेकिन समय समय के उपर लुटती रही उसके ही परिवार के लोगों ने इस दिल्ली को जिसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था उस समय के अंदर। अपने ही परिवार के लोगों ने उस दिल्ली को लूटा। उसके बाद दिल्ली के उपर फिर से आक्रमण हुए। बाहरी लोगों ने दिल्ली को लूटा। अंग्रजों ने दिल्ली को लूटा लेकिन देश के इन्हीं लोगों ने दिल्ली को आजाद करवाया। दिल्ली से जो भी आवाज जाती है पूरे विश्व के अंदर जाती है क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है लेकिन आज केन्द्र के अंदर बैठी हुई सरकार को ये पसंद नहीं आता कि जो खूबसूरत दिल्ली पहले हुआ करती थी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को फिर से खूबसूरत बनाया और दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को फ्री के अंदर पानी दिया, फ्री के अंदर बिजली दी। माताओं को बहनों को, बेटियों को सुरक्षा प्रदान की उनके चलने के लिए, फिरने के लिए बसों को फ्री के अंदर यहां पर चलाया और दिल्ली के लोगों के लिए फ्री के अंदर ही इलाज दिया और फिर भी दिल्ली फायदे के अंदर रही लेकिन अपनों की नजर ने जो

केंद्र के अंदर बैठे हैं मैं तो उनको भी अपना ही कहता हूं क्योंकि वो देशवासी हैं हमारे जिस प्रकार से पांडवों को कौरवों ने लूटा था इसी प्रकार से इन भाजपाइयों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के अंदर लूट रहे हैं दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। मेरे यहां पर तीन वार्डों के अंदर सीवर लाइन का काम चल रहा है। जिन एरियों के अंदर पानी नहीं हुआ करता था बुद्ध विहार जैसे इलाकों के अंदर पानी नहीं हुआ करता था उसके अंदर सरकार बनने के बाद जब से मैं विधायक बना था ठीक नौ महीने के अंदर मैं अपने एरिए के अंदर पानी ले आया था। जब से हम संघर्ष कर रहे थे बहुत सी जगह के उपर सीवर लाइन बिछने के बाद बहुत सी जगह के उपर लाइनें ब्रेक हो जाती हैं पोपुलेशन भी बढ़ती है। पानी की खपत भी बढ़ती है। आज जहां जहां पर भी लाइन कोई ब्रेक हो जाती है तो वो लाइन को ठीक करवाने के लिए आज सौ मीटर भी यदि कोई पाइप लाइन डालनी पड़ जाती है तो दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों के पास में वो फंड नहीं होता कि वो पाइप लाइन को वो ठीक कर सकें। बड़े ही शर्म की बात है जब लोग जिन एरियों के अंदर हम गर्मियों के अंदर भी पानी दिया करते थे मैं इस समय की स्थिति बता रहा हूं जहां पर मैंने मई के अंदर भी पानी दिया है तपती गर्मी के अंदर भी पानी दिया है आज की स्थिति ये है कि उन घरों के अंदर भी वो पानी नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मंशा के उपर सवाल उठते हैं अभी मैंने एक लाइन डलवाई है जिस लाइन के जरिए हमें

बहुत से फायदे होने चाहिए थे उस लाइन के जरिए कुछ एरिए के अंदर तो पानी जा रहा है बहुत ज्यादा उस लाइन के उपर हमें वॉल सिस्टम लगाना था लेकिन वॉल लगाने के लिए अधिकारियों के पास पैसे नहीं हैं। करोड़ों के बजट से लाइन तो हमने डाल दी जहां पर हजारों के उसमें या पांच सात दस लाख रूपये के उससे काम चलना चाहिए वॉल का और ये छोटी छोटी लाइनें जो डायवर्ट करने के लिए हमें वहां पर बिछानी चाहिए आज उन अधिकारियों के पास में पैसा नहीं है। काम तो पहले भी किया करते थे। टैण्डर पहले भी हुआ करते थे टैण्डर हुए हुए भी हुए लेकिन कोई भी ऐजेंसी काम करने के लिए आज राजी नहीं है क्योंकि उनको इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि वो पैसे भी मिल जाएगा क्योंकि अधिकारी उनको बोलते हैं। अधिकारी उनको बोलते हैं कल को पैसा मिले ना मिले भई आप काम मत करना। ये किस वजह से हो रहा है क्योंकि सीइओ साहब छुट्टी लिए बैठे हैं चार चार पांच पांच महीने से दिल्ली जलबोर्ड के सीइओ अपने ऑफिस नहीं आते ये कितनी शर्मनाक बात है और किसके इशारे के उपर हो रहा है ये जो आज सुप्रीम पावर दिल्ली के अंदर एलजी साहब को कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही कहा है बहुत से साथियों ने अभय वर्मा जी कह रहे थे कि चुनाव करवा लें। मैं कह रहा हूं आप किसी भी सीट से चुनाव करवा लें मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं यदि एलजी साहब चुनाव लड़ते हैं तो मेरी विधानसभा में आ के एक बार चुनाव लड़ लें। आज ही लिख

के दे देता हूं मैं एकसेप्ट करें उस बात के लिए आम आदमी पार्टी से तो लड़ने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल उनको टिकट देने वाला नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ जो किया है। वो उसी देश की सबसे बड़ी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ के देख ले दावे के साथ मैं कहता हूं वहां से जमानत जब्त हो के उनकी जाएगी। औकात नहीं है। अभी इनकी कोई औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, मैं तो कहता हूं वहां पे कोई महेंद्र गोयल चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा जमानत जब्त करवा के भेजेगा इतना मान लो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर दम है। मैं तो सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा अध्यक्षा जी ये लाइनें देख के मुझे बड़ा दुख होता है पूरा का पूरा बैंच ये अधिकारियों के लिए होता है आज दिल्ली जलबोर्ड के उपर चर्चा हो रही थी और एक भी अधिकारी नहीं है यहां, कितने शर्म की बात है। ये सफुनिश्चित होना चाहिए जिस भी समय में सदन बुलाया जाए उस समय के अंदर चीफ सैक्रेट्री साहब के साथ साथ सभी के सभी अधिकारी यहां पर मौजूद होने चाहिए। पहले भी हुआ करते थे और आज भी होने चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए वर्ना हम यहां पर आए हैं अपने दुख दुविधा को रो के चले जाएंगे। हम कहेंगे हमने ये बोला वो बोला है लेकिन उसके उपर काम नहीं होगा तो उसका फायदा कुछ नहीं है। ये सदन बुलाना भी इस प्रकार से बेकार हो जाएगा। हम दिल्ली की समस्या को उठाने के लिए आते हैं।

दिल्ली की जनता की समस्या को उठा रहे हैं। मेरे बुद्ध विहार इलाके के अंदर, बुद्ध विहार फेस-2 के इलाके के अंदर, विजय विहार के अंदर आज इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत से एरिया के अंदर पानी नहीं आ रहा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मई, जून के अंदर भी तपती गर्मी के अंदर भी मैंने वहां पर पानी दिया है, आज वहां पर वो पानी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है किसी ना किसी बात की। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके माध्यम से आज इस सदन के अंदर चर्चा होने के उसमें, माननीय मंत्री साहब से मैं आग्रह करूंगा कि और वायस चेयरमेन साहब से भी आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता आज बहुत त्रस्त है और क्षेत्र की जनता की तरफ देखते हुए आप आज पूरी की पूरी दिल्ली की समस्याओं को देखते हुए इन समस्याओं के ऊपर आप भी ध्यान देंगे अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे और एल जी साहब को भी इस सदन के माध्यम से कहूंगा, यदि आपको कोई बड़ी पावर मिली है तो कम से कम उसका ध्यान करें। वर्ना जिस अहंकार के अंदर आप हैं, मैंने पहले भी एक बार सदन के अंदर कहा था, जिस प्रकार से आप अहंकार के अंदर है, उसके अंदर कुछ लाइनें कह देता हूं। अहंकार से तीनों गए, बिधूड़ी साहब सुनने की बात है और मोहन सिंह बिष्ट जी इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अहंकार से तीनों गए धान, वैभव और वंश। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसके तीनों के तीन चीज चली जाती है। उसका धान भी चला जाता है,

उसका वैभव भी चला जाता है और उसका वंश भी चला जाता है। अहंकार से तीनों चले गए, धान–वैभव और वंश और यकीन नहीं तो देख लो रावन, कौरव और कंस। उन तीनों का भी नाश हो गया है। तो एल जी साहब जो आज आप दिल्ली को ये तहस–नहस कर रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो तमाशा देख रही है। मैं उन तमाशाइयों को भी कहना चाहूंगा, तमाशबीन मत बनों, दिल्ली की जनता की तरफ देख लो वर्ना आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा।

माननीया अध्यक्षः गोयल साहब धन्यवाद।

श्री महेंद्र गोयलः और मैं इसी के अंदर सिर्फ तीस सैकंड का टाइम और लूंगा। काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा की लोग तुम्हारे लोटने का इंतजार करें, ना करो अनर्थ कुछ ऐसा की लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। आज लोग आपके मिटने का इंतजार कर रहे हैं। पहले तीन आई, फिर आठ आई, लेकिन अगली बार सुनने के ऊपर है इस बात के लिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी सरकार को भी कहना चाहिए कि दिल्ली की जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए, जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः मोहन सिंह बिष्ट जी। पांच मिनट। 42 पर शुरू हो रहा है आपका।

श्री मोहन सिंह बिष्टः जो बात बोलूंगा, बिल्कुल सही-सही बोलूंगा। आदरणीय उपाधयक्षा महोदया जी आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्षा जी, वास्तव में इस शॉर्टडयूरेशन हो या अल्पकालीक चर्चा हो या जी कोई भी चर्चा हो। चर्चा के लिए समय पहले ही तय किया जाता है। हमने इसी हाउस के अंदर देखा है, यदि कभी अल्पकालीक चर्चा हो या किसी बात में कॉलिंग अटैंशन हो तो निश्चित रूप से अधिकारियों का उनके कक्ष में बैठना अतिआवश्यक है। मैं पहली बार इस सदन के अंदर देख रहा हूं, इस चर्चा का कोई महत्व नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं। आप रूलिंग पढ़ रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, इन नियमों को आपने पढ़ा, लेकिन ये सदन नियमों से बंध हुआ है और यदि जल बोर्ड पर चर्चा हो, आपका एक भी अधिकारी इस कक्ष में ना बैठा हो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, मैंने देखा है, 1993 के अंदर यही जल बोर्ड दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता था, दिल्ली जल मल स्थान के नाम से इसको जाना जाता था, पावर लैस विधान सभा थी उस समय में। तीन-चार डिपार्टमेंट सिर्फ सरकार के पास थी, अध्यक्षा जी लेकिन मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना आज हमारे बीच में नहीं है, हमें उनकी याद आ रही है कि हमारे उस समय में, हमारे भाई रामबीर सिंह बिधूड़ी जी इसी सदन के मैंबर थे। उधर से हमारे प्रहलाद सिंह जी साहनी साहब वो नहीं थे लेकिन वो जब शीला जी के समय में

आए। तो ये सदन के अंदर यदि किसी भी विषय पर चर्चा होती थी तो अधिकारियों को बाध्य कर दिया जाता था, वो दर्शक दीर्घा में यदि चर्चा हो तो अधिकारी कम से कम उस पर जितने भी मैंबर बोल रहे हैं उन मैंबरों की बात को सुनकर के तुरंत डिसिजन लेने का होता था, ये सदन की मर्यादा थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं एक दूसरे को, उसपर आरोप-प्रत्यारोप बिल्कुल करें आरोप-प्रत्यारोप लेकिन उससे हटकर के हमारे लिए सबसे बड़ा है ये सदन। इस सदन के अंदर 70 के 70 मैंबर, चाहे वो मंत्रिमंडल का हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। यदि दिल्ली की बात आती है, हम दिल्ली की समस्याओं को जोरदार ढ़ंग से उठाना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमने इस सदन के अंदर, मैं तो अध्यक्षा जी 2015 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हम लोग रह गए, 2020 के अंदर फिर मैं जीत कर आया। जहां लोग समझते थे ऐसी विधान सभाओं से दूसरा नहीं जीत सकता है, वहां से मैं जीत कर आया। टोटली अनोथराइज्ड कॉलोनिज, गांव का एरिया, अनडवलप एरिया। लेकिन इसी सदन में भले ही सरकार किसी की भी हो तो उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, इसमें काम करने की योजनाओं को बनाया। आज हम इस सदन के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं, हमने कहा की जल बोर्ड के, बहन जी मुझे अच्छी तरह याद है। यही सदन था, लोग भले ही बदल गए होंगे लेकिन उस समय में एक फंडस की ऐसी व्यवस्था थी ताकि वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो उसकी तनख्वाह देने के लिए एक

एफडी बनी थी, शायद भारद्वाज वगैरा आप सब जानते होंगे, 2017 के अंदर, 16 और 17 के अंदर उस एफ डी को तोड़ दिया गया और फिर कहा गया कि यहां पर जो घाटे में सरकार चल रही है वो प्रॉफिट में चल रही है। उस पैसे से जो तनख्वाह दी जाती थी वो तनखा दी जाती थी। लेकिन मैं उस टीका-टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये हाउस मर्यादाओं से बंध हुआ है, नियम और कायदे से चलता है, यदि हमारी अध्यक्षा इस बात को बोल रही है तो निश्चित रूप से हमको उसके बारे में सोचना चाहिए किन पूवाइंटस पर। यदि जल बोर्ड के बारे में चर्चा हो तो जल बोर्ड का बहन जी अलग बजट होता है। इसका बजट का प्रोविजन है, आखिर वो बजट का हुआ तो हुआ क्या। क्यों नहीं बजट आज areas के अंदर दिया जाता है, क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। यदि हम देखें, हमने सभी सरकारों की, काम करने का मौका मिला, सरकारें आएंगी और जाएंगी जनता ऐसे ही रहेगी, जन प्रतिनिधि को काम करना होगा, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तरदायी बनना पड़ेगा। सरकार में क्या है ये, अमूक पार्टी का व्यक्ति है, मैं उस दल का हूं, इसको बजट नहीं देना। अरे आखिर बजट नहीं दोगे तो एरिया के अंदर डवलपमेंट कैसे होगा। क्यों नहीं योजनाएं बनेंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यही जल बोर्ड था, यहीं-यहीं सदन के मैंबर थे, ये साहनी साहब जानते हैं, बिधूड़ी साहब जानते हैं, एमएलए को जल बोर्ड के लिए एक्सट्रा बजट दिया जाता था। जब हमको

बजट अलॉटमेंट होता था तो दो-दो करोड़ रुपया एमएलएज को दिया जाता था। आज एक रुपए का बजट नहीं दिया जा रहा है। अभी इसी सदन के अंदर भारती साहब हम चिल्ला रहे हैं कि साहब 10 मीटर की हम पाइप लाइन नहीं बदल पा रहे। आखिर इसका प्रोविजन कौन रखेगा, कौन इसको करेगा। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बजट अलॉटमेंट करते समय यदि एक या दो करोड़ रुपया उसके बजट के अंदर एमएलए हैड में हो, उसका प्रोविजन रख दिया जाए तो निश्चित रूप से वो छोटे-मोटे काम हो सकते हैं, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट करिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः बहन जी, आप बोलोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, वैसे मैं बहुत सम्मान करता हूं इस चेयर का। आप बोलोगे मैं बैठ जाऊंगा मुझे कोई इसमें ज्यादा एतराज नहीं है। मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि अमूक व्यक्ति यदि हम आठ लोग बीजेपी के हैं, बहन आज हमारी स्कीमों को रोका जाता है। किसके आगे रोएं, कौन हमारी बात को कहेगा। मेरे यहां सोनिया विहार में सीवर लाइन डलनी थी। मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा जिस दिन यहां का एक मंत्री जेल गया। मेरा दुर्भाग्य था वो जेल गया। यदि वो व्यक्ति यहां रहता तो सोनिया विहार के अंदर जो सीवर लाइन की स्कीम थी उस स्कीम के लिए 82 करोड़ रुपया उन्होंने पास कराया, अब उस बजट को रोक दिया गया। क्यों रोका गया। मैं बीजेपी का एमएलए हूं इस

वजह से। बीजेपी वाले के यहां काम ना हो। अरे जनता ने तुम्हे भी तो वोट दिया, ये बैठे हैं दुर्गेश पाठक। तुम्हे भी 88 हजार वोट दिया था। अरे वो तुम्हारे घर के वोट थोड़ी थे। जनता ने दिए, हो सकता है विचाराधारा पर बंधे हुए थे, उन्होंने 88 हजार वोट दिया। बहन जी आज मैं वहां, कल को और हो सकता है, फिर यहां मैं हो सकता हूं या कोई भी हो सकता है। जनता का काम करना चाहिए, यहां तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, हम विधान सभा के लोगों को खून के आंसू रूला देंगे। अरे ये कोई ठीक सभ्यता का दायरा क्या है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बहन जी, जब इसका बजट का प्रोविजन रखा गया है, तो उस समय में जो सीवर लाइन का था उसका अलग से प्रोविजन था। जो आपके टैंकर लगने थे उसका अलग से बजट का प्रोविजन था। मैं आज एक ही निवेदन करना चाहता हूं यहां रोने से कुछ नहीं होगा, आप सब लोगों को एक इच्छा, दृढ़शक्ति बनानी पड़ेगी कि हमें अधिकारियों को इस विधान सभा के सत्र में बुलाने के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा। यदि हम मजबूर नहीं करेंगे, कुछ मर्जी, एक दूसरे मर्जी को गाली दे दो। कुछ मर्जी कह लो, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है, अधिकारी कहे और सरकार को भी करना पड़ेगा। हमने देखा है शीला जी की सरकार। काम करने का तरीका, मदनलाल खुराना जी को देखा। हम सबको याद करते हैं, इसलिए करते हैं कि कम से कम यदि विपक्ष का मैंबर होता था, वो कभी हाउस के अंदर बोलता था तो सामने मंत्री, संतरी और

यहां तक की चीफ मिनिस्टर भी उसको बुलाती थी। ये विपक्ष कहीं आपको लग रहा होगा, आप विरोधी दल के लोग मान रहे होंगे, लेकिन ये आपकी नाक, आंख, कान का काम करती हैं। विपक्ष बोलता है तो सरकार को सीखने का मौका मिला है।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। एक सैकंड आप बैठिए प्रकाश जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः ऐसा है मोहन सिंह बिष्ट जी ने बहुत अच्छी बोली है, तो केंद्र सरकार भी विपक्ष को आंख, नाक, कान समझे, केंद्र सरकार भी विपक्ष की बात को बैठिए। प्रहलाद सिंह जी बैठ जाइए। बिष्ट जी। आप दोनो बैठिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये हो गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये बिष्ट जी। मैं बिष्ट जी की बात पर मैं एक जवाब दे रही हूं, बिष्ट जी ने बोला विपक्ष आंख, नाक, कान का काम करता है तो केंद्र सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाये, दुर्गेश पाठक जी।

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदया आज इस मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया। बिष्ट की बात बिल्कुल

उससे सहमत हूं कि और आपने भी वो संदेश दिया कि केंद्र सरकार को विपक्ष को नाक, कान समझना चाहिए और तुरंत ही हमारे जो दो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह जी और राघव चड्ढ़ा जी। उनको जो सस्पेंड किया है मात्र ये मांग पर की मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और लोकसभा के हमारे जो हैं उनको तुरंत उनका सस्पेंशन वापस लेना चाहिए, ये हाउस ये मांग करती है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्षा जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैंबर का आचरण कैसा होना चाहिए, देखिये आचरण की वजह से उनको सदन से निष्कासित किया गया। मैं एक बात बता दूं बहन, ये वैल में कूद जाओ, ये किसने कहा आपको।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये आप।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः माहौल खराब ना करें बिष्ट जी, बिष्ट जी। बिष्ट प्लीज बैठ जाइये। अच्छा ठीक बैठिए।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः मुझे लगता है कि राघव चड्ढ़ा जी के आचरण को संजय सिंह जी के आचरण को और विजेंद्र गुप्ता जी

के आचरण को एक बार विडियो पर देख लेना चाहिए, किसका क्या आचरण है।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः अच्छा सुन तो लो, अब मेरी बात तो सुन लो। मुझे लगता है कि।

माननीया अध्यक्षः दुर्गेश पाठक जी विषय।

श्री दुर्गेश पाठकः मुझे लगता है कि सभी 70 विधायक इस मुद्दे को लेकर बड़े परेशान हैं और हमने बहुत सारे मुद्दे इस हाउस में डिस्कस किए होंगे लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा वाला मुद्दा ये आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है जल बोर्ड के ऊपर। मैं 4 इग्जाम्पल दूंगा अपनी विधान सभा से। मेरे यहां और अभी जाकर उसको आप चैक कर सकते हैं, लाइव जाकर चैक कर सकते हैं, मेरे यहां नारायणा गांव में एक गली है कुम्हारों वाली गली, आप देखेंगे वहां पर सीवर का पानी लगातार बहता रहता है, सड़क के ऊपर बहता रहता है। सैलुशन क्या है कि सल्यूशन ये है कि एक डेढ़ सौ मीटर सीवर की लाइन बदली जानी है अगर वो लाइन बदली चली जाए तो पानी वहां बहना बंद हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी, सीवर की लाइन बहुत पुरानी है 20-25-30 साल पहले कभी पड़ी थी। इसी तरह से सी-ब्लॉक बुद्ध नगर के अंदर 43 परिवार हैं जिनको पानी की बड़ी दिक्कत होती है, सल्यूशन उसका ये है कि एक दो सौ मीटर की पानी की पाइप लाइन दो इंची

की अगर सीधे-सीधे उनको क्नैक्शन दे दिया जाए तो वो 43 परिवारों को पानी की समस्या नहीं आएगी। इसी तरह से 16 ब्लॉक हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर हर 10-12 दिनों के अंदर सीवर का मिक्स होकर पानी आता है और पानी गंदा आता है, लगभग 15-20 परिवार ऐसे हैं जो गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। सलूशन ये है कि एक पानी की पाइप लाइन बदली जानी है और थोड़ी सी एक सीवर की लाइन बदली जानी है, वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी तरह से हमारे यहां ई-ब्लॉक नारायणा विहार में एक पानी की पाइप लाइन बदली गई, वो पूरा का पूरा बदलने के बाद वो पूरा का पूरा सड़क तोड़कर पड़े हुए हैं उसी में कोई गिर रहा है, कोई साइकिल से गिर रहा है, कोई बाइक से गिर रहा है, हर आदमी बुजुर्ग आदमी गिर रहे हैं, लोगों के पैर टूट रहे हैं, लोग परेशान है। मुश्किल से 5-6-10 लाख रुपए का काम है वो काम सड़क बन जाएगी। इस तरह से मैं पूरी कॉपी लेकर आया हूं, 56 ऐसे काम मेरी विधान सभा के अंदर हैं, कोई पांच लाख रुपए का है, कोई 9 लाख रुपए का है, कोई 10 लाख रुपए का है, कोई 15 लाख रुपए का है। लगभग 56 ऐसे काम हैं जिसके कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ये मैं फाइल भी आज टेबल पर आपके सामने रखता हूं। इसी तरह से मुझे याद है अजय महावर जी, जब मैं चुनाव जीता बड़े भाई की तरह मेरे पास आए और उन्होंने कहा दुर्गेश जी पानी की समस्या किसी तरह से ठीक कर लेना आपकी विधान सभा में बड़ी दिक्कत है। हम लोगों

ने बड़ी मेहनत करके सौ-सवा-सौ बोर का प्रपोजल बनाया, जल बोर्ड के अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की, हमारे residents ने बड़ी मेहनत की। उसमें से 67 बोर पास भी हो गए। डीएम से सारी जो कमेटी बनती हैं, उसमें से किसी तरह से 12 बोर होने का प्रपोजल शुरू हुआ। 12 बोर खुद गए, पानी भी आ गई, पानी साफ भी आ गया, लेकिन अब वो बोर के बाद उसमें चैंबर बनना है, पाइप लगकर कनैक्शन होना है इसका पैसा नहीं है। वो 12 के 12 बोर भी खराब हो गए और साथ ही साथ 55 और बोर जो हो सकते थे जिससे जनता को पानी मिल सकता था वो भी सारा का सारा प्रोजैक्ट ठंड़े बस्ते में चला गया। ये स्थिति कशमोकश लगभग-लगभग हर विधान सभा की है। पहले मुझे ऐसा लगा की मैं शायद नया-नया विधायक हूं मुझे समझ में नहीं आता होगा, मैंने अपने बहुत सारे साथियों को फोन किया। मैंने पूछा यार की ये दिक्कत आ रही है इसको कैसे रिजोल करें, आप मुझे समझाओ कैसे ठीक कर सकते हैं। सबने लगभग-लगभग वही समस्या बताई, आप किसी भी विधान सभा में चले जाइए, छतरपुर से लेकर करावल नगर चले जाइये। हर जगह इस समस्या का दिक्कत है कि जो हमारे बड़े एमरजेंसी के काम है, बड़े प्रोजैक्ट तो चलो बाद में आते हैं, जो छोटे-छोटे काम है, पांच लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसके लिए भी जल बोर्ड फंड नहीं दे रहा है। हमारे सोमनाथ भारती जी हैं, वायस चेयरमेन साहब हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं मैं चाहूंगा इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम

लोगों के लिए जब भी इनको मैसेज तक कर देंग, मैसेज पर रिप्लाई करते हैं, अधिकारियों के साथ कान्फ्रेंस कॉल कराते हैं मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन वो सारी चर्चा इसी बात पर आकर रूक जाती है, की भईया कोई अधिकारी साहब हैं वो फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई ओब्जैक्शन लगाकर भेज देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं आपसे भी मैं ये रिक्वैस्ट करूंगा की जो घर, जिनको इस तरह की पांच-पांच, दस-दस लाख रुपए के कारण पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, सड़क नहीं बनी तो लोग गिर रहे हैं उसके कारण। क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, अगर हम किसी को गंदा पानी पिला रहे हैं और गंदा पानी के कारण वो हॉस्पिटल में जा रहा है, उसकी मौत भी हो सकती है। क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। मैं ये मांग करता हूं इस पटल पर की इस तरह की घटना के लिए पूरी दिल्ली के लिए जो-जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपको क्रिमिनल एक्ट करना चाहिए, क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि लोगों को तो हम दिखते हैं, लोगों ने हमें वोट दिया, लोग हमसे सुबह-शाम पूछते रहते हैं, हमें गालियाँ भी देते हैं। हमें बताते भी अपनी समस्या है। लेकिन अब कितनी बार ये समझाएं एक साल से एक ही चीज समझा रहे हैं कि भईया बजट नहीं, बजट नहीं, बजट नहीं इसका कोई तो सलूशन निकलेगा, जनता परेशान है पूरी तरह से। कम से कम कई बाद सीईओ साहब

को मेल डाल दिया, कई बार उनको मैसेज किया, उनके पीए को फोन किया सर आप ही मिलने का मौका दे दो, हो सकता है हमारे जो दोनों साथी हैं इनको बात ना समझ में आती, हम आपको बात समझा देंगे। पता चला सीईओ साहब तीन महीने से छुट्टी पर हैं। जल बोर्ड के सीईओ, जब दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है। ऐसे समय में अगर जल बोर्ड का सीईओ तीन–तीन महीने की छुट्टी पर होगा तो काम कैसे चलेगा। कैसे काम चलेगा की तीन–तीन महीने से जल बोर्ड का सीईओ छुट्टी पर है। इस पूरे समस्या को कैसे इसको सोल्व किया जाए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई किसी तरह से कोई तरीका नहीं और ये आज जल बोर्ड में दिखने लग गई क्योंकि जल बोर्ड एक तरीके से पानी और सीवर एक ऐसी समस्या है जिससे जनता डायरेक्टली टच में है। धीरे–धीरे ये हर उस डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट जनता के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हो आज हम जल बोर्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर जो एटीटयूड है एल जी साहब का और उनके ऊपर जो बैठे हुए बोस है, जो उनका एटीट्यूड है कि किसी तरह से केजरीवाल को फैल करो दिल्ली के अंदर। अगर ये चलता रहा तो हम जल बोर्ड नहीं बल्कि आने वाले दिनों में हम पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे, हम आने वाले दिनों में हर उस डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा करते रहेंगे जहां इस तरह के अधिकारियों को जबरदस्ती डायरेक्शन

दे-दे कर काम रूकवाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा गम्भीर मामला है और मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं भारतीय जनता पार्टी से भी विनती करता हूं, एल जी साहब से भी विनती करता हूं और उनके सारे जो हमारे सैंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे बड़े-बड़े प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं, दिल्ली बहुत छोटी सी स्टेट है मुश्किल से दो करोड़ लोग रहते हैं, उन्होंने मान लिया की गलती कर दी एक अपने हिसाब से किसी सरकार को चुन लिया, डैमोक्रेसी है किसी को चुन सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा काम करोगे आपको अगली बार चुन लेंगे। लेकिन आप इतना तो मौका दो की जो हम काम कर सकते हैं वो काम तो हमें करने दिया जाए। आप सोचिए की इसमें मुझे लगता है दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आज जी-20 होने वाला है अगले महीने में। सितंबर में जी-20 है। दिल्ली के अंदर 16 ऐसी जगहों पर पीडब्लूडी ने सड़क का ब्यूटीफिकेशन किया है जब वहां से गुजरो तो ऐसा लगता है की ये दिल्ली है ही नहीं। अगर उस पूरे प्रस्ताव को रोका न गया होता एक साल डेढ़ साल पहले मनीष सिसोदिया जी ने सत्येन्द्र जैन साहब ने उस पूरे विजन को देखा था अरविंद केजरीवाल जी ने विजन को देखा था की दिल्ली को ऐसा बनाएंगे। अगर एक साल डेढ़ साल पहले आपने उस पूरे प्रस्ताव को रोका न होता उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को रोका न होता आज सोचिये जब जी-20 के अंदर बाइडेन साहब आएंगे बड़े-बड़े देश के लोग आएंगे, बड़े-बड़े दुनियां के लोग आएंगे

अगर इस तरह की सड़कें देखते हैं दिल्ली के अंदर तो प्रधानमंत्री उनको क्या पता था दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है वो तो प्रधानमंत्री जी का ही सीना चौड़ा होता। ये जो नफरत की राजनीति चल रही है की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो उसे काम नहीं करने देंगे ये बहुत गलत है। एक लोकतंत्र के अंदर ये ठीक काम नहीं है। आज हम, बिष्ट साहब ने कहा आज हम रहेंगे नहीं रहेंगे कल किसी और पार्टी यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग आकर और भी बैठेंगे लेकिन इस तरह की राजनीति से कोई भला नहीं होना इससे सिर्फ और सिर्फ जनता परेशान हो रही है और जनता परेशान होती है तो जनता की आह भी लगती है आपको, बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्षा महोदया।

माननीया अध्यक्षः वो बोलते-बोलते उनका गला खराब हो गया था तो उनको दोबारा नम्बर मिल जायेगा। मेरे पास नहीं आया।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): इस सदन के माननीय सदस्य।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप शुरु करें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आदरणीया अध्यक्षा महोदया, इस सदन के माननीय सदस्य श्री कुलदीप जी ने 2024 में किसकी सरकार होगी उस पर कुछ शंका व्यक्त की है।

माननीया अध्यक्ष: यह विषय है।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अब ये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: एक सेकेंड, आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं आप इतने पुराने सदस्य हैं क्या मतलब।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): चुनाव के बाद हम लोग फिर इस हाउस में मिलेंगे और श्री नरेन्द्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे और हम मिठाई खिलाएंगे।

माननीया अध्यक्षः आप जलबोर्ड पर आ जायें, जल बोर्ड पर आ जायें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः वंदना जी, अभी तो आप समय मांग रहे थे बोलने के लिए, अभी आप सब लोग समय मांग रहे थे और समय खराब भी कर रहे हैं फैसला आप ही को करना है क्या करना है, विषय पर आईये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आदरणीया अध्यक्षा महोदया।

माननीया अध्यक्षः विषय पर रहिये बिधुड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आदरणीया अध्यक्षा महोदया, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 से लेकर और अभी कुछ दिन पहले तक निरंतर दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया की उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वॉटर उपलब्ध कराएगी। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना वायदा करने में पूरी तरह किल हो गईं आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आज दिल्ली जलबोर्ड 72 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही जानकारी दी थी की 2013-2014 में जलबोर्ड 500 करोड़ रुपये के मुनाफे में था आज 72 हजार करोड़ रुपये के घाटे

में चल रहा है। हमारे दिल्ली जलबोर्ड के माननीय चेयरमैन और उस महकमे के मंत्री आदरणीय श्री सौरभ भारद्वाज जी इस सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे यह जानकारी जरूर लेना चाहूंगा की आखिर क्या कारण है की 2016 से दिल्ली जलबोर्ड के खातों की जांच सीएजी के द्वारा क्यों नहीं करवाई गई है। सीएजी ने अनेकों बार दिल्ली जलबोर्ड को पत्र लिखे हैं, आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है आखिर क्या कारण है क्या पूरे देश में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण पेश किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, दिल्ली के लोगों ने शिकायत की कि हमें दिल्ली जलबोर्ड द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वो दूषित है साढ़े 7 हजार सैंपल्स दिल्ली जलबोर्ड ने उठाये और जब उनकी रिपोर्ट आई ढाई हजार सैंपल्स फैल हो गये और कहा गया की यह पानी पीने के लायक नहीं है, इससे पेट की बीमारी हो सकती है अनेक बीमारियां हो सकती हैं। मैं जरूर आदरणीय मंत्री जी का जवाब चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से की दिल्ली में जो जल उपभोक्ता है जब पानी का बिल आता है तो पानी का जो बिल उनको दिया जाता है वह पैसा एक बैंक को दिया जायेगा जो बिल का पैसा है चाहे वो कैश दिया जाए, चाहे वो चैक द्वारा दिया जाए और बैंक जो है उस पैसे को उसी दिन या अगले दिन दिल्ली जलबोर्ड के पास जमा करा देगा ये जल उपभोक्ताओं का पैसा था जलबोर्ड का पैसा था। मैं पूछना चाहता हूं

की आखिर जो बैंक था उसने आगे सबकांटेक्ट कैसे दिया और उसके बाद फिर जिस एजेंसी को सबकांटेक्ट दिया फिर उसने आगे सबकांटेक्ट दे दिया क्या इसमें कानून-कायदे का उल्लंघन नहीं हुआ और जो सैकड़ों करोड़ों रुपये का कलेक्शन हुआ था जो जलबोर्ड में जमा होना था वो जलबोर्ड में जमा नहीं हुआ वो निजी खातों में जमा हो गया आखिर इसका जवाब आज ऑनरेबल मिनिस्टर को इस हाउस में देना पड़ेगा। क्या सरकार ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, एफआईआर की बात छोड़ दीजिए आज बताएं आदरणीय मंत्री जी की उस कॉन्टेक्ट को बढ़ा दिया गया और कॉन्ट्रेक्टर को या जो कॉन्टेक्ट दिया गया उनको 5 परसेंट कमीशन दिया जाता था वह कमीशन बढ़ाकर 6 परसेंट कर दिया इसकी जानकारी तो आज ऑनरेबल मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं जरूर चाहूंगा की आदरणीय मंत्री जी जरूर बताएं की आज जब श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार के जल मंत्री थे क्या दिल्ली जलबोर्ड को 6 हजार करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। उसके बाद शेखावत जी जलमंत्री बने लगभग ढ़ाई हजार करोड़ रुपया उन्होंने जलबोर्ड को उपलब्ध कराया और केन्द्र सरकार पत्र लिखकर निरंतर जानकारी मांग रही है कि ये पैसा कहां खर्च किया गया है आखिर उसकी जानकारी केन्द्र सरकार को क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही है आखिर वो पैसा कहां गया मैं मंत्री जी से इसकी जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर इस हाउस में बैठे हुए हैं क्या दिल्ली के

लोगों के साथ यह वायदा नहीं किया गया था कि हम पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें सुधार करेंगे और उसके लिए कुछ उपाय बताए गए। यह भी कहा गया की हिमाचल से पानी लाया जाएगा एमओयू साइन हो गया आखिर क्या कारण है कि हम उस मामले में एक भी कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। श्री मदनलाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे सोनिया विहार से उन्हीं के समय में सबकुछ हुआ था वही लेकर आए थे। आज इतने लंबे समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है आखिर मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते यह पूछने का तो अधिकार ऑनरेबल मिनिस्टर से है की आज आप बताईये हाउस को की क्या कारण रहे हैं कि हिमाचल से आप पानी नहीं ला पा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, ये भी घोषणा की गई की बरसात होगी यमुना में जो बरसाती पानी बह जाता है समुद्र में जाकर गिर जाता है हम जो किसानों की जमीन यमुना के किनारे है उस जमीन को किराये पर लेकर गढ़ढे खोदकर और उसमें यमुना के पानी को स्टोर करके और उसको ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे आखिर उस मामले में क्या प्रगति हुई हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि हम रेलीवैल लगाएंगे पल्ला में भी लगाएंगे, सोनिया विहार के आसपास भी लगाएंगे आखिर बताएं किन्तु एक भी रेनीवैल क्यों नहीं लगा क्या इसके पीछे कारण रहे हैं मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं डेढ़ सौ एमजीडी पानी

हमको गंगाजल का पानी हमको मुराद नगर से लेना था यूपी सरकार से और लगभग ये समझौता हो गया की वे हमें डेढ़ सौ एमजीडी पानी दिल्ली के लोगों को प्यास बुझाने के लिए देंगे और हम उनको सीवेज का जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को इरिगेशन के लिए देंगे आखिर उस मामले में क्या प्रगति हुई है मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूं और उसमें हमारी किसी मदद की आवश्यकता है यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास चलना है मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ अपने सभी विधायकों को लेकर चलूंगा मैं आज इसकी घोषणा करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): मैं खत्म कर रहा हूं। देखिये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये घोषणा की थी की हम जो सीवेज का पानी है इसको ट्रीट करके लगभग 50 एमजीडी पानी दिल्ली के लिए और उपलब्ध करा देंगे और उन्होंने मीडिया के सामने वह पानी पीकर भी दिखाया था तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कई साल गुजर गये आखिर वो जो 50 एमजीडी पानी मिलना था उसका क्या हुआ ये ऑनरेबल लेफ्टीनेंट गवर्नर तो अभी एक साल से आए हैं लेकिन ये जो घाटा बढ़ता चला गया उसका हिसाब नहीं देना तो मुझे ऐसा लगता है ये बात हम कहते रहे हैं कि हिसाब-किताब सीएजी को क्यों नहीं दिया जा रहा है लगता यह है कि जलबोर्ड

में हजारों-करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है और इस 72 हजार करोड़ रुपये का जो घाटा है जो हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है या घाटा हुआ है उसकी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए और ऑनरेबल मिनिस्टर सीबीआई को कहें की जांच-पड़ताल करें और उसके लिए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो इसमें तो आप कॉम्पीटेंट हैं आप सीबीआई से इन्क्वायरी मांग सकते हैं यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप सीबीआई को लिखिये हम उसका स्वागत करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्षा महोदया बहुत-बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे जलबोर्ड पर बोलने का समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं वो जब मंत्री बने थे मुझे लग रहा था कि जलबोर्ड की स्थिति बहुत खराब है शायद स्थिति में कुछ सुधार होगा लेकिन सुधार होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आज वो बताएंगे की सुधार कैसे होगा उसमें हमारी कहां सहयोग की आवश्यकता है हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः सही राम जी, सही राम जी 5 मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री सही रामः बिलकुल-बिल्कुल अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने समय दिया।

मननीया अध्यक्षः ये कौन सी तमीज़ है अजय दत्त जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदया, आप भी समझ रही होंगी और विधानसभा में सभी मेंबर भी समझ रहे होंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली की जनता के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है फ्रेंडली मैच और फ्रेंडली मैच में क्या होता है अध्यक्ष महोदया की सभी टीमें मिलकर खेलती हैं और यहां तीन टीमें दिल्ली की जनता के खिलाफ भी और दिल्ली की सरकार के खिलाफ भी तीन टीमें काम करती हैं तीन टीमें फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। सबसे पहली टीम का कैप्टन है केन्द्र में बैठी हुई सरकार का होम मिनिस्टर। दूसरी टीम का कैप्टन है दिल्ली का एलजी और तीसरी टीम का कैप्टन है दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर तीनों टीमें मिलकर खेल रही हैं।

...व्यवधान...

श्री सही रामः हां सॉरी–सॉरी फाइनांस सेक्रेटरी सॉरी।

माननीया अध्यक्षः जब आप बोल रहे थे उन्होंने बोला था कुछ।

श्री सही रामः दिल्ली के फाइनांस सेक्रेटरी।

माननीया अध्यक्षः बिष्ट जी, मोहन सिंह बिष्ट जी।

...व्यवधान...

श्री सही रामः चीफ सेक्रेटरी भी हो गये, फाइनांस सेक्रेटरी भी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गलती हर किसी से हो सकती है न माहौल खराब करना बहुत जरूरी है।

श्री सही रामः अब अध्यक्ष महोदया, अब इनमें क्या है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप भी जो बोल रहे थे। मेरे पास तो आंख, नाक, कान हैं तो केन्द्र को संदेशा भेजिये उस विषय का।

श्री सही रामः बिष्ट जी रुकिये जरा, जो मैं कहना चाहता था सब समझ गये हैं।

माननीया अध्यक्षः आप कन्ट्टिन्यू करिये।

श्री सही रामः अब यहां डेली क्या हो रहा है फाइल-फाइल खेली जा रही है वो कैसे सबको पता है कि साल में तीन या चार बार दिल्ली जलबोर्ड अपनी डिमांडें भेजता है फाइनांस में की हमें इतना पैसा सीवर के लिए चाहिए, इतना पानी की रिपेयर के लिए चाहिए, इतना पैसा ट्यूबवैलों के लिए चाहिए। अध्यक्ष महोदया, लेकिन जो तीनें टीमें खेल रही हैं फाइल-फाइल वो कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल को वापस कर देते हैं। जो अभी मेरे साथी कहते हैं सरकार काम नहीं करना चाहती सरकार ने पिछले 7-8 साल में बहुत काम किया है। अध्यक्ष महोदया, आज यह समस्या मैं खासकर के इस बात पर जोर दे रहा हूं आज ये समस्या खाली तुगलकाबाद विधानसभा की ही नहीं पूरी दिल्ली की

है पिछले 7 साल से दिल्ली जलबोर्ड ने दिल्ली की जनता की पानी की समस्या के लिए काफी काम किया और काफी समस्याओं का समाधान भी किया है लेकिन इस बजट के अभाव में दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारी व दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है उसका मैं आपको एक अध्यक्ष महोदय जीता-जागता प्रमाण दूं दुर्गेश भाई चले गये उन्होंने छोटी-छोटी बातें रखी। पिछले तीन साल से लगातार बिधूड़ी जी बैठे हुए हैं यहां तुगलकाबाद गांव के लिए मैंने 22 करोड़ की लागत से लाइन डाली 22 करोड़ की लागत से पहले वहां हमारा निगम पार्षद नहीं था वो आए दिन एमसीडी वालों को भेज देता था की नहीं काम को बंद करा दो कोई बात नहीं जी। किसी तरह वो एनओसी लेकर वो काम पूरा किया आज हालत यह है कि लाइन डलकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है एक खाली 18 इंच का 3 लाख का वाल्व लाना है 3 लाख का पिछले 6 महीने से लगातार मैं उनसे संपर्क कर रहा हूं लेकिन एक वाल्व लगाने के लिए बजट नहीं है। अध्यक्ष महोदया, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अधिकारियों के ऊपर थोपा कर रहे हैं अधि कारी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं पूरी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एलजी महोदय से यह पूछना अभी पिछले महीने बड़ी परेशानी हुई जो सरकारी टैंकर थे उनकी सप्लाई बंद हो गईं लोगों के मुझे फोन आये मैंने अपने एक्सईएन, एक्सई को पूछा की भई ये सरकारी जो टैंकर हैं ये क्यों खड़े हो गये कह रहे हैं जी पिछले 3 महीने से पेट्रोल पंप वाले की जो हम

डीजल ले रहे थे उसकी पेमेंट नहीं हुई बड़ी कहा सुनी के बाद उनकी पेमेंट हुई वो टैंकर चले। अध्यक्ष महोदया, छोटे-छोटे पार्को में जाकर उद्घाटन करना तो एलजी को याद है आए दिन अखबार में न्यूज जो आप देख रहे हो उनको ये नहीं पता की 1 अगस्त से मैं तो अपनी विधानसभा की बता रहा हूं 1 अगस्त से मेरे 20 टैंकर एसएस वाले जो स्टील के थे 20 टैंकर एक साथ हटा दिये गये बगैर किसी तैयारी के आगे भी उन लोगों को पानी देना है। 20 टैंकर का मतलब अध्यक्ष महोदया 200 ट्रिप मिस होना और 200 ट्रिप मिस होने का मतलब कम से कम 20 हजार लोग उससे इफेक्टेड हुए हैं अध्यक्ष महोदया ये किसकी जिम्मेदारी थी। ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है अगर ये हमें बजट, अभी कह रहे थे बजट, बजट तो सरकार ने पहले ही दे रखा है रिलीज कौन करेगा उसे बात रिलीज करने की है अध्यक्ष महोदया, बड़ा दुख होता है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे क्योंकि अध्यक्ष महोदया, न तो केन्द्र के होम मिनिस्टर को न दिल्ली में बैठे एलजी महोदय को और न ये जो फाइनेंस वाले बैठे हैं उनको दिल्ली के भूगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता की दिल्ली की भौगोलिक स्थिति क्या है और किस विधानसभा की क्या समस्या है सबसे बड़ी दिक्कत तो यह हो रही है। अभी गोयल साहब कह रहे थे चुनाव की बात वास्तव में यह बहुत कड़वा सच है अगर ये लोग भी चुनाव हमारी तरह चुनाव लड़कर आते ना तो इन्हें दिल्ली की समस्याओं का पता होता की किस विधानसभा में पानी के टैंकर की जरूरत है किस

विधानसभा में पानी की लाइन की जरूरत है किस विधानसभा में बोरों की जरूरत है।

माननीया अध्यक्षः कंप्लीट कीजिए।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 16 रि-बोर नये बोर की बात नहीं कर रहा मैं 16 रि-बोर एक साल से पास हुए पड़े हैं एडवाइजरी कमेटी से खाली बजट स्लिप लगनी है अब आप अंदाजा लगाओ जहां वो 16 रि-बोर होने हैं जहां वो बोर डेड हैं वहां की जनता क्या कर रही होगी किस तरह पानी ले रही होगी ऊपर से ये 20 टैंकर और बंद कर दिये 200 ट्रिप और मिस कर दिये तो अध्यक्ष महोदय मेरा तो आपसे इतना निवेदन है एक तो जो हाउस में अधिकारी नहीं आते इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए मैं इस बात से सहमत हूं। दूसरा जिन अधिकारियों की वजह से ये बजट लेट हुआ है आज हमारी पूरी विधानसभा के हर मेंबर चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो परेशान है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें मैं अभी भी यहां बैठे हुए हैं हमारे जल मंत्री जी उनसे भी निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करे जिससे आने वाले समय में यह समस्या न हो और अब मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा की मेरे यहां जो टैंकर हटे हैं किसी भी तरह के लगाओ डीजल के लगाओ पेट्रोल के लगाओ मुझे ये मतलब नहीं है मुझे टैंकर चाहिए कृपया करके हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है जल्दी से जल्दी चाहे एलजी से पूछ

लो अगर वो दे रहा है तो ठीक है नही तो अध्यक्ष महोदय मैं साफ कहना चाह रहा हूं आज पूरी विधानसभा के सामने अगर मेरे यहां टैंकरों की समस्या का पानी का समाधान नहीं हुआ तो कभी भी मैं कल या परसों कभी भी एलजी के घर के आगे अनिश्चित काल के लिए धरना देने के लिए जा रहा हूं मैं जा रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए।

...व्यवधान...

श्री सही रामः ऐसा करेंगे न आधे विधायक फाइनेंस सेक्रेटरी के यहां चले जाना आधे एलजी के यहां।

...व्यवधान...

श्री सही रामः चलो अध्यक्ष महोदय हम जाने के लिए तैयार हैं

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सही रामः आपने ऐसे कठिन उसमें समय में दिया मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का जवाब देंगे।

माननीय जल मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, सभी साथियों ने अपनी-अपनी विधानसभा की समस्या के बारे में बताया और हम भी अपने-अपने क्षेत्रों के विधायक हैं। इसके

अंदर कोई दो राय नहीं की अगर किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा और वहां का जेई, एक्सईएन पब्लिक को बता दे की भी ये तो डेढ़ सौ मीटर लाइन अगर मैं यहां जोड़ दूंगा तो तुम्हारे यहां पानी आ जाएगा तो पब्लिक रोज विधायक के ऑफिस में पहुंचती है रोज। ऐसा नहीं है कि विधायक यह कह दे महीने भर बाद आना और पब्लिक महीने भर बाद आएगी पब्लिक अगले दिन आएगी फिर अगले दिन आएगी फिर अगले दिन आएगी औरतें आएंगी और जो विधायक साथी गांव में रहते हैं वो तो जिस वक्त गांव में पानी आने का समय होता है अगर 4 बजे है पब्लिक 4 बजे उठेगी मोटर चलाएगी पानी नहीं आ रहा है कहेगी चलो विधायक के घर चलो वो 4 बजे विधायक के घर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हम जगे हुए हैं तो तू भी जग और रोज है ये। रामवीर बिधूड़ी जी ने भी गई सारी बातें कही। उन्होंने सहायता करने के विषय में भी कहा कि वो सहायता करेंगे। मैं मोटे तौर पे पहले ये लोगों को बताना चाहता हूं अपने विधायक साथियों को बताना चाहता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों कि समस्या क्या है इसका बैकग्राउंड आप लोग सब समझिये। समस्या इस साल से शुरू नहीं हुई, समस्या पिछले साल से शुरू हुई है। कोरोना के समय में दिल्ली जल बोर्ड की जो आय है जो रेवेन्यू है हर साल की तरह दिल्ली जल बोर्ड के बिलों से आती है। कई लोग ये कहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटा क्यों हो रहा है, घाटा क्यों हो रहा है उस पे भी आयेंगे।

दिल्ली जलबोर्ड की आमदनी जो होती है बिलों के भुगतान से। कोरोना के समय में करीब दो साल न मीटर रीडर्स गये, न बिल जनरेट हुए, और जो थोड़े बहुत बिल जनरेट भी हुए तो लोगों ने पे नहीं किये। मगर दिल्ली जल बोर्ड तो चलता था हर महीने तनख्वाहें भी दी गयी, पंप ऑपरेटर को भी तनख्वाह दी गयी, पंप की मेंटेनेंस भी हुई, सीवर की लाईनें भी डलती रही, जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे चलते रहे, दिल्ली सरकार का खर्चा चलता रहा मगर दिल्ली सरकार की दिल्ली जल बोर्ड की जो आय थी जो बिलों के भुगतान से आती थी वो आय आनी बंद हो गयी, लगभग बंद हो गयी। तो वो पैसा जो दिल्ली जल बोर्ड को कामों के लिये मिला जिसको कैपिटल भी कहते हैं कैपिटल वर्क्स के लिये कहते हैं, सीवर डालने के लिये, पानी डालने के लिये, और आपको तनख्वाहें तो देनी हैं, पंप ऑपरेटर अगर हैं तो उनकी भी तनख्वाह देनी है, अफसरों की तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल आता है हमारा करोड़ों में बिजली का बिल आता है जितने भी पंप सैट चलते हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं, मोटर चलती हैं, ट्यूबवेल चलते हैं हजारों की संख्या में ट्यूब वेल चलते हैं उनका हर महीने का बिजली का बिल देना है तो वो बिजली के बिल का भुगतान ये जो रेवेन्यु साईड के अंदर जो रिकरिंग एक्पेंसिस है वो हमने कैपिटल से दे दिया। ये करीब 1500 करोड़ रूपये के करीब ये पैसा हो गया। अब पिछले साल 2022 के अंदर फाईनेंस विभाग के एक खास अफसर ये कहने लगे कि

भैया ये 1500 करोड़ रूपये कहां गया। हमने बोला कि ये 1500 करोड़ रूपये मैं नहीं था तब दिल्ली जल बोर्ड का बट मैं जानता हूं दिल्ली जल बोर्ड के विषय में क्या हो रहा था वाईस चेयरमैन था मैं उस समय कुछ समय तक। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि ये पैसा जो है हमने इसको तनख्वाहों के अंदर दे दिया। तो फाईनेंस क्या कहता है नहीं नहीं हम नहीं मानते तनख्वाह के अंदर, हम तो ये मान लेंगे कि तुम्हारे पास खातों में 1500 करोड़ रूपये है। अध्यक्षा महोदया वो पैसा नहीं है हमने उनको बता दिया वो पैसा तनख्वाहों में खर्च हो गया यहां पे हो गया, कह रहे नहीं नहीं ऐसे तो तुम कर ही नहीं सकते। ये पैसा तो जो कैपिटल का था ये आप रेवेन्यु में कैसे खर्च कर सकते हो, ये आपके खाते में खड़ा हुआ है 1500 करोड़ रूपये। तो वो खाते में है नहीं मगर ये कह रहे हैं आपके खाते में 1500 करोड़ रूपये हैं तो एक तो इन्होंने 1500 करोड़ रूपये की मार ऐसे मारी दिल्ली जल बोर्ड को, ठीक है जी। अब इन्होंने जितना पैसा हम मांगे इनसे हमने मांगा जी हमें 2000 करोड़ रूपये दे दो अच्छा दो हजार करोड़ रूपये की जरूरत है लाओ सारे प्रोजेक्ट ले आओ। अच्छा अब ये ले आओ। अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, कई महीने निकाल दिये। कह रहे अच्छा लो 500 करोड़ रूपये ले लो। अरे हमने तो 2000 करोड़ मांगे थे नहीं 1500 करोड़ रूपये तो हैं तुम्हारे पास। ये फाईलों में चल रहा है, फाईल फाईल खेल रहे हैं। जो 1500 करोड़ रूपये है नहीं उसको कह कह के आपका पैसा काटा जा

रहा है। तो जब 2023-24 के साल में हम घुसे तो हमारी जो देनदारी है ठेकेदारों की जो काम हो चुके हैं वो करीब 846 करोड़ की देनदारी के साथ हम घुसे जबकि आरई के अंदर जितने पैसे का वादा फाईनेंस डिपार्टमेंट ने किया, आरई के अंदर भी उतना पैसा नहीं दिया उसमें से भी पैसा काट लिया। तो जब आप 2023-24 के अंदर घुसे तो दिल्ली जल बोर्ड माइनस 846 करोड़ के साथ घुसा देनदारी के साथ। अब ये वही ठेकेदार हैं जो 3 महीने काम करते हैं फिर और 3 महीने का काम तो हर 3-3 महीने हर एक एक महीने की इनकी पेमेंट होती है। ज्यादातर वोही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट तीन तीन साल, चार चार साल के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। छोटे ठेकेदार भी होते हैं तो उसी कंस्टीट्यूएंसी के वही ठेकेदार होते हैं जो दोबारा टेंडर लेते हैं। उन्हीं की पेमेंट आपको पुरानी भी करनी है तभी वो नया काम वो करोगे। उपर से ये कंडीशन डाल दी गयी कि पहले आप पुरानी पेमेंट करो फिर आप जो चलते हुए काम हैं उसकी पेमेंट करो फिर आप कोई नया काम आप ले सकते हो। बहुत मेहनत मशक्कत करके कैलाश जी उस वक्त फाईनेंस मिनिस्टर थे उनके दौरान जो है हमने एक मीटिंग की, मीटिंग बड़ी लंबी चली, बड़ी मुश्किल से ये फैसला हुआ कि हमें 2023-24 की पहली किश्त तो दे दो जो हमारी बनती है 25 परसेंट हमारा। वो 2023-24 की पहली किश्त हमें जो है मई जून में मिली, बहुत लेट मिली जबकि शुरू में मिल जानी चाहिये थी। वो पैसा जो हमारा आया वो सारा का सारा पैसा हमारी देनदारी में

चला गया और ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स में चला गया। जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उसका पैसा तो देना है और जो पुराने खत्म हो चुके हैं उसका पैसा देना है सारा पैसा वहां चला गया। और पिछले 6 महीने में आप देख सकते हो कि कोई नया प्रोजेक्ट मोटे तौर पर शुरू नही हो पा रहा क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार पैसा देना चाहती है मगर जल बोर्ड को फाईनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पैसा नहीं दे रहा बात अब वो फाईल चल रही है यहां से फाईल जाती है वो उसके अंदर जैसा कि उन्होंने अपने गोयल साहब ने भी बताया, सही राम जी ने भी बताया, ऋतुराज जी ने बताया कि आप फाईल भेजो, फाईल पे ऑब्जेक्शन लग जायेगी फिर आप उन ऑब्जेक्शनों का जवाब दो फिर ऑब्जेक्शन लग जायेगी। अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्शन लग क्यों रही है और ये ऑब्जेक्शन लगाने के पीछे सिद्धांत क्या है? यही सिद्धांत है कि अफसरों के उपर कंट्रोल चाहिये केंद्र सरकार को। जिस दिन तक अफसरों का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है फाईल पे जितनी ऑब्जेक्शन चाहे लगवा लो। वो तो लगाते रहेंगे क्योंकि जिसके हाथ में कंट्रोल है उसने ही कह रखा है कि तू ऑब्जेक्शन लगाये जा पैसा मत दे, दिल्ली को पूरा बर्बाद कर। ये झगड़ा है जो ट्रांस्फर पोस्टिंग का झगड़ा है, सर्विसिज़ का झगड़ा है, जो कहते हैं कि हमारे को अफसर दे दो, हमारे को अफसर दे दो क्यों चाहिये इन्हें अफसर? भई ये कोई मंत्री कोई न

हैं इनको क्यों चाहिये, मंत्री हम हैं अफसर इन्हें चाहियें, क्यों चाहिये इन्हें। क्योंकि इन्हें ये काम कराने हैं उनसे। क्या काम करना है कि कोई काम नहीं करना, ये काम कराना है उनसे, ये चल रहा है। जब डायरेक्शन उपर से ये है कि आप काम न करें, तो वो क्या करेंगे, ये चल रहा है। अब बात आती है कि क्या उन अफसरों को आप सिर्फ इस बहाने से माफ कर सकते हैं क्योंकि उनके उपर उपर से दबाव है इसलिये वो काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। उन अफसरों की जवाबदेही है। जैसे मंत्रियों की जवाबदेही है वैसे अफसरों की जवाबदेही है भई वो तनख्वाह ले रहे हैं काम करने के लिये, काम रोकने के लिये तो नहीं ले रहे। वो जो है अध्यक्षा महोदया वो करना पड़ेगा। मैं मोटे तौर पे जो है कुछ चीजें लिख के लाया था तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बता दिया इस साल के बजट के बारे में। कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि भई जल बोर्ड घाटे में क्यों है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि जल बोर्ड की आमदनी कहां से होती है और जल बोर्ड का खर्चा कहां पे होता है। जल बोर्ड की आमदनी तो बिलों से होती है बस। मेरे इतने सारे साथी बैठे हैं कोई एक साथी भारतीय जनता पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, वो ये कह दे कि भैया मेरी कंस्टीट्यूएंसी में उतना ही खर्चा करियो जितने बिल आयें तेरे पास, मैं उसका करने के लिये तैयार हूं। आप मुझे बता दो इस असेम्बली के अंदर बता दो कि मेरे यहां अगर 50 करोड़ रूपये आमदनी हो जल बोर्ड की तो मेरे यहां एक साल में 50 करोड़

रूपये ही खर्च करो हम तो तैयार हैं। आमदनी तो न के बराबर होती है खर्चा तो पूरा होता है। मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि खर्चा क्या होता है। जल बोर्ड के अनऑथोराइज कालोनिज़ की सिर्फ अगर हम बात ले लें तो 2014-15 में जब ये सरकार बनी तो 985 कालोनी थी जिनके अंदर वाटर नेटवर्क था। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2014-15 तक 985 कालोनियों में ये वाटर नेटवर्क था, 22-23 पिछले साल में हमने 1630 कालोनियों के अंदर वाटर नेटवर्क डाल दिया इसमें पैसा खर्च होता है। वाटर प्रोडक्शन बिधूड़ी जी पूछ रहे थे वाटर प्रोडक्शन कितनी बढ़ी इससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी एक दो साथी ने भी पूछा कि वाटर प्रोडक्शन कितनी बढ़ी। हरियाणा से पानी नहीं बढ़ा, यूपी से पानी नहीं बढ़ा, कहीं से पानी नहीं बढ़ा जो इंटर्नल सोर्सिज से दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वाटर प्रोडक्शन बढ़ायी है वो है 2014-15 में हम 861 एमजीडी पानी जनरेट करते थे आज की तारीख में हम करीब हजार एमजीडी पानी जनरेट कर रहे हैं हमने बढ़ाया है। अपने इंटर्नल सोर्सिज से हमने बढ़ाने की कोशिश की है मगर जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है दिल्ली की उस स्पीड से वो पानी बढ़ना मुश्किल है जब तक हमारा कोई पड़ोसी राज्य जो है हमें पानी नहीं देगा तब तक मुश्किल है। अनऑथोराइज कालोनी सीवर के अंदर अगर आपको यमुना साफ करनी है तो आपको सीवर लाईन डालनी पड़ेगी खासतौर से अनऑथोराइज कालोनी के अंदर डालनी पड़ेगी क्योंकि अनऑथोराइज कालोनिज़ के अंदर जो

मल रोज उत्पन्न होता है वो घूम फिर के किसी आपके नाले में जाता है, वो नाला घूम फिर के यमुना के अंदर जाता है फिर वो यमुना को प्रदूषित करता है तो जब तक आप अनऑथोराइज कालोनिज़ के अंदर सीवर लाइन नहीं डालेंगे तब तक आप यमुना साफ नहीं कर सकते। तो अनऑथोराइज कालोनिज़ के अंदर सीवर डालने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया जब 2014-15 में उनकी सरकार बनी तो 220 कालोनियों के अंदर सीवर लाईन थी और पिछले साल तक हम 747 कालोनियों के अंदर सीवर लाईन डाल चुके हैं। ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया आप सोचिये जब से भारत आजाद हुआ 2014-15 तक 220 और जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तब से तब से अब तक 747 जो है इसको हमने पहुंचाया है। अब सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो सीवर ट्रीटमेंट जितनी सीवर ट्रीटमेंट होती थी दिल्ली में वो थी 373 एमजीडी। अध्यक्षा महोदया, जितना पानी हम लोग देते हैं उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना सीवर जनरेट होता होगा। दिल्ली के अंदर हमारा अनुमान है करीब 792 एमजीडी मतलब 792 मिलियन गैलन पर डे सीवेज वेस्ट जनरेट होता है और उसमें 2014-15 में मात्र 373 मिलियन गैलन पर डे हम ट्रीट करते थे यानि कि करीब 600 माफ कीजियेगा यानि कि करीब 400 एमजीडी सीवर वेस्ट हम यमुना के अंदर डालते थे। आज की तारीख के अंदर पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं

पिछले साल का डेटा कह रहा है कि हमने ये जो Quantity of sewage treated 570 एमजीडी कर दिया है हमारी कैपेसिटी इस साल दिसम्बर में 814 एमजीडी हो जायेगी यानि कि जितना हम सीवेज जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जायेगी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि कम से कम हमारे पास इतने र्प्याप्त साधन हैं कि जितना सीवर जनरेट होगा उतना हम लोग ट्रीट करेंगे। अब अध्यक्ष महोदया ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं इतनी सारी कालोनिज़ के अंदर आप अनऑथोराइज कालोनिज़ के अंदर सीवर डाल रहे हैं, पानी की लाईनें डाल रहे हैं जो पुराने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे उनकी क्वालिटी जो थी जो उसकी आउटफाल की क्वालिटी थी वो 30/50 की बोली जाती है अब 10/10 की क्वालिटी के अंदर हम सारे के सारे एसटीपीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं तो इसके लिये हजारों करोड़ रूपया चाहिये आपको, हजारों करोड़ रूपये। इस साल का बजट मैं आपको बता रहा हूं जोकि कम पड़ रहा है वो है करीब 4600 करोड़ रूपया इस साल का बजट है मतलब करीब 4600 करोड़ रूपया हम लोगों का अनुमान है कि हम लोग माफ कीजियेगा 4839 करोड़ का हमारा बजट है और हमारी जो आमदनी होती है दिल्ली जल बोर्ड की वो मोटा मोटा हजार 12सौ करोड़ के बीच में होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप साढे 4 हजार करोड़ रूपये खर्च करेंगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, सीवर लाईनें डालेंगे, पानी की लाईनें डालेंगे, ट्यूबवेल डालेंगे, नये नये सोर्सिज खोल रहे

हैं आप लेक्स बना रहे हैं साढे 4 हजार करोड़ रूपये आप खर्च कर रहे हैं 12 सौ करोड़ रूपये आप कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हर साल जो है एक debt के अंदर जायेंगे। और जितनी भी पब्लिक सर्विसिज़ हैं वो debt में जाती हैं ये कोई profit earning centre नहीं है दिल्ली जल बोर्ड, कोई विधान सभा का आदमी बता दे कि भई हमारे अगर आप मान लें कि साढे 4 हजार करोड़ रूपये खर्च होता है तो एक विधान सभा के अनुपात के अंदर बहुत बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसके हिसाब से जल बोर्ड की कमाई नहीं है। अब बिधूड़ी जी ने कई सारी बातें कही। उन्होंने बोला कि हिमाचल के अंदर एमओयू क्यों नहीं साईन हुआ, हो गया, इनको पता है। अब सवाल ये आता है कि वो एमओयू 2 साल पहले साईन हो गया वो पानी भी हमारे पास अध्यक्ष जी महोदय और सारे विधायक साथी समझें कि इसके अंदर कला कहां पे है और कलाकार कहां पे बैठा है। हथिनी कुंड बैराज जहां से पानी आया और दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति हुई वहां पे कई राज्यों का पानी का डिवीजन किया हुआ है केंद्र सरकार ने सेंटर वाटर कमीशन ने। दिल्ली के हिस्से का पानी हम दिल्ली ले आते हैं कैनाल से, हिमाचल के हिस्से का पानी हिमाचल का है, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलता है वहां से। अब वहां जो इंट्रस्टिंग बात ये है कि जितना पानी का जो हिस्सा हिमाचल का है हिमाचल चाह के भी वो पानी हिमाचल में नहीं ले जा पाता क्योंकि हिमाचल उंचाई पे है हथिनीकुंड नीचे है प्लेन

में है। तो हिमाचल प्रदेश के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि वो अपने हिस्से के पानी को हिमाचल ले जा सके तो लिहाजा वो पानी वहीं पे छोड़ देता है। और वो पानी हरियाणा को मिल जाता है हिमाचल के हिस्से का। तो हमने हिमाचल प्रदेश से एमओयू किया कि भई तुम्हारा पानी यहां पे हथिनीकुंड पे हम तुम्हारा पानी खरीद लेंगे तुम्हें पैसे की आमदनी हो जायेगी दिल्ली सरकार पैसा दे देगी आप अपने हिस्से का पानी हमें दे दो। हिमाचल तैयार हो गया। उनको लगा पैसे की आमदनी हो जायेगी अब समस्या किसको हुई हरियाणा को। जो हिमाचल के हिस्से का पानी मुफ्त में ले रहा है तो हरियाणा ने मना कर दिया कि भई पानी तो ले लोगे पर रास्ता तो हम ही देंगे हम रस्ता ही नहीं देंगे तुम्हें। हमारी कैनाल है वहां पे हमारी सीएलसी और डीएसपी दो कैनाल हैं जिसपे हमारा पानी आता है मगर इसके बावजूद हरियाणा का ये एतराज है कि भई ठीक है कैनाल तुम्हारी है मगर इजाजत तो हम से लेनी है। सिर्फ हरियाणा के पेट में दर्द इतना है कि पानी तो तुम खरीद लोगे ले जाओगे कैसे हम ले जाने नहीं देंगे। अब बिधूड़ी जी करो इसका सॉल्यूशन। अब दूसरी पे आते हैं। जो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा एमओयू हुआ वो बड़ा अच्छा एमओयू था। उत्तर प्रदेश के साथ हमारा एमओयू ये हुआ कि हमारे ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट हैं 140 एमजीडी के ट्रीटमेंट प्लांट हैं। बल्कि अब तो अपग्रेड हो रहा है नयी क्वालिटी का साफ पानी निकलेगा। कोंडली वाला भी है। हमारा ये उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव था कि हम

आपको ट्रीटिड वाटर दे देंगे क्योंकि आपको तो खेतों में देना है तो वो आपके लिये और ज्यादा न्यूट्रिशियस है और ज्यादा आपको फायदा है उस पानी से और जल्दी ग्रोथ होती है। और उसकी एवज़ में आप हमें साफ पानी दे दो। ये मामला हमने नीचे नीचे चलाया अफसरों के पास। और वो मामला सही चल रहा था। फिर ये बात हमने अपने एलजी साहब को बता दी इनसे पहले वाले जो थे। उन्होंने चिट्ठी योगी आदित्य नाथ जी को लिखी। जिस दिन योगी आदित्य नाथ जी को पता चला उन्होंने वो स्कीम वहीं की वहीं रोक दी, आप करा लो। मैं आभारी रहूंगा आपका। अब तीसरी बात। अब बिधूड़ी जी आप अच्छे आदमी हो आप हरियाणा, यूपी में कहां परेशान होओगे मैं आपको एक आसान चीज दे देता हूं मैं आसान सी चीज दे देता हूं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आप कैनाल बनाईये और।

माननीय जल मंत्री: कैनाल बनी हुई है। ठीक है अब सुनिये।

माननीया अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बैठिये।

माननीय जल मंत्री: ठीक है। अब क्या है अब बिधूड़ी जी। अब क्या है बिधूड़ी जी इसके लिये हमें कोई बिधूड़ी जी ये सोच रहे हैं कि ये नये कैनाल की बात में इनको फंसा दूं ये कैनाल बनाते रहेंगे तब तक तो टर्म एक्सपायर हो जायेगा ऐसा नहीं है कैनाल बनी हुई है उसी कैनाल में आना है पानी। कैनाल बनी हुई

है अब मेरी बात तो मान लो अब दे दो न। कैनाल बनी हुई है। आप दे दो न। चलो।

माननीया अध्यक्ष: बिष्ट जी।

माननीय जल मंत्री: आप सुनिये, अब।

माननीया अध्यक्ष: बहुत हो गया।

माननीय जल मंत्री: भई आपने ऑफर दिया था इसलिये मैंने आपका ऑफर मान लिया। आप ही ने दिया था। अब तीसरी चीज पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप हिमाचल जाओगे, हरियाणा जाओगे, यूपी जाओगे इतना टाईम लगेगा आप एक किलोमीटर दूर एलजी साहब के यहां क्यूं नहीं चल लेते मेरे साथ। एक किलोमीटर पे ही है। उनको कह दो कि ये जो अफसरों ने जिन्होंने पैसा रोक रखा है वो पैसा न रोकें काम पूरा हो जायेगा। इतना दूर नहीं जानना पड़ेगा। पडोस में है। टाईम ले लो मैं और आप चलते हैं। अभी चलते हैं। यूपी वाले से कब मिलेंगे, हरियाणा वाले से कब मिलेंगे, पास के पास में। आपकी तो चलती है इतनी। सिर्फ इतना कह दो कि दिल्ली सरकार के पास जो दिल्ली के टैक्स वालों का पैसा है हम केंद्र से पैसा नहीं मांग रहे बिधूड़ी जी, न हम किसी और से पैसा मांग रहे हैं हम दिल्ली सरकार के पास दिल्ली के टैक्स वालों का जो पैसा है वो मांग रहे हैं। वो देने के लिये तैयार नहीं हैं, हमारा पैसा हमीं को देने के लिये तैयार नहीं हैं। ये चीज आप एलजी साहब को बता दो तो हमारा काम हल हो जायेगा। करेंगे?

माननीय नेता, प्रतिपक्षः आप हिसाब तो दे दो फिर आगे भी दिलवा देंगे। वो तो दे दो हमारा हिसाब। हिसाब देंगे नहीं आप और पैसा मांगते जाओगे तो ये उचित नहीं है।

माननीया अध्यक्षः बिधूड़ी जी बैठिये। मंत्री जी।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्षा महोदया मैं ये पूरी की पूरी जो बातचीत थी देखिये ये बड़ा अच्छा हुआ कि इतने सारे विधायक साथियों ने अपना दर्द बताया। रामवीर बिधूड़ी जी ने भी अपना दर्द बताया, ये भी बहुत परेशान हैं फंड से। इनके बीजेपी के साथी नहीं जानते होंगे। ये भी बहुत परेशान हैं फंड से ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से किसी तरीके से इनको कुछ बजट जो है दिल्ली जल बोर्ड का मिल जाये और सब लोग परेशान हैं। मगर इस बात को समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली जल बोर्ड इकलौता विभाग नहीं है जिसको परेशान किया गया है। हमारी पीटिशंस कमेटी के अंदर वो मामले आये थे जिसके अंदर अध्यक्षा महोदया जैसे हमारे एक ऋतुराज भाई ने भी बताया ठीक एमसीडी के चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी के अंदर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को भगा दिया गया। आप सोचिये दिल्ली सरकार के अस्पतालों में क्या हालत हुई होगी जब बीमार लोग ओपीडी में पहुंचे होंगे और पर्ची बनाने वाले लड़के कई महीनों तक गायब थे, इन्होंने ऐसे सताया है दिल्ली के गरीब लोगों को। दीवाली से पहले पीटिशन कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गरीब लोगों के वीडियोज़ हमने असेंबली कमेटी के

अंदर चलाये थे वो गरीब गरीब लोग कह रहे थे बेटा तीन तीन चार चार महीने से पेंशन रोक रखी है सरकार ने। वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने रोक रखी थी ये जानते कोई नहीं, ये तो जानते हैं वो कौन अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो फ्री टेस्ट होते थे जो कंपनी फ्री टेस्ट करती थी उसको पैसे रोक दिये, उन्होंने टेस्ट रोक दिये दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट होने बंद हो गये महीनों तक। कैसे हुआ था, सब जानते हैं कैसे हुआ था। इनको भी मालूम है। आपने पेंशन रोक दी, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर भगा दिये, मोहल्ला क्लिनिक के डाक्टरों का मेहनताना बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट जो होते थे वो बंद कर दिये। ये अपने आप ही कोई न हो रहा है और जो अधिकारी कर रहे हैं उनके उपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही एक बार मुझे पता चला कि ड्यूसिब का एक रैन बसेरा देखने एलजी साहब गये और वहां पे एक चदर गंदी थी तो एलजी साहब ने उस सीईओ को निकाल दिया सुबह। रात को ही आर्डर कर दिया, सीईओ सस्पेंड। और एक महीने बाद उस रैन बसेरे को डीडीए ने उड़ा दिया। मतलब जिस रैन बसेरे की एक चदर से एलजी साहब को इतना एतराज था आपने उस पूरे रैन बसेरे को ढहा दिया और आपके दिल में दर्द नहीं आया। क्योंकि मामला वो रैन बसेरे का नहीं था मामला उस अधिकारी का था उस अधिकारी को हटाना था तो आपने हटा दिया। तो जब आप एक चदर का बहाना लेकर एक अधिकारी को

हटा सकते हो तो जहां पे आपके मोहल्ला क्लिनिक को ठप्प किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों को तीन तीन महीने तक पेंशन के लिये चक्कर कटाये जा रहे हैं, जल बोर्ड को आप पूरा का पूरा जो है ठप्प करना चाहते हैं क्या एलजी साहब को दिख नहीं रहा होगा ये। एलजी साहब को दिख रहा है। कौन कर रहे हैं ये भी पता है। सबको सबकुछ पता है। इसीलिये इनको अफसरों का कंट्रोल चाहिये। लड़ाई तो ये है इसीलिये इनको अफसरों का कंट्रोल चाहिये क्योंकि अफसरों से इनको ये काम रूकवाने हैं दिल्ली में, ये लड़ाई है अध्यक्षा महोदय। बहुत अच्छी चर्चा हुई, सब लोगों ने इसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट किया, विपक्ष से भी कई साथियों ने बहुत अच्छा बोला मोहन सिंह बिष्ट जी मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो करावल नगर का सोनिया विहार का जो सीवर रूका हुआ है उसके साथ दिल्ली जल बोर्ड के करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट रूके हुए हैं क्योंकि पैसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं आप चाहे दिल्ली जल बोर्ड के मिनट्स चैक कर लेना। ऐसा नहीं है कि आपके लिये हमने रोका हुआ है पैसा नहीं है आप पैसा दिलवा दो आपको दिलवा देंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्टः unauthorized कालोनिज़ का क्या हुआ?

माननीय जल मंत्रीः पैसा नहीं है। सीवर के अंदर नहीं है पैसा। मैं आपको बता रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय जल मंत्रीः ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बिष्ट जी इस विषय पर चर्चा हेतु मेरे पास दर्जन से भी ज्यादा सदस्यों की रिक्वेस्ट आई थी और सबकी पीड़ा समान ही है कि बजट नहीं है, काम रूके पड़े हैं अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया और अध्यक्ष जी ने इससे पहले भी एक संबंधित विषय जल बोर्ड का इसी तरीके का याचिका समिति में भेजा हुआ है और आज पूरे सदन की भावना को देखते हुए, पीड़ा को देखते हुए मैं ये निर्देश देती हूं कि याचिका समिति इस विषय पर मुझ से पूर्व अध्यक्ष जी ने जो विषय भेजा है दोनों विषयों की जांच करे और एक महीने के अंदर रिपोर्ट सदन पटल पर पेश करे। अब सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये जो है लंच तक के लिये स्थगित की जाती है लंच के बाद दोबारा सदन होगा।

(सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए लंच हेतू स्थगित की गईं)

सदन अपराह्न 4.17 बजे पुनः समवेत हुआ ।

माननीया अध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं ।

माननीया अध्यक्षः अब श्री संजीव झा माननीय सदस्य विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने की परमिशन लेंगे।

श्री संजीव झाः अध्यक्षा महोदय मैं विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूँ।

माननीया अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा श्री संजीव झा को विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने की परमिशन दी गई है। अब श्री संजीव झा अपना विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे रूल-66 के अंतर्गत आपने अपना परमिशन दिया। मैं विषय पर आऊं इससे पहले चूंकि जब मैं सुन रहा था बिधूड़ी जी को तो बिधूड़ी जी 2024 की बात कर रहे थे। आज चूंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य तिथि भी है और अटल जी ही कहा करते थे, उन्होंने लिखा था कि जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने, ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है, ये जो आपका अहंकार है, ये अहंकार

पहले जो लोग थे उनके भी थे उनके भी टूटे और आपके भी टूटेंगे क्योंकि किसी ने ठीक ही लिखा है कि अहंकार और शराब का नशा एक जैसा ही होता है। खुद को छोड़कर बाकी सब को पता चल जाता है कि चढ़ी हुई है। तो ये जो अहंकार चढ़ा हुआ है ये अहंकार टूटेगा। खैर अब मैं विषय पे आता हूँ। अध्यक्ष महोदय एक बहुत गंभीर विषय है जिसके कारण मैंने आपको रूल–66 में परमिशन आपसे मांगा था आज। दिल्ली विधान सभा ने डार्क डीएआरसी फैलोशिप में कुछ बच्चों को नियुक्त किया था और ये नियुक्त अपनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। ये प्रक्रिया क्या थी कि पहले जनरल पर्पज कमेटी जो है हमारा सामान्यकार्य संबंधी जो कमेटी है उसमें चर्चा हुईं उस चर्चा का रिपोर्ट इस सदन में लाया गया। इस सदन ने उसकी अनुशंसा करी और अनुशंसा के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया। फाइनेंस सेकेट्री ने उसके लिए बजट अप्रूव किया और उस बजट अप्रूव होने के बाद फैलोज की नियुक्ति हुईं लेकिन अभी आनन–फानन में उस सबकी नियुक्ति को डिस्कन्टीन्यू कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह से आनन–फानन में उसको रद्द करना ये सदन की भी अवमानना है चूंकि ये जो सलैक्शन प्रोसेस था ये सलैक्शन प्रोसेस पूरी तरह से एक पारदर्शी प्रोसेस था, जिसमें दिल्ली के ये कहूं कि देश का सबसे मानक संस्था दिल्ली टैक्निकल यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली टैक्निकल यूनिवर्सिटी ने पहले उसकी विज्ञप्ति निकाली। उस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि जिसको एक experience

criteria रखा गया कि एक्सपीरियन्स क्या होना चाहिए, क्वालीफिकेसन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियन्स के साथ–साथ एक ब्रीफ सबसे मांगा गया। लगभग 2900 लोगों ने उसको एप्लाई किया तो जिस एक्सपीरियन्स और उसकी ब्रीफ को देखकर के कुछ को शोर्टलिस्ट किया गया। उसको शोर्टलिस्ट करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस था कि सबसे एक कुछ कोश्चंस देकर के एक रिटन उनको लोगों से सब्मिशन मांगा गया। उसके बाद उसमें फिर कुछ लोगों को सलैक्ट किया गया और बाद में फिर दिल्ली टैक्निकल यूनिवर्सिटी के गाइड लाइन में कुछ एक्सपर्ट बैठकर के उन सबका इन्टरव्यू लिया और उस इन्टरव्यू में जो लोग सलैक्ट हुए उनको फैलोशिप दिया गया। अब ये जो फैलोज थे ये फैलोज रिसर्च स्कोलर थे। आईआईटी दिल्ली या अलग–अलग जो मानक संस्था है वहां से पढ़ के आये थे। ना केवल देश बल्कि विदेश से, कोई आयरलैण्ड से कोई यूके से, वर्ल्ड के अलग–अलग वहां जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग वहां से पढ़के बच्चे आये थे, उनको ये नियुक्ति दी गई और ये जो नियुक्ति थी इस नियुक्ति में कुछ जिम्मेदारी जो विधान सभा में काम कर रहे हैं उनको उसमें मदद करने के लिए दी गईं अलग–अलग एमएलऐज को जहां जो बैठे हुए हैं सदन में मुझे भी और बाकि सब एमएलऐज को दी गईं कुछ को मंत्रालय में दी गई कि मंत्रालय के काम में उसको ऐसिस्ट किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि ये दो तरह का प्रोसेस था। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे यहां जो फैलोज थी उसको हमने पूछा कि आपकी क्या

क्वालीफिकेशन है और आप कैसे आये, और क्यूं आये, क्या आपके आने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? तो वो लड़की बता रही थी कि सर मैंने पीएचडी करा हुआ है। पीएचडी के बाद फिर हमने अलग-अलग जो वर्ल्ड इंडिया के पॉलिटीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम किया। लेकिन हम एक्जीक्यूटिव कैसे काम करता है मैं जानना चाहता था और ये ही कारण था कि हम जब ये फैलोशिप आये तो मैं उस फैलोशिप को हमने ज्वाइन किया। अब समझिये कि एक तरह से हम एक वो नया पौधा तैयार कर रहे हैं जो पौधा जनतंत्र को जनतांत्रिक व्यवस्था को, पॉलिटीकल एक्जीक्यूटिव कैसे काम करता है और उस काम को कैसे बेहतर किया जाए। चूंकि ये भी आज देश की एक विपदा है कि हम कहते हैं एक तरफ कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ हमारे यहां ज्यादा परसेंटयूथ हमारे यहां है, यूथ कंट्री हैं और उस यूथ कंट्री को जो गवर्न कर रहा है वो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। एक जबरजस्त मिस मैच है कि जो चाहिए यूथ को, जो गवर्नेंस में है उनको नहीं पता क्या चाहिए। वो जो दे रहे हैं उनको यूथ को जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब ये बच्चे आ रहे हैं तो वो बच्चे हम जैसे लैजिसलेचर को ना केवल अवेयर कर रहे हैं, बल्कि हमारे काम काज को भी और आसान कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक हमारे काम को परुैक्शन की तरफ ले जा रहे थे और वो उस तरह से समझ रहे थे कि वास्तव में एक ये जो पॉलिटीकल एक्जीक्यूटिव्स का काम कैसे होता है। लेकिन जिस तरह से उन सबको हटाया गया है

इसके पीछे दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य तो ये था कि किसी तरह से दिल्ली सरकार और इस विधान सभा के काम को हैम्पर किया जाए और दूसरा मंशा था कि बदनाम किया जाए और मैं दोनों पे आता हूँ। आप एक बात समझिये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज हमारे एमएलए ऑफिस में ये मेरे नहीं विपक्ष के साथियों के ऑफिस में भी जितनी मीटिंग्स होती है, मीटिंग का कॉर्डिनेशन, मीटिंग का मिनट्स, उसका फोलोअप, उसकी ड्राफ्टिंग ये सारा काम बैठ के वो लोग कर रहे थे। बल्कि कई बार उनके अपने भी अच्छे इनपुट होते तो उस इनपुट को हम लोग इन्क्लूड करते थे। दूसरा कि इन बच्चों के जरिये विधान सभा के बहुत सारे रिसर्च हुआ। विधान सभा के बहुत सारे काम उस काम के एक्जीटयूशन में आसानी होती थी। मंत्रालय में जो काम हो रहा है उसमें मंत्री के साथ मिल के उसके काम को आसान करने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सरकार जो ये डिलीवरी सिस्टम है इनका ये सिस्टम में ऐसे कौन–कौन से ingredients हैं जिस ingredients को अगर हम हैम्पर कर दें तो डेवलपमेंट का मॉडल प्रभावित हो जाए। चूंकि ये इनको अरविन्द केजरीवाल जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बहुत घबरा रहे हैं। चूंकि इनका अब ये जो ऊवाह का जो तंत्र है उस तंत्र पे ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब भारी पड़ रहा है और ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री 20 साल तक मुख्यमंत्री थे और जब हम लोग

गुजरात का चुनाव इस बार लड़ने गए तो प्रधानमंत्री को एक टिन टप्पर के टैम्प्रेरी स्ट्रैक्चर में ही सही बैठके उनको कहना पड़ा कि हम भी अब मॉडल स्कूल बना रहे हैं। तो बेसिकली उनको लगता है कि दिल्ली में अगर ये ठीक से काम करते रहे तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये गवर्नेंस, तो सवाल इनके होते रहेंगे। तो इसको यहां हैम्पर कर दो, 'न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी।' तो उस मॉडल को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। वो किसी ने लिखा है कि :

''हमारी अफवाहों का धुंआ वहीं से उठता है
जहां हमारे नाम से आग लग जाती है।''

तो अरविंद केजरीवाल के नाम से जो आग लगती है तो उसका वो धुंआ है।

दूसरा जो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह बदनाम किया जाए और उसमें मेरे अपने प्रिविलेज का भी बिइंग ए मेम्बर ऑफ दिस हाउस हमारे अपने प्रिविलेज का भी हनन करने की कोशिश की है और इसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता शामिल थे। इनके बहुत सारे नेताओं ने ऐसे झूठ-मूठ का एक लिस्ट निकाला, जो लिस्ट न तो मंत्रालय से आई, न लिस्ट वो विधान सभा से था लेकिन उसको सरकारी लिस्ट मानकर उसमें अनाप-शनाप नाम जोड़े गये। मेरे दो-दो भाइयों का नाम जोड़ा गया है उसमें और उन्होंने कहा कि संजीव झा के दो भाई डीएआरसी के फैलोज हैं।

हमने सबको डेफमेशन का नोटिस किया है। एक शहजाद पूनावाला इनका प्रवक्ता है, दूसरा प्रवेश वर्मा जी सांसद हैं, इसी दिल्ली की जनता ने उनको चुना है कि जनता के लिए काम करें बट अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं वो। तीसरा बेपेंदी का, बिना पेंदी का लोटा है वो कपिल मिश्रा। इसी तरह से बहुत सारे लोग. हां, ये भी हंस रहें, जानते हैं, ये जानते हैं वहां से भी पलट सकता है, अब पलटा ही था, जब इधर था पता है इनको इसीलिए हंस रहे हैं, सच्चाई जानते हैं। मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने एक लिस्ट निकाला और उसमें मेरा ही नहीं, अभी बंदना जी बता रही थी कि एक किसी लड़की का नाम जोड़ दिया कि इनके वो रिलेटिव है.. कोई कविता झा। हमारे दिलीप भाई, चीफ व्हिप हैं, इनके साथ जो लोग पॉलिटिकल काम करते हैं उनका नाम कई लोगों ने चलाया।.. दुर्गेश पाठक जी की मिसेज फैलोज थीं, शादी बाद में हुई है। कम से कम, देखिए मुझे लगता है..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप किसी को सफाई न दें।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः और इन्हीं के फैलोज थीं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः संजीव जी, कंटिन्यू रखे।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः देखिए सदन के जरिए ये जानना भी जरूरी है कि इनको, और ये फैलोज भी इन्हीं के थे और ये ही कई बार तारीफ करते रहे हैं। तो मेरा ये कहना है और ये सदन के जरिए दिल्लीवालों को और देश को जानना भी जरूरी है कि किस तरह से अफवाह का तंत्र भारतीय जनता पार्टी चलाती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किसी भी बात पर दिल्ली या देश की जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा, जीएनसीटीडी बिल के जरिए अभी कानून बनाया है। जन-संघ के समय से ये कहते थे दिल्ली को पूरा राज्य बनना चाहिए और आज मुकर गये। तो भला इन लोगों का, इन पार्टियों का जनता कैसे भरोसा करे? तो इनका एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका काम है अफवाह फैलाना। तो हमने न केवल डेफमेशन किया है बल्कि मैंने, कोर्ट भी जा रहे हैं चूंकि गवर्मेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्ज किया गया है, ये 120-बी का भी मसला बनता है। तो हम कानूनी कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन मैं ये मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये इस सदन की अवमानना इसलिए है कि 2018-19, 19-20, 20-21 में फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन फैलोज को पहले से ही सैलरी देता रहा है तो अगर तीन फाइनेंशियल ईयर में आपने सेंक्शन दिया, किस बिना पर दिया आपने? तो अगर तीन फाइनेंशियल ईयर में आपने सैलरी दी तो आज ये इलीगल कैसे हो गया? और ये चूंकि सदन के पटल पर

ये रखा गया था, सदन ने इसको अप्रूव किया था इसीलिए ये सदन की भी अवमानना है।

तो मेरा दो निवेदन है अध्यक्ष महोदय। पहला कि जिन अधिकारियों ने ये इसको डिस्कंटिन्यू किया है या कराया है उन सभी अधिकारियों पर अवमानना होनी चाहिए और वो तमाम लीडर्स, जिन लीडर ने इस झूठ को फैलाया है उन सभी लीडरों पर भी अवमानना होनी चाहिए और सदन से कठोर से कठोर मैसेज जाना चाहिए ताकि कल कोई दिल्ली विधान सभा का अवमानना, इस विधान सभा के सदस्यों का अवमानना करने की हिम्मत ना करें। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय आज मैंने आपसे रूल-66 के अंतर्गत आपसे इस परमिशन को हमने मांगा था। मुझे उम्मीद है कि आज ये सदन इस गंभीर विषय पर सोचकर के सभी अधिकारियों पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने सदन की अवमानना या सदन के सदस्यों की अवमानना करने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई हो पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः सुरेंद्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, आपने डीएआरसी पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आज डीएआरसी फैलो के चर्चा आदरणीय हमारे संजीव झा लेकर आये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं 24 दिसंबर, 2021 को 2989 अपलीकेशन आईं जिसमें ये फैलो नियुक्त किये जाने थे। उनमें से केवल 3 परसेंट लोग सेलेक्ट

किये गये। उनकी क्वॉलिफिकेशन देखकर, उनके टेस्ट कर और उनको इंटरव्यू के आधार पर उन्हें जो भी डीटीयू की गाइडलाईन्स थी उसके आधार पर वो सेलेक्शन करने का काम किया गया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे फैलोज थे वो दिल्ली सरकार को चलाने में पूरा अपना सहयोग करते थे। तमाम सरकार के विधायक या विपक्ष के विधायक भी उनका कार्य करने में उनका पूरा सहयोग करते क्योंकि विधायक जी को बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर वो अपना समय देते थे लेकिन जो फैलोज थे हमारे निश्चित तौर से हम सभी विधायकों को वो तमाम कार्यों में सहयोग करते थे। कोई चिट्ठी लिखनी है, कोई लेटर लिखना है तो निश्चित रूप से वो लिखता था। वो इसको रिसीव कराने भी वो मंत्रालय जाता था या हम किसी के पास भेजते थे, किसी डीएम, एसडीएम के पास भी उसको भेजने का काम करते थे क्योंकि वो पढ़ा लिखा हमारा फैलो था। तो वो साइंटिस्ट भी थे, कुछ उसमें पीएचडी भी थे। तो कहने का तात्पर्य सरकार को चलाने में और हम सबके काम को देखने में उसका बड़ा एक सहयोग मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखती थी कि इनके विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विधायकों को, सरकार का नाम चल रहा है। आदरणीय सी.एम. साहब का जो बिजली, पानी पर जो उन्होंने काम किया है, देश में विश्वविख्यात के नाम से आदरणीय सी.एम. साहब ेमस हुएं। आज हम सब लोग विश्वविख्यात मुख्यमंत्री से

उनको कहते हैं कि भई उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ख्याति पाई हैं तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, एल.जी. बौखला गये हैं क्योंकि उनका, अमित शाह के वो चेले एल.जी. हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन ये दिल्ली सरकार का पैसा है लेकिन ये जनता का पैसा जनता के ऊपर दिल्ली सरकार खर्च करने का काम करती है और दिल्ली की जनता जब टैक्स देती है या जीएसटी देती है या इन्कम टैक्स देती है तो निश्चित तौर से उसी पैसे को हम फैलो पर खर्च करते थे न कि, हम सेंट्रल गवर्मेंट से कोई पैसा नहीं लेते थे। दिल्ली का पैसा दिल्ली के द्वारा दिल्ली की जनता के द्वारा दिल्ली के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा खर्च करने का मौका मिलता था। क्योंकि यदि हमारे पास स्टाफ ठीकठाक होगा तो निश्चित तौर से हम जनता के क्षेत्र के लिए, सरकार को चलाने के लिए हमें यदि अच्छे फैलो मिले हैं तो सरकार चल़ाने में उनका बहुत सहयोग रहा। तमाम उन्होंने डिपार्टमेंट के, अनके डिपार्टमेंटों में रिसर्च करके दिया कि आप कोई ऐसा काम करते हैं तो निश्चित तौर से हमारी जो तमाम क्षेत्र की जो समस्या इसके आधार पर नई चीजें वो लेकर आते थे, नए रिसर्च करते थे सरकार के लिए। आप इसको रिसर्च करके देखें, कोई भी काम उसको दिया जाता तो उसको रिसर्च करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय केजरीवाल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और आज केजरीवाल जी की सरकार को तहस–नहस करने में

भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन इस देश में ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडर के संविधान को दिशा देने का काम किया, उसकी रक्षा करने का काम किया और उसकी हिफाजत करने का काम किया। रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम जब हमारे पास स्टाफ होगा अच्छे, हमारे पास सर्विस वाले, काम करने वाले अधिकारी होंगे तभी इन चीजों को हम अंजाम दे पायेंगे, इस प्रदेश की जनता को। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब इस रूल-66 के तहत हम सब लोग इन, जिन लोगों ने, अधिकारियों ने, जिन नेताओं ने इस पर तमाम हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया है उन सभी पर एफआईआर लॉज करके उन पर मुकद्मा चलाया जाए और मानहानि का मुकद्मा उन पर लगाया जाए कि सरकार को बदनाम करने के लिए और हमारे तमाम विधायकों को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है तो निश्चित तौर से मानहानि का मुकद्मा लगा कर एफआईआरलॉज करकर उन लोगों को संदेश दिया जाए कि आपने प्रदेश की जनता को, जो जनता के साथ जो अन्याय, अत्याचार आप कर रहे हैं। मेरा मानना है आज तमाम अध्यादेश आए, दिल्ली सरकार के सामने अध्यादेश ले के आए लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में है जो कि बाबा साहेब डा अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाला है लेकिन इस देश के जितने लोग

दुनिया में हैं, लोग बाबा साहब को मानते हैं, ये लोग नैगलैक्ट करते हैं। ये तो चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति संविधान बने और लोगों को फिर हम जिस तरह से करना चाहते हैं जो उसके संविधान में हमें राजपाट का अधिकार नहीं है, उसमें हमें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हमें किसी चीज का भी अधिकार नहीं है। उसी के तहत वो रहना चाहते हैं लेकिन इस देश में एक पहला नेता है जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं देश के संविधान को दिशा दूंगा। इस संविधान की रक्षा करूंगा। इसकी मैं हिफाजत करूंगा, इस देश का जो गरीब निचले पायदान पर जो खड़ा है, लास्ट पायदान पर जो खड़ा है उसको मैं हर अधिकार देने का काम करूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब को मैं अपना सलाम सैल्यूट करता हूं कि वो एक नेता हमारे बीच से आए जो कि इस संविधान के मौलिक अधिकारों की जो बात करते हैं, जो उनके अधिकारों की बात करते हैं । आज दिल्ली का विकास मॉडल को देखे तो आप जानें पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि इस देश में पहला ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला है जिसने वास्तव में मानवता के इंसाफ के लिए काम करा, आखिरी पायदान के व्यक्ति के लिए काम करा है क्योंकि पहले कोई व्यक्ति ना फ्री पानी देता था, ना बिजली देता था, ना शिक्षा देता था, ना कोई स्वास्थ्य देता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं लेकिन हमारी सरकार को कमजोर करने के लिए तमाम चीजें वो आज लेके आए हैं संसद में लेके आए हैं,

लोकसभा में लेके आए हैं। आज एलजी के द्वारा अपनेअधिकारों को गलत यूज करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद, शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, उपसभापति महोदया जी आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आपने अभी सुना ही जो संजीव झा जी बता रहे थे कि क्या प्रोसेस था। एक बहुत ही डिटेल्ड साफ सफथरा ट्रांस्पेरेंट किस्म का एक प्रोसेस था जिसके अंदर जो पढ़े लिखे युवा हैं जो देश के लिए, सरकार के साथ में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं उनको ये मौका दिया गया कि वो अपनी योग्यता है उसको प्रमाणित करें और दिल्ली सरकार के साथ में काम करें। जैसा कि आपने सुना कि दरअसल इनकी परेशानी बड़ी अजीब सी है तो वही एसोसियेट और वही फैलोज जब हमारे विपक्ष के साथियों के साथ काम कर रहे थे तब इनको कुछ गलत नजर नहीं आया। तब बिल्कुल ठीक था ये उनसे काम करा रहे थे रिसर्च, आज इसीलिए शायद बैठे हुए हैं क्योंकि फैलोज नहीं हैं इनके साथ में। पहले तो बहुत बोलते थे तो आज फैलोज नहीं हैं तो इनको पता नहीं है करना क्या है, तो थोड़े ये परेशान से हैं, नहीं तो कभी मंच पर चढ़ जाते, कभी वैल में आ जाते हैं तो आज कुछ लिखना पढ़ना रह गया लगता हैं। अब इन्होंने हमारे सारे साथियों पे आरोप लगा दिए। ये बंदना जी बैठी हैं इनकी बहन

बना दी एक कि भई वो फैलो है। अब हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हमसे झगड़ा करने आ गए कि जब बंदना जी की बहन लग सकती है तो हमारी बहन क्यूं नहीं लग सकती। अब बंदना जी के घर में झगड़ा हो गया, ये तो प्रापर्टी के हिस्से बंट रहे हैं इनके पिताजी का झगड़ा हो गया। संजीव झा जी के भाई गांव में बैठे हैं यहां पे दो और आ गए कि पहले ही कुछ नहीं है। गरीब विधानसभा का विधायक है और भाई भाई नए पैदा कर दिए, बहनें पैदा कर दीं। बताओ लेना एक ना देना दो, कहां से इन विषयों को ये ले के आते हैं। मतलब रिश्तेदार ही पैदा कर देते हैं। जवान सीधे तीस साल का भाई पैदा हो गया। कमाल हो गया, वो हाजी साहब का बेटा लग गया। आप बताओ जो सच के बेटे हैं वो मारेंगे नहीं मारेंगे। जिनको बीस पच्चीस साल से जो इनके घर में रह रहे थे वो नाराज हो गए कि हमको नहीं लगाया हाजी साहब आपने पता नहीं कौन से बेटे को लगा दिया। अब अम्मा को पता नहीं बेटा है, हाजी साहब को पता नहीं बेटा है, इनको पता है वो बेटा है इनका। कमाल हो गया। अब बताओ ये इस किस्म का जो मजाक होता है देखिए ये कितनी ये बातें कभी कभी कितने सीरियस मैटर में जा सकती हैं। अब इन्होंने कहा दुर्गेश पाठक जी की पत्नी थी। अरे भई बाद में शादी हुई थी, पहले तो आप ही के यहां फैलो थी वो पता होगा आपको भी, ये भी नहीं पता था।.. अरे ये कोई बात थोड़े ही है, ऐसे तो आप बहुत पहले कुछ कर सकते थे लेकिन ये बहुत ही मजेदार किस्म की चीजें लेके

आते हैं कि हमको नहीं पता हमारा कोई भाई है, हमारे पिताजी ने हम को बताया नहीं, हमारी माताजी ने पैदा नहीं करा, इनको पता है। अरे भाई कुछ तो सोचो, कोई तो सीरीयसनैस लेके आओ, किसी चीज में कोई तो आधार कार्ड भी कोई आपके पास बनाने आता है तो आप पूछते हो कौन है, क्या है। आप किसी के भी रिश्तेदार बना रहे हो विधायक के साथी को। देखिए इनकी जो दिक्कत है वो इस बात से कतई नहीं थी कि नए लड़के काम करने आ रहे हैं, उन्हें हटाया जाए, क्या करा जाए, इनको बस ये देखना है कि सरकार में अगर कोई भी चीज ठीक दिख रही है, अच्छा यहां अच्छा हो रहा है तो इसको कैसे हिलाया जाए, कैसे बदनामी करी जाए। ये कह रहे हैं अखबारों की न्यूज बनाई जाए। मैं आपको बताता हूं दो एग्जाम्पलस कि फैलोज़ कैसे काम करते थे। देखिए आप भी एक विधायिका हैं और ये बहुत सारे विधायक बैठे हैं, हम रोजमर्रा के कामों में बहुत बिजी होते हैं लगातार जो शिकायतें होती हैं उसी पे काम कर लें तो बात होती है। कई कई नई नई चीजें आती हैं जिसके उपर रिसर्च करने वाले लोग हमारे साथ में नहीं होते हैं। जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं वो अपने एक इलाके को देखते हैं कि यहां पानी की दिक्कत है, यहां लाइट की दिक्कत है वो हमको बताते हैं, उस पे हम काम करते हैं। जो साथी साथ में लगे हुए होते हैं वो उसके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको नॉलेज हो उस चीज की, एक्सपीरियंस के साथ कार्यकर्ता काम करता है लेकिन ये जो नया खून है, नए पढ़े लिखे

लोग पीएचडी थे जिसके अंदर सीए थे ऐसे लड़कों को लगाया गया, लड़कियों को लगाया गया क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई की हुई थी, स्पेशलिस्ट थे वो। अभी एक आपको मैं पॉलिसी डिसीजन के बारे में बताता हूं कि इन्होंने कैसे काम करे। आपको पता है हमारी पेंशंस आती थी उसमें दस परसेंट हिस्सा केन्द्र सरकार का आता था। बिधूड़ी जी जरा गौर दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं। दस परसेंट हिस्सा केन्द्र सरकार देती थी पेंशन का, देना बंद कर दिया। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जब नब्बे हम दे ही रहे थे तो हमारी पेंशन और रूक रही है क्या फायदा। तो ऐसे ही जो हमारे फैलोज थे उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये दस परसेंट के लिए एक पॉलिसी लेके आ जानी चाहिए, दिल्ली सरकार जब 90 दे ही रही है तो दस में और क्या आफत है, 78 हजार करोड़ का बजट है और इसको मान लिया गया। मैं विडो पेंशन की बात कर रहा हूं, इसे मान लिया गया। हंडरेड परसेंट हम दे रहे हैं, तुम दो मत दो, जो विडो होती हैं, जो बेचारी परेशान हैं, इनके घर में उसी से खर्चा चलता है वो मिल जाए। अब ये आइडिया विधायकों को आ सकता है लेकिन कभी कभी बहुत सारे काम होते हैं विधायकों के पास में तो इसकी इम्पलीमेंटेशन कैसे होगी, इसके बारे में पढ़ना क्या है, क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम किससे कहें? ये छोटे छोटे काम लेकिन रिसर्च के काम हैं, ये फैलो किया करते थे। ऐसे ही अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा सुनियोजित स्पोंन्सर्ड दंगा मणिपुर के अदंर चल रहा था। बच्चे वहां

से आ गए दिल्ली। बच्चों को स्कूल के अंदर ऐडमिशन दिलाना है, उनके पास कोई कागज ही नहीं है, वो तो छोड़ के भाग के आए हैं, वहां दंगे चल रहे हैं या चलवाए जा रहे हैं। अब उनको ऐडमिशन कैसे मिलेगा? फिर इन्हीं फैलोज से एक पॉलिसी बनवाई गई, उन्होंने दिल्ली सरकार को दी और हमने बिना कागजों के भी उनका अपने स्कूलों में ऐडमिशन कराया जो मणिपुर के बच्चे हैं। अब इनको पता ही नहीं ना कि वो काम क्या करते थे। मुझे पता नहीं ये क्या करवाते थे, हो सकता है बिठा के रखते हो, हो सकता है इनका कोई रिश्तेदार लगा हुआ हो, ये बताते नहीं। मेरा वजीरपुर से एक भी आदमी नहीं लगा फैलोशिप में क्योंकि उसके क्राइटिरिया ये नहीं था कि वो वजीरपुर का है कि मंगोलपुरी का है, उसका क्राइटिरिया ये था कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो इंटरव्यू को पास कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। इस तरीके के नए नए डिसीजनस देने काम करने में, अब कभी कभी जनता में जा के पूछना होता है कि तकलीफ क्या है, जब कार्यकर्ता जाता है वो उसको रोज देखते हैं, हो सकता है ना बताएं लेकिन वो फैलोशिप वाले लड़के लड़कियां जब जाते थे, एकदम प्रोफेशनल लगते थे, प्रोफेशनल तरीके से बात करते थे, अधिकारियों से बात कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तो ये कसम खा रखी है कि देखना ही नहीं है बच्चे कहां कहां से पढ़ के आए थे आईआईटी से, आईआईएम, डीयू, बीएचयू, ये कोई छोटी छोटी संस्थाएं तो है नहीं। वहां से पढ़ के जब वो आ रहे हैं, तो

सात हजार में, तो दस हजार में, तो 15 हजार में तो काम करेंगे नहीं जो आपने कहा इतनी सैलरी क्यों दे दी। वो स्पेशलिस्ट काम के लिए बच्चों को रखा गया था। लेकिन इन्होंने सारे के सारे यहां से भगा दिए। अब आप देखिए कि कितनी जल्दी जल्दी फैसले होते हैं। एक फैसला आया और उपर से नीचे तक हिलाए जा रहे हैं। विधानसभा को नोटिस भेज दो, हमारे विधानसभा के अधिकारियों को नोटिस भेज दो, विजिलेंस का नोटिस भेज दो, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट सीएजी के नाम को पहले कोई जानता नहीं था, जो वो सीएजी की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस की सरकार नीचे तक हिल गईं आप सबको याद होगा जब उसी वक्त अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ था तो सबको पता होगा। आज जब सीएजी कुछ कह रहा है तो कोई बात आप सुन रहे हो, ना हमारे विपक्ष के साथी यहां कुछ कहेंगे, ना उधर कुछ कहेंगे, ना लोकसभा में होगी, ना राज्यसभा में होगी। अयोध्या के अंदर पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा अयोध्या के अंदर बीस लाख रूपये एकड़ पर जमीन ली एमएलए के रिश्तेदारों ने, बाकायदा एक कंपनी बना ली, एक ट्रस्ट बना ली और उसको 250 करोड़ में मंदिर के ट्रस्ट को ही बेच दिया। ये है परिवारवाद जिसको आप कह रहे हो रिश्तेदारों को लगा दिया। खुला परिवारवाद है, सीएजी की रिपोर्ट है। कितने गुणा प्राफिट कमा लिया और किसके नाम पे कमाया जिसके नाम पे ये देश में सरकार बनाते रहे हैं मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के नाम पे। बोलिए आप उसके उपर क्यूं नहीं बोलते ,सीएजी की

रिपोर्ट है, हमारी थोड़ी है या वो भी कह देंगे केजरीवाल जी ने बोली है। रोड़ बनवाया ये द्वारका ऐक्सप्रेस वे, सोने की सड़क बनाई है इन्होंने वो, कोई जवाब नहीं होता और सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है जिन छह जगहों के बारे में बात करी है तेलंगाना को छोड़कर, सब जगह इन्हीं की सरकार है। हिमाचल में अब कांग्रेस की है लेकिन उस वक्त इन्हीं की थी जब ये घोटाले हुए। ये बोलेंगे उसके उपर कुछ, ये बताएंगे उसके उपर कुछ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन बच्चों को हटाना क्योंकि वो दिल्ली सरकार के विधायकों के साथ काम कर रहे हैं, सीएम के साथ काम कर रहे हैं या एजुकेशन में काम कर रहे हैं, इनको तकलीफ होती है। और तो और जिन्होंने पोलिसी बनाई उनके उपर आप जा के उनको कोई नोटिस भिजवा दो, विजिलेंस से भिजवा दो, ये क्या हो रहा है। मैंने सुबह भी एक बात करी थी, मैं दोबारा विपक्ष के साथियों से पूछता हूं कि ये आफिसर्स गैलरी खाली पड़ी है, आप बताइए आप लोग इतने पुराने पुराने हैं बिष्ट साहब और बिधूड़ी साहब तो बहुत बार यहां पर एमएलए बन के बैठे हुए हैं इनको. क्या ऐसे गैलरी खाली पड़ी रहती थी कभी? कैसी राजनीति है ये, क्या करने हम आ रहे हैं यहां पे? चाय तो हमारे घर पे भी है। खाना भी घर पे मिल जाता तो यहां क्या करने आए थे, एसी भी लगा हुआ है घर पे।

यहां इसलिए आते हैं कि जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है या आपको चुनकर भेजा है उसके हम कुछ काम करा सकें। काम

कैसे कराएंगे जब वहां कोई है ही नहीं। ना ये इसपर कुछ बोलते हैं, इनको बोलना चाहिए। अगर साथ देना है तो यहीं दे दो ना, एल जी के पास में तो बाद में चलेंगे, यहीं पर करना चाहिए कि जब भी सत्र लगे यहां पर आकर बैठे अधिकारी। आपने डाकिए भी हटा दिए, अधिकारियों को ऊपर वालों को आप आने नहीं दे रहे, फिर क्या चाहते हो दिल्ली के लिए? आपकी 1993 में जब पहली बार सरकार बनी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपके बड़े नेता दिल्ली के, आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी, जिस क्षेत्र से मैं विधायक बनकर आया हूं, आदरणीय खुराना साहब जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने, जो लगातार लड़ते रहे इन चीजों के लिए, ये वो लोग हैं, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिये। और ये सब भी साथ थे उनके, इसी बात पर इनको पहली बार सरकार मिली। लेकिन जब इन्होंने झूठ पर झूठ बोला तो ये वनवास हो गए। और अब तो कमाल ही कर दिया जितनी शक्तियाँ थी आपने वो भी छीन लीं, अब तो आधी-अधूरी भी नहीं छोड़ रहे आप। इस तरीके की खतरनाक राजनीति जो ये दिल्ली के साथ में कर रहे हैं, इनको लगता है कि ठीक है भई इनकी सरकार नहीं आई तो किसी और की बने ही नहीं, हम 24 भी जीत जाएंगे और अब तो मेरे ख्याल से 100 साल का फार्मूला दे दिया प्रधानमंत्री जी ने।.. एक हजार साल का, एक हजार साल बाद में क्या होगा पता नहीं।.. प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। वो अभी कोई मुझे बता रहा था कि अगर अबकी बार मोदी जी जीत जाते हैं जिसकी

सम्भावनाएं नहीं है, जीत जाते हैं तो वो कहेंगे सब अपना नाम मोदी रखो ताकि कोई बुराई ना कर पाए मोदी जी की। अरे आपको पूरा देश दे रखा है आप उसे चला लो ना। आप क्यों दिल्ली की ऐसी-ऐसी चीजों में, छोटी-छोटी चीजों में आते हो। जो लोग सरकार की, विधान सभा की मदद कर रहे हैं आप उनको हटवा देते हो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखो आपने सही किया, गलत किया। और फिर आप विजिलेंस के नोटिस भिजवाते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी इन्होंने करना था, वो तो ये लगातार करते ही रहेंगे। लेकिन ये बात ये समझ लें कि ये दिल्ली की सरकार ऐसी नहीं है कि झुक जाएगी, ये महाराष्ट्र में जो मर्जी खेल करके आ जाएं, एक हफ्ते पहले कह दें कि पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला किया और मैं छाती ठोकर कह रहा हूं कि घोटालेबाजों को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा भी नहीं, एक हफ्ते बाद अपनी पार्टी में ले लिया। छोड़ा थोड़े ही, ना छोड़ने का क्या मतलब होता है। एक आदमी गुस्से में कहता है तुझे छोडूंगा नहीं, एक आदमी प्रेम में भी कहता है, भाई तुझे नहीं छोडूंगा मैं कभी भी। तो इनका प्रेम वाला छोड़ना होता है भ्रष्टाचारियों के साथ। तो सब इनका साथ देंगे तो इनके साथ है। अब सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसने भेजी है उसका भगवान ही मालिक है, मुझे नहीं लगता एक हफ्ता भी वो लोग उस सीट पर रह पाएंगे।.. देशद्रोही नहीं सीट पर नहीं रह पाएंगे, पता नहीं क्या-क्या होगा।..

माननीय अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री राजेश गुप्ताः इलैक्शन कमिशन में चीफ जस्टिस का नाम है उसको वो हटवा देंगे। मतलब जो भी आदमी इनको ये दिखाई देता है कि कोई भी इनकी राजनीति के बीच में रोड़ा आ रहा है उसको हटा दो। जो जज ने बोल दिया कि मेवात के अंदर दंगे हुए, तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए उसका ट्रांस्फर कर दिया। मैं उस क्षेत्र से आता हूं सोहना मेरा गांव है, वहीं मेवात है, 1947 के अंदर भी कभी दंगे नहीं हुए, जहां इनके लोगों ने वो बेकार-बेकार की विडियो वायरल कर-करके वहां दंगा कराया, क्यों? क्योंकि 70 किलोमीटर दूर यूपी है, 70 किलोमीटर दूर राजस्थान है और 70 किलोमीटर दूर दिल्ली है वहां से। तो इनको तीन स्टेट दिखाई दे रहे है वहां से। कैसी राजनीति है ये। मैं अपनी बात को ये कहकर विराम देना चाहता हूं कि जो डार्क के माध्यम से जो बच्चे यहां काम करते थे और बहुत बेहतरीन उन लोगों ने काम किया, ये विपक्ष के साथी भी जानते हैं इसलिए वे इनके साथ काम करते थे और अगर इसमें कोई घोटाला हो सकता होता तो ये भी अपने कुछ लगवा लेते, ना हमारे लगे ना इनके लगे, इनको पता है बिल्कुल न्यूटरल था। स्टेज वन का जो उसका प्रोसैस था, वो टोटल ऑन लाइन एप्लीकेशन सोफ्टवेयर के थ्रू हुआ। उसमें ये तो नहीं था किसी से कुछ पकड़ लिया, सीधे ओनलाइन था। जितने भी फैक्ल्टी थी उसको डीटीयू की जो फैक्ल्टी है वो हैंडल करती थी, उसमें दिल्ली सरकार का या विधान सभा का कोई डायरेक्ट लेना-देना नहीं था। मैं संजीव झा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है,

उसके साथ हूं और मेरा मानना है कि इसको बिल्कुल प्रिविलेज में भेजना चाहिए कि इस तरीके से जो काम रोकने के जो तरीके हैं इनसे ये बाज आएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी। 5 मिनट हैं।

श्री अजय कुमार महावरः आदरणीय अध्यक्षा जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नहीं बोलना।

श्री अजय कुमार महावरः पहले विजेंद्र जी को बुलवा लीजिए उसके बाद मैं बोल लूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः नहीं-नहीं दो नाम भेजे थे।

माननीया अध्यक्षः सीरियल नम्बर आप ही ने दिया है, मैंने अपने पास से नाम नहीं लिखा, नम्बर एक पर आपने अपना नाम लिखा..

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः आपकी अनुमति हो तो।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नंबर, मैं पहले कुछ बोल लूं, बैठें बिधूड़ी जी। जैसा कि प्रक्रिया है पक्ष से नाम आता है, मैं विपक्ष को भी पूरा मौका देती हूं कि आप अपना नाम दे दीजिए,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सीरियल नम्बर से आपने दिया, कोई बात नहीं बैठिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विनय मिश्रा जी।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः नहीं– नहीं मैं, अरे मैं बोलूंगा ना।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं दे दूंगी बाद में। मौका बाद में दे देंगे।

श्री अजय कुमार महावरः विजेन्द्र जी को पहले बुलवा दीजिए। ठीक है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विनय मिश्रा जी।

श्री विनय मिश्राः मैडम बहुत–बहुत धन्यवाद, पहला ही जो है डीएआरसी फैलो ना होने का पहला ही परिणाम आपको दिख गया

कि आपस में फैसला नहीं पाया और वो बोल नहीं पाए कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। और मैं एक बात से और बहुत खुश हूं मैडम कि एटलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में पढ़े-लिखों की जमात है तभी इन्होंने जितने भी स्कोलर थे सब मान लिया आम आदमी पार्टी के थे, चाहे वो संजीव झा के भाई हों, चाहे वो दिलीप पांड़े जी के रिश्तेदार हों, किसी के भी, सबको मान लिया अब चाहे पीएचडी हो, ग्रेजूएट हो सब आम आदमी पार्टी में, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं इनसे पूछना भी चाहता हूं ये ईमानदारी से बताएं इनको भी फैलो मिले हुए थे, आज ये महसूस कर रहे हैं बदलाव कि नहीं, आज बोला नहीं जा रहा, देखिये मैं आज सुबह से देख रहा हूं। आज सुबह से ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठकर सारी बात सुन रहे हैं, ये पच नहीं रहा है मैडम। ये पच नहीं रहा है मैडम, आज बड़ी मतलब हैरानी वाली बात है। तो ये आज दिख रहा है फैलो ना होने का असर क्या है, मैडम सामने परिणाम नजर आ गया।.. मैडम वैसे एल जी साहब क्या, इनकी भी तो पावर छीन ली, बेचारे करें तो करें क्या। अब इनकी चलती नहीं, सुनते नहीं है इनकी। मैडम मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से बताईं मैं एक बात पर हैरान हूं मैडम, जब डीटीयू की वैबसाइट पर जब रजिस्ट्रेशन हुआ, डीटीयू की वैबसाइट से रजिस्ट्रेशन होकर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जब एक एक्सपर्ट पेनल ने इंटरव्यू लिया और स्वाभाविक है

मैडम उसके अंदर कोई पीएचडी स्कॉलर है, मेरा वाला जो फैलो था, वो लॉयर था और मैडम मतलब मैं गाथा क्या बताऊं उसकी वो मैं जब उसका इस तरीके से नौकरी छूटी तो मेरे पास रोता हुआ आया, बोला सर इतनी मुश्किल से मेरी नौकरी लगी थी, मेरे फादर की डैथ हुई थी, उसके बाद मुझे ये नौकरी मिली। मेरे फादर एक मैकेनिक थे, हमारी स्कूटर ठीक करने की दुकान थी, मेरी जब नौकरी लगी तो मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ने लग गई कि हमारे घर से कोई बच्चा अगर पढ़ा-लिखा निकला तो उसकी नौकरी लग गई, लेकिन आज मैं एकदम सड़क पर आ गया, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, कहां से शुरू करूं और कहां जाऊं। और निश्चित तौर पर मैडम बड़ी हैल्प मिलती थी। किसी भी टॉपिक पर, कभी भी रिसर्च मांगो तो क्योंकि निश्चित तौर पर मैडम सुबह हम लोग दफ्तर में बैठते हैं, कभी प्रैस में हमको ब्रीफिंग करना होता है, कभी हमारे को बहस पर जाना होता है। तो सुबह से जब पब्लिक में बैठते हैं तो, जब आप पब्लिक डीलिंग करो तो आपको टाइम नहीं मिल पाता रिसर्च करने का। क्योंकि आज कल जब टीवी डिबेट होती है या कहीं भी हम युवाओं के बीच में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या कहीं भी आज कल युवाओं से बात करते हैं तो वो तथ्यों पर बात करना चाहता है। वो आजकल इधर-उधर की बात सुनना नहीं चाहता कि इधर की, उधर की बात करके उसको टरका दो, वो तो तथ्य की बात सुनना चाहता है और जब ये

रिसर्च फैलो होते थे तो मेरी विधान सभा में मोहल्ला क्लीनिक में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जहां डॉक्टर नहीं होते थे, इमीडेटली मुझे इन्फोर्म करना, जहां मोहल्ला क्लीनिक में दिक्कत आती थी उसका इन्फोर्म करना। स्कूलों के एडमिशन के समय में, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो एडमिशन लेने आते हैं ज्यादातर जो वहां मॉं–बाप आते हैं वो इतने शिक्षित नहीं होते, उनको मदद करना, कागजों में मदद करना, उनको बताना कैसे क्या करना है, उनको गाइड करना, स्कूलों में स्टेब्लीश करना, वहां बताना, बड़े काम करते थे। तो तमाम तरीके के काम करते थे और बड़ी मदद मिलती थी उससे। और मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरे सभी सीनियर हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे ये ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलें कि इनको भी हैल्प मिलती थी कि नहीं मिलती थी, गलत था या सही था, ईमानदारी से बताएंगे तो इनके दिल से भी निकलेगा की फैलो सही थे। और फैलो की नौकरी उस सरकार ने छिनी जो सरकार कहती थी हम सरकार में आएंगे तो दो करोड़ नौकरी per साल हम युवाओं को देंगे, लेकिन इन्होंने नौकरी तो दी नहीं, दिल्ली सरकार ने जो नौकरी दी उल्टी वो छीन और ली। और इसमें मैडम मैं जानकारी ले रहा था, इसमें कोई गोयथा यूनिवर्सिटी से आया था जो फ्रैंकफर्थ जर्मनी में है, कोई डबलिन यूनिवर्सिटी से आया था जो आयरलेंड में है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रूड़की और देश के तमाम ऐसे जो टॉप के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजिज हैं उसके बच्चे वहां

आकर पढ़ते थे। मैडम मैं पूरे देश में देख रहा था कि कहॉ–कहॉ इस तरह के सिस्टम है क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है युवाओं को भी लेजिस्लेशन में लाना, युवाओं को भी गवर्नेंस में लाना। तो युवाओं को हम चाहते हैं कि सरकार आज की डेट में युवा राजनीति से विमुख हो गया तो हम चाहते हैं कि युवा भी आएं और गवर्नेंश में और लेजिस्लेशन में पार्ट लें। तो इस बहाने युवा जुड़ता था और जब युवा फैलोशीप में आता था तो वो और भी लोगों को वो मोटिवेट करता था जब मिलता था, जब बच्चों से मिलता था तो लोगों को लगता था वो मोटीवेट करता था, वो बताता था कि विधान सभा में काम कैसे होता है, कैसे विधान सभा में बहस होती है, कैस कानून बनता है तो और लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि short sightedness की वजह से इस प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर दी गई मैं देख रहा था मैडम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं था ये, ये यूपी में भी सीएम फैलोसीप प्रोग्राम चलता है जिसमें मैनेजमेंट को लेकर, policy implementation, monitoring वहां के जो है नौजवान देखते हैं। झारखंड में सीएम साहब ने young professionals निकाला, महाराष्ट्र में सीएम फैलोसिप चलता है, मध्य प्रदेश में Chief Minister Young Professionals for Development programme चलता है, उत्तराखंड में सशक्त उत्तराखंड सीएम फैलो चलता है, उड़ीसा में Chief Minister Research and Innovation Fellowship programme चलता है, तमिलनाडू में चलता है। तमाम हमारे देश के तमाम राज्यों में जब ये चलता

है तो दिल्ली से ही परहेज क्युं? दिल्ली से ही उनको क्यों काम करने से रोका जा रहा है?..

श्री सोमनाथ भारती: गुजरात ने नहीं चलाया है।

श्री विनय मिश्रा: गुजरात में मुख्यमंत्री अनपढ़ थे न तो उन्होंने नहीं चलाया अगर पढ़े-लिखे होते तो चलाते इस बात को। तो वो मैम जो ये संजीव झा जी ने रूल-66 में चलाया मैं निश्चित तौर पर मैम आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये अफसरों के ऊपर जो एक हाथ रखा जिस वजह से आज उनका ये डर खत्म हो गया और सही मायने में जगह-जगह पर अफसरों ने जो काम करना बंद कर दिया और विजिलेंस वालों ने जो इन्क्वायरी बिठाई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं क्यों नहीं जाते हैं एसडीएम दफ्तर में जहां जो सर्टीफिकेट बनने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं? हम चिट्ठी दे रहे हैं, हम चिट्ठी देते हैं जहां-जहां विभागों में काम नहीं हो रहा है वहां जाकर आप विजिलेंस इन्क्वायरी करो लेकिन वहां नहीं करेंगे, जहां दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही होगी वहां जाकर रोकने का काम इनका जरूर है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है ऐसे अफसर जो इसमें लिप्त हैं और जो दिल्ली विधानसभा को उसका काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा एक स्वायत्त बॉडी है जब इसका काम नहीं करने दे रहे और बकायदा दिल्ली विधानसभा से एक बिल पास हुआ और उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको अप्रूवल देकर फाइनेंस दिया। अब उसके काम को रोका गया तो निश्चित तौर पर आप सोचिये कि इनकी मंशा क्या है। तो

मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं रूल-66 में जो ऐसे आफिसर जो लिप्त हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए और उनसे पुख्ता जानकारी ली जाए कि ये किसके कहने पर ये क्यों किया जा रहा है और दिल्ली में जो अच्छे काम रोके जा रहे हैं उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाए ताकि लोगों के बीच में लाया जाए कि दिल्ली सरकार का काम आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रोक रही है और जो चाहती नहीं है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम कर सके, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीया अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः थैंक यू स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहिबा जैसे की मेरे से पहले साथियों ने बताया की किस तरीके एलजी साहब के निर्देश पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक नोटिस पर एक ही झटके में 116 विधानसभा के फैलोज की नौकरी एकदम छीन ली गईं बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मेरे पास भी फैलो काम करते थे और हर दिन मैं जानता हूं कि किस तरीके से वो हमारे रोजमर्रा के काम है चाहे हमारे आफिस का मैनेजमेंट हो, चाहे सरकार के साथ तालमेल के काम हों उसमें हमारी हर दिन मदद करते थे। जिस दिन से ये प्रपोजल शुरु हुआ था, जीपीसी में पास हुआ फिर इस हाउस में पास हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, इनकी अपाइंटमेंट की प्रोसीडिंग शुरु हुई और अपाइंटमेंट भी स्पीकर साहिबा ऐसे नहीं कि जैसे ये ब्लेम कर रहे हैं उस तरीके से हो गया। इनकी

एजुकेशन के, इनकी इलिजिबिलिटी के, इनके स्किल्स के, उसके बाद इंटरव्यूज के बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ और पिछले कुछ सालों में संदीप और दीपक नाम के दो फैलोज ने मेरे साथ काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों के पास विदेश में बहुत अच्छी नौकरी की अपोर्चुनिटी थी पर इन्होंने दोनों ने सोचा कि हम अपने देश में रहकर ही अपने सिस्टम को समझेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। तो ये किस तरीके का न्याय है अध्यक्ष महोदया की जो बच्चे, काबिल बच्चे अपनी मेहनत से चुनकर, सिलेक्ट होकर, इंटरव्यू देकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, रातोंरात बिना कुछ सुने उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी और ये जो करने वाले हैं इनका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारे फोटो खिचवाने के शौकीन प्रधानमंत्री साहब की बड़ी सी फोटो लगी है और एक घोषणा पत्र में क्या कह रहे हैं कि 'India is a youthful country, a country with such a major percentage of youth, has the capability to change not only its own but the fate of the entire world' पर ये क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदया, ये तो मतलब इस तरीके से तो कल को नौजवान कोई सरकारी नौकरी मिलती होगी वहां भी करते हुए डरेंगे, पता नहीं कब मोदी साहब के मूड में आए और हमारी नौकरी छीन लें और जिस तरीके से एक-एक अपनी घोषणाओं की ये धाज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से 15 लाख वाले अपनी बात को जुमला कह दिया और नोटबंदी करके जो घर में पड़े थे वो भी निकलवा लिये। जिस तरीके से

बोलते थे जी किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसानों की एमएसपी तक हटाने पर अमादा हो गये। जिस तरीके से बोलते थे कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और किस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। जिस तरीके ये बोलते थे कि पेट्रोल 50 रुपये से 35 रुपये कर देंगे 100 रुपये पेट्रोल हो गया और जिस तरीके ये बोलते थे कि डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे आज 100 रुपये का एक डॉलर लगभग हो चुका है अध्यक्ष महोदया। उसी तरीके से इन्होंने रोजगार देने के नाम पर युवाओं के साथ भी धोखा किया है, छल किया है और इन्होंने तो अध्यक्ष महोदया पिछली टेन्योर का, वो तो हमको नहीं छोड़ा था। एक principle of natural justice होता है जिसके तहत सुना जाता है सामने वाले को भी तुम्हारे को हटा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ कहना है। इन्होंने तो हमारे 21 विधायकों को जिसमें मैं भी शामिल था पिछले टर्म में हम ही को डिस्क्वालिफाई कर दिया था बिना सुने। वो तो भला हो माननीय हाईकोर्ट का जिन्होंने हमें सुना और हमारे पक्ष में फैसला दिया और फिर से हम यहां पर बहाल हुए। मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हैं जो उसके चलते डिस्क्वालिफाई कर दिये गये थे। तो ये किस तरीके का सिस्टम इस देश में लाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत अफसोसजनक है। कुछ काम ऐसे करें कि अगले साल किसी एक मुद्दे पर वोट लेने लायक हो जाएं, जो काम आप कर रहे हैं बहुत लंबा न कहते हुए दो लाइनें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि:

''भाजपा को आम आदमी पार्टी के बार-बार
जीतने का डर कुछ यूं सता रहा है,
भाजपा को आम आदमी पार्टी के बार-बार
जीतने का डर कुछ यूं सता रहा है,
साजिशों का सहारा लेकर काम रोकना चाहते हैं,
साजिशों का सहारा लेकर काम रोकना चाहते हैं,
ये उनका हाल बता रहा है।''

तो इस तरीके के घटिया हरकतें बंद करें और जो पूरी प्रक्रिया से चुनकर आए डीएआरसी फैलोज हैं उनको रोकने का जो काम किया उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं और अपने साथी माननीय विधायक संजीव झा के इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद अध्यक्षा महोदय।

माननीया अध्यक्षः राजेन्द्र पाल गौतम जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सेशन खत्म कर दिया मैंने अभी स्पीकर्स हैं न अगर मैंने नहीं किया हो..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नहीं दिया सुबह से?

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जो अभी संजीव झा जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा ये बेहद महत्वपूर्ण है और मैं उससे सहमति भी रखता हूं। निःसंदेह एक्सपर्ट्स को हायर करना ये किसी भी विभाग के लिए और किसी भी देश की सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो दिल्ली की विधानसभा ने इसी विधानसभा में पास करके प्रस्ताव फैलोज रखने का प्रोवीजन किया था और उसके बाद फैलोज रखे गये। फैलोज के रखे जाने से कई प्रकार के फायदे हुए। जो दिल्ली असेंबली रिसर्च के लिए जो सेंटर बनाया उसमें जो एक्सपर्ट्स रखे गये उनके आने से वेल्यूएबल रिसर्च मटीरियल उपलब्ध होना शुरु हुआ। उनके आने से सदन की क्वालिटी आफ डिबेट देखने को मिली। उनके आने से जो स्टडी की बेस्ट प्रेक्टिस थी जिससे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी और देश के भी अलग-अलग राज्यों में किस-किस तरह के काम सरकारें कर रही हैं, विभाग कर रहे हैं। असेंबलीज किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें बड़ी मदद मिली और साथ ही साथ जो एग्जीस्टिंग लाज हैं उस पर कंपेरिटिव स्टडी करके रिसर्च फैलोज के माध्यम से हम लोग अपडेट हुए और यह रिपोर्ट्स पब्लिश भी हुई मटीरियल पब्लिक के डोमेन में भी आया। इससे एमएलऐज को भी, मंत्रीगण को भी और अधिकारियों को भी काम करने में काफी मदद मिली। इनको इस तरह हटाया जाना ये तो वास्तव में ये देश को और सरकार को और सरकार के काम को पीछे ले जाने वाला कदम था। हम सब जानते हैं कि

लेजीस्लेटर का काम सदन के माध्यम से कानून बनाना और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके एफेकटिव इंप्लीमेंटेशन करवाना। अधिकारी उसके इंप्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के बीच और अधिकारियों के बीच में कड़ी बनकर लोगों के काम करवाना ये एमएलऐज का काम रहता है लेकिन जनता एमएलऐज को बिजली, पानी, सड़क, सफाई और अपनी छोटी-छोटी समस्याओं में वो सोचती है कि हमारा माध्यम तो केवल एमएलए है चूंकि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर उनकी नहीं सुनते और किसी भी विभाग में जाएं तो उनकी आसानी से सुनवाई नहीं होती, तो जनता के लिए सबसे आसान और अच्छा साधन अगर कोई है तो वो एमएलए आफिस है। जनता एमएलए आफिस आती है, अपनी इस तमाम, उन्हें लगता है जैसे हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान एमएलऐज के पास है। एमएलऐज जो लेजीस्लेटर होते हैं वो इंटरनेशनल क्या दुनिया में चल रहा है उसकी स्टडी के लिए टाइम निकालें या देश-विदेश में अलग-अलग सरकारें किस-किस तरह की योजनाओं पर काम कर रही हैं और योजनाओं में क्या खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए जो स्टडी करने का उसे टाइम चाहिए वो एमएलऐज को टाइम मिलता नहीं है लेकिन विधानसभा की मदद से रिसर्च फैलो मिले, एसोसिएट फैलो मिले तो उनको गाइड हम लोग करते थे, उनको सब्जेक्ट हम देते थे कि ये सब्जेक्ट है कुछ रिसर्च मैं खुद कर रहा हूं, कुछ रिसर्च आप भी स्टडी करके मुझे दीजिए।

इसी तरह बाकी एमएलऐज भी करते थे और मैं समझता हूं मंत्री के तौर पर भी हमनें किया तो एक कंपेरेटिव स्टडी करते थे हम। भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारों की भी और विदेश में जो सरकारें काम कर रही हैं उनकी भी। कंपेरेटिव स्टडी करके हम देखते थे कि और बेहतर क्या किया जा सकता है लेकिन ये पूरे तरीके से काम को हैंपर किया गया, लेकिन इसमें साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिन को भी चयन करने की जिम्मेदारी मिली, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ ने किये हो या जो भी इंटरव्यू बोर्ड बना हो, उसमें एक बात जरूर होनी चाहिये जो मैं एक एडिशन कर रहा हूं इस समर्थन के साथ साथ कि एसोसिएट फैलो, रिसर्च फैलो होने चाहियें, उससे सरकार के काम में मदद मिलती है, एमएलएज़ को भी मदद मिलती है, क्वालिटी आफ वर्क सुधारता है, रिसर्च वर्क होता है, कंपेरेटिव स्टडी होती है लेकिन मैं इसमें सरकार से एक निवेदन करूंगा कि इसको तो बहाल करवाया ही जाये, कानूनी तरीका जो भी अपनाया जाये लेकिन इस व्यवस्था में एससी/एसटी और ओबीसी को रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिये ये मेरा सरकार से और इस सदन से निवेदन है। ये कह देना कि क्वालिटी छांटनी और क्वालिटी छांटने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी में क्वालिटी नहीं है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं, यहां पर कितने सारे एससी/एसटी के और ओबीसी के मेंबर्स बैठे हैं तो क्या ये कहेंगे कि ये काबिल नहीं हैं सदन के लिये। अगर ये सोच है तो ये सोच गलत है। आपको मौका

देना चाहिये। अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिजर्वेशन है तो वहां पे हमारे लोग सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनके बैठे हैं, केंद्र सरकार में भी सेक्रेटरी बैठे हैं। उन्होंने अपने काम के दम पे अपना लोहा मनवाया है, उन्होंने दिखाया है कि हमारे अंदर काबिलियत है और अगर पिछले 6 साल के अंदर दो बार एससी ने एक बार ओबीसी ने सिविल सर्विसिज़ में टॉप किया है तो आप कम से कमये तो नहीं कह सकते कि इन लोगों में क्वालिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको अवसर ही नहीं देंगे जैसा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन न होने का नुकसान ये है कि वहां पे रिप्रजेंटेशन हमारे एससी/एसटी के लोगों का न के बराबर है। कभी कोई इक्का दुक्का कभी कोई बनता है। तो मैं इस सदन के माध्यम से ये निवेदन जरूर करूंगा पहला तो ये कि ये रिसर्च फैलो, एसोसिएट फैलो होने चाहियें, इसके लिये कोर्ट के माध्यम से भी लड़ के चूंकि पूरे देश में हैं, सभी राज्य सरकारों ने हायर किये हैं, सारे विभागों के अंदर हैं, केंद्र सरकार तो लैटरल एंट्री करके लोगों को भर्ती कर रही है और यहां रोक रहे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मौका मिलना चाहिये। तो मेरा ये मानना है कि मौका मिलता है तो लोग अपनी काबिलियत साबित करते हैं। के आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति बने, लोग आज भी तारीफ करते हैं कि वोदेश के एक बहुत जबर्दस्त काबिल राष्ट्रपति बने, के.जी. बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस आफ इंडिया बने। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। उसी प्रकार अनेकों हमारे मंत्रीगण बनें उन्होंने अपनी

काबिलियत साबित की। कई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं जो अपने काम के दम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ मेरा सरकार से भी और इस सदन से निवेदन है कि हम चाहे ये अपनी विधान सभा के अंदर फैलो, रिसर्च फैलो रखें चाहे सरकार के विभिन्न विभागों में रखें, उसके अंदर रिप्रजेंटेशन दिया जाये जिन देशों ने affirmative action को अपनाया है वो देश तरक्की के मामले में आगे निकले हैं। अगर सभी वर्गों को साथ ले के चलना चाहते हैं तो उनको अवसर देना होगा, इसमें भी हमें अवसर मिलना चाहिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदया, यहां जो प्रस्ताव लाया गया ये प्रस्ताव जो है रूल 66 में है ब्रीच आफ प्रिविलिज का और मेरा पहला जो विषय है वो ये है कि इसमें अवमानना के जो नियम हैं उसका पालन नहीं किया गया है। रूल 66 में ये लिखा गया है रूल 67 में कि इशु स्पेस्फिक होना चाहिये। दूसरा ये सदन की अवमानना किस प्रकार से है ये बात समझके परे है। जो प्रपोजल है, जो लिखा है कि संजीव झा ने लिखा है 'To raise a Question of privilege against officers who abruptly discontinued the DERC Fellowship program of Delhi Legislative Assembly' तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव flaw हुआ है या किसी भी कारण से वो प्रशासनिक तौर पर कोई discontinuity हुई है तो सदन की अवमानना

किस प्रकार से है ये हमारी समझ के परे है। दूसरा, इसमें इशु कोई स्पेस्फिक नहीं लिखा गया, कोई नाम कोई स्पेस्फिक नहीं है, किसके अगेंस्ट मोशन है ये प्रिविलिज का। कोई नाम ही नहीं है। तीसरा, इसमें अगर ये ये लिखते हैं कि उन्होंने डिस्कंटिन्यू किया तो उसका मतलब है उसके दस्तावेज पर आधारित है ये। तो किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ मूल दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न होनी चाहिये, वो कोई प्रतिलिपि नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई स्पेस्फिक ब्रीच आफ प्रिविलिज किस तरह हुआ वो नहीं है। तो ये रूल 66 में, हां इतना जरूर है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पहला प्रस्ताव था रूल 54 का और ये जो दूसरा आज जो सुबह जो डिस्कशन होता रहा दिनेश मोहनिया जी की प्रस्ताव पर, कालिंग अटेंशन पर उसमें भी कहीं न कहीं फाइनेंशियल सेक्रेटरी की बात हो रही थी और इस दूसरे में भी फाइनेंशियल सेक्रेटरी की बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बदले की भावना से ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूसरा अभी गौतम जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने ये लिख के ही रखा हुआ था, अच्छा हुआ आपने बोल दिया तो बड़ा अच्छा समर्थन हो गया कि आरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। जो फैलोज़ रखे गये उसमें एक भी सीट आरक्षित नहीं थी, क्यों? आरक्षण क्यों नहीं दिया गया और ये सारा का सारा प्रोसेस जो इसके रूल्स हैं आरआर फॉलो नहीं हुए। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कौन से आरआर थे, किसके

आधार पर इनको रखा गया था, डेढ़ डेढ़ लाख रूपया जो सेलेरी दी गयी under utilisation थे। दूसरा इसमें बहुत साफ है कि पोस्ट क्रिएट हुई थी क्या, कोई फार्मेट बना था क्या? कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की गयी, कोई उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, आरआर नहीं थे और जिसके कारण और ये बात तो सही है चाहे आप कितना भी अपनी बात कहे पर इस पूरे मामले में भाई भतीजावाद तो हुआ है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने जो उनकी भर्ती का जो तरीका अडॉप्ट किया बिना financial arrangements के प्रॉपर, बिना उसके रिक्रूटमेंट रूल्स के, बिना उन पोस्ट के उनको भर्ती किया गया और उसमें जो एक बर्डन सरकारी खजाने पर था, उसका उस प्रकार से सदुपयोग नहीं हुआ। आज हम बात कर रहे हैं प्रिविलिज मोशन की, बाकी बातें तो जितनी की जा रही हैं सही है लेकिन ये जो मोशन है प्रिविलिज का ये अपने आप में जो है कहीं न कहीं contradictory है और इस रेज्योल्यूशन पर कोई भी प्रिविलिज की कार्यवाही आपकी टिक ही नहीं पायेगी, आगे ही नहीं बढ़ पायेगी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सिर्फ दिखाने के लिये आप कर रहे हैं, वास्तविकता में आप खुद ही सीरियस नहीं हैं कि आपको करना क्या है और होना क्या चाहिये। सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और उस भड़ास से आगे ये कुछ नहीं है।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः आदरणीय अध्यक्षा जी, प्रिविलिज नोटिस रूल 66 के तहत जो श्री संजीव झा जी ने इस सदन के पटल पर रखा है मुझे उससे सहमति नहीं है। अभी आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने जो बात कही, विजेंद्र जी ने ठीक कहा और मुझे भी लगता है कि ये प्रिविलिज मोशन के नाम पर जिसमें न कोई नाम है, न कोई सपोर्टिंग डाक्यूमेंट है, सिर्फ शगूफा छोड़कर के जनता को गुमराह करना, घोटालों से ध्यान भटकाना, अधिकारियों को निशाना बनाना, यही इसका मकसद दिखता है। अगर कानून सम्मत व्यवस्था करके, एलजी से जो संवैधानिक तरीके से इसका एक प्रॉपर चैनल हो सकता था, आप करते। रिसर्च वर्क के नाम पर अभी कुछ साथी कह रहे थे कि यहां पर रिसर्च सेंटर चल रहा था, हमें तो आज तक नहीं पता आठों विधायकों को कौन सा रिसर्च सेंटर चल रहा था। कौन सी उसकी बिल्डिंग थी, कौन सा उसका ऑफिस था, कहां जाकर हम पूछ सकते थे। हम पार्लियामेंट भी जाते हैं कभी तो रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा एक हाल बना हुआ है किसी भी दल का कोई भी एमपी जाकर के वहां से अपनी चीज निकाल सकता है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिये या अपनों को फायदा पहुंचाने के लिये अवैध तरह से अपनाया हुआ एक रास्ता था। जिस प्रकार से फीड बेच यूनिट बनाई गयी थी और जिसके लिये अभी शायद कानून के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं किसको लपेटे में वो लेंगे, कानून अपना काम कर रहा है, उसी प्रकार से ये भी

अलोकतांत्रिक था। इस सरकार की आदत है कोई भी काम करे वो अलोकतांत्रिक तरीके से कर रही है, चाहे एफ बी यूनिट बनाये, चाहे फैलोशिप का काम किया चाहे वो शीश महल का काम किया कितने उसमें अलोकतांत्रिक तरीके अपनाये गये, पर्यावरण की दृष्टि से भी, पैसे की धान की दृष्टि से भी। जब एक्साईज पॉलिसी बनी नयी लिकर पॉलिसी उसमें भी गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की चेष्टा की गयी शराब ठेकेदारों को।

उसी प्रकार से ये सब मामला जनता से ध्यान हटाने के लिए है ताकि लोग घोटालों के बारे में चर्चा ना करें, ताकि जो दो मंत्री जेल में हैं, उसकी..। एक साथी कहने लगे शायद विनय मिश्रा जी कह रहे थे कि भई पैसा कोई केंद्र से तो ले नहीं रहे थे। अरे भई दिल्ली की जनता के टैक्स की, गाढ़ी कमाई का पैसा है ये। आप कैसे उससे मजाक कर सकते हैं। आप मिसयूज कर रहे हैं पैसे का। कभी विज्ञापन पर मिसयूज करते हैं और आप राजेश जी कह रहे थे कि दस परसेंट नहीं दिया, पेंशन की बात कर रहे थे। आप याद कीजिए पैरिफेरियल रोड जब बनाई दिल्ली के लिए भारत सरकार ने 3700/- करोड की रूपये की हिस्सेदारी दिल्ली सरकार ने पे नहीं की। प्रगति मैदान का भी टनल बना है, एक हजार करोड का, 20 परसेंट हिस्सा दिल्ली सरकार को देना था 200/-करोड रूपये दिल्ली सरकार ने एक भी रूपया नहीं दिया, तब भी केन्द्र सरकार ने उन कामों को दिल्ली की जनता के हित में पूरा किया और आप आज आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे ये बताईये सदन में

आज तक कोई रिपोर्ट पेश हुई है। तीन साल अगर फैलोशिप के हो गई क्या एक भी सदन में कोई रिपोर्ट है कि इस फैलोशिप से आउटकम क्या है, क्या रिसर्च किया है? हमारे पास भी फैलो आ रहे थे। कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे लेकिन मुझे तो कोई फायदा उसका नजर आया नहीं। जितनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर, जितने बड़े एजूकेशन के नाम पर था, मुझे उसका कोई फायदा नजर, कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा और मुझे तो एक शक लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, फैलोशिप सिर्फ उनको और उनके ऑफिस पर नजर रखने के लिए बने थे।.. ये ही कारण है, ये ही कारण है कि पिछली बार सदन में एक बार जब ये बात उठाई थी हमने तो सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने भी उसमें समर्थन करने का प्रयास किया था, पर उन्हें रोक दिया गया। अब पता नहीं कौन बॉस हैं, कौन रोक रहे हैं। अभी कुछ साथियों ने कहा कि इसमें दलितों की बात की, कुछ ने दलितों के लिए सफरेन्द्र जी ने कुछ कहा। अरे दलितों का सम्मान तो जो हमने किया है, बाबा साहब को जो सम्मान हमने पंच तीर्थ बनाकर दिया आज तक आजाद हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं दिया और धारा 370 जो कश्मीर में हटाई पहली बार वहां दलित भाई बहनों को वोट देने का अधिकार किसी ने दिया तो भारत सरकार, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। हमें आप दलितों को सम्मान करना सिखायेंगे। हमने रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति, हमने सम्मान दिया। आज scheduled tribes से हमने एक आदिवासी महिला

को बनाया तो.. हमने उनको सम्मान देने का काम किया। अब भैया पेट में तो दर्द होगा ही क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि, क्योंकि देखो लड़ाई करना आपकी आदत बन गई है।.. नजीब जंग जी से लडाई, अनिल बैजल जी से लड़ाई, वर्तमान एलजी से लड़ाई, केन्द्र से लड़ाई, पुलिस अधिकारियों से लड़ाई,.. कमिश्नर से लड़ाई, सभी लोगों से सिर्फ लड़ाई करना आपका मकसद बन गया है और ये ही कारण है, ये ही कारण है। कई बार मैं सोचता हूं कि मुझे आज अच्छा लगा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि भई अधिकारी क्यूं नहीं, आने चाहिए अधिकारी। मैं समर्थन करता हूं, आने चाहिए, क्यूं नहीं आने चाहिए। लेकिन रात को बारह बजे बुलाकर किसी चीफ सेक्रेट्री को धमकाओगे, पीटोगे तो शायद उनकी भी पीड़ा आहत होती होगी। तो क्यूं नहीं प्यार से काम कर सकते, क्यूं नहीं प्यार से काम कर सकते.. क्यूं नहीं प्यार से काम कर सकते? लड़ाई करना, टकराव करना, आपका मकसद है। दिल्ली की जनता का हित चाहते,..

...व्यवधान....

श्री अजय कुमार महावर: दिल्ली की सेवा करना चाहते तो निश्चित रूप से आप संविधान के अनुरूप काम करते और जन सेवा को प्रथम स्थान देते। लेकिन आपने जनसेवा को स्थान नही दिया है। आपने टकराव की राजनीति को और लड़ाई की राजनीति को स्थान किया है। मैं संजीव झा के इस प्रिविलेज का समर्थन नहीं करता हूं। उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मदन लाल जी।

श्री मदन लालः थैंक्यू स्पीकर मैडम for giving me time to speak on this matter and present the प्रस्ताव। स्पीकर मैडम 2013 में पहली बार श्रीमान अरविन्द केजरीवाल जी की कॉल पर हम में से बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वॉइन की। उससे पहले हम में से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं थे, न किसी का इन्ट्रेस्ट था। 2013 में अचानक उनकी कॉल पर कि corruption free society बनायेंगें, हम सब लोगों ने उनको ज्वाइन किया और 2013 में लोगों ने हमें बहुमत भी दिया। 28 सीट थी, भले ही हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई हो पर उस समय हमारे लिए चुनौती थी कि दफ्तर कहां चलायें। जो लोग पॉलिटिक्स में शुरू से थे उनके पास दफ्तर भी थे, बड़ी-बड़ी जगह भी थी। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से दफ्तर चलायें। मैंने भी अपने एक मित्र के घर में 10 X 10 का एक रूम लेकर पहली असेम्बली का मैम्बर रहते हुए अपना दफ्तर चलाया और मैं धन्यवाद करता हूं इस असेम्बली को, स्पीकर महोदय को कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके और उसमें सबसे ज्यादा योगदान मैं अरविन्द केजरीवाल जी जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं उनको देता हूं कि उन्होंने स्पोर्ट किया और स्पीकर महोदय ने सब एमएलऐज को एक-एक ऑफिस दूसरी विधान सभा के समय मुहैया कराया जिसकी वजह से हमने अपने ऑफिस वहां चलाने शुरू किये। जब ऑफिस चलाया तो पता चला कि हमें दो-दो लोग मिले हैं जिनकी तनख्वाह पन्द्रह-पन्द्रह हजार रूपये थी।

दिल्ली में मिनिमम वेजिज एक्ट चालू है। जहां 16782/- रूपया unskilled labour को मिलते हैं। जब मैं unskilled labour कहता हूं तो वो पढ़ा लिखा आदमी जो सड़क पर रोजगारी कर रहा है, जो unskilled है जिसको कुछ आता जाता नहीं है, उसकी तनख्वाह 16782/-रूपया है। जो semi-skilled है उसकी तनख्वाह 18499/- रूपये हैं। पर तनख्वाह...

...व्यवधान...

श्री मदन लालः नहीं तो मैं आपकी बताने लगूंगा, मैं तो फैलोज की बात कर रहा हूं। उनकी तनख्वाह जो semi-skilled है 18499/-है पर विधान सभा क्या दे रही थी, दो लोग पन्द्रह-पन्द्रह हजार के। मुझे कई बार अचरज आया जब मैं एमएलए बना कि पिछले वाले एमएलए काम कैसे कर रहे थे। भई तनख्वाह अगर वो पन्द्रह हजार रूपये दे रहे लेबर को तो वो आदमी इतना पढ़ा लिखा कहां उनके दफ्तर में काम कर रहा था, बारह हजार, चौदह हजार या पन्द्रह हजार में मैक्सिमम पन्द्रह हजार में। इसका मतलब वो चोरी कर रहे थे या कहां से ले रहे थे। बहुत दिन हुए विधान सभा ने समझा, स्पीकर साहब ने समझा और उसके बाद उन्होंने फैलो देने की मन में ठान ली। ये वो समय था 2019, 27 फरवरी को general purpose committee के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पर डिस्कशन हुई और हर विधायक को एक-एक फैलो देने का फैसला हुआ। उसके लिए बकायदा एक कमेटी बनी। कमेटी ने सफझाव दिया, सफझाव देने के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन

की बात की गई और अखबार में ऐड निकाली और 2900 लोगों ने अप्लाई किया। Delhi Technological University ने इन्टरव्यू लिये और 116 लोग विधान सभा के strength पर रखे गए। अब सवाल उठता था कि ये लोग विधान सभा ने रखे या गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये 27 फरवरी, 2019 को विधान सभा की उस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया General Purpose Committee ने और इसको विधान सभा के सदन पटन पर रखा गया। यहां सब लोगों की सहमति ली गई और विधान सभा ने उनको अप्वाइंट किया। जब अप्वाइंट किया तो उनके बारे में सबसे पहले चिट्ठी में लिखा गया, अप्वाइंटमेंट करते हुए that the candidate to the fellowship programme shall on no account be treated as a claim to employment/ appointment in the Delhi Assembly or Delhi Govt. इसका मतलब था कि जो भी फैलोशिप के प्रोग्राम में लोग लिये जा रहे हैं ये कभी भी एम्पलायमेंट क्लेम नहीं करेंगे, एम्पलाइ नहीं समझे जायेंगे और इनका termination या appointment जो आर्टिकल 309 के मुताबिक होता है जो सिविल पोस्ट के लिए होता है या ऑफिस के लिए होता है वो भी नहीं था। उनका रिमूवल जो आर्टिकल 311 के हिसाब से होता है वो भी नहीं था। इसका मतलब ये appointment इनकी एम्पलायमेंट बिल्कुल भी नहीं थी और केवल और केवल विधान सभा के स्पीकर के discretion पर विधान सभा के हाउस के discretion पर थी। लिहाजा सीधे-सीधे appointment दिल्ली विधान सभा ने की थी। फिर हटाने का परपज और हटाने

का प्रोग्राम कौन कर सकता है, हटाने की पावर किसको है? हटाने की पावर अगर दिल्ली सरकार का कोई एम्पलोई है तो दिल्ली गवर्नमेंट को, अगर कोई केन्द्र का है तो केन्द्र को और अगर विधान सभा ने employment नहीं दी है बल्कि फैलोशिप प्रोग्राम है। क्योंकि इसका तो नाम ही था दिल्ली असेम्बली फैलोशिप। तो कहां का appointment थी ये जो इसको हटाने की अब सेक्रेट्री फाईनांस को जरूरत पड़ी या जो एक बड़ी सरकार है उसको पड़ी। तो ये सीधे–सीधे एक ऐसा षडयंत्र है कि सरकार के काम को कैसे रोका जाये। अभी हमारे एक और साथी संजीव झा जी ने कहा कि उनके यहां एक पीएचडी काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे।

मेरे दफ्तर में एक फैलो लगे थे। मैं आपको बता दूं पीएचडी के लिये उनको स्वीडन से स्कॉलरशिप मिल गई और वो वहां चले गये स्वीडन, पीएचडी सांइस में। दूसरा एक होम्योपैथिक के डॉक्टर थे वो रिसर्च का काम कर रहे थे।जब कोई लोग कहते हैं कि मुझे फायदा नहीं लगा, सदन पटल पर नहीं रखा, जिस समय जितने दिन दफ्तर में काम कर रहे थे सब लोग बड़े खुश होकर उनका स्वागत कर रहे थे क्योंकि 15 हज़ार का आदमी को अगर में एक्सपेक्ट करूं कि वो चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख देगा, सी.एम. साहब को चिट्ठी लिख देगा, मैं कभी नहीं मानता। हमको धन्यवाद करना चाहिये बार–बार स्पीकर साहब का और इस हाउस का और अल्टिमेट्ली अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने ये फैलो

देकर हम लोगों को फायदा नहीं किया बल्कि दिल्ली की जनता को फायदा किया जिसके लिये हम सब लोग अपने दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं। हम अपने दफ्तरों में बैठकर एमएलए का काम अपने लिये कभी नहीं करते। हमारा कोई काम नहीं है एमएलए का कि मुझे अपने घर में बिजली लगवानी है इसलिये मुझे एमएलए चाहिये, मुझे लोगों के लिये काम करना है, उनका सीवर दिखवाना है, उनका पानी दिखवाना है, उनके स्कूल के एडमिशन दिखाने हैं, उनको मदद करनी है, उनको बैंक में मदद करनी है, उनको सब सिस्टम में मदद करनी है और उसके लिये पढ़ा-लिखा आदमी चाहिये और इतना अगर दिल्ली टैक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी के संरक्षण में अगर कोई एपोंइटमेंट हो रही है तो फिर कौन उस पर उंगली उठा सकता है? तब तक तो, 2019 तक तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, तब तो माननीय विपक्ष भी वहां उस समय तो they were enjoying the fruits, बड़े चाव से उन्होंने रखा हुआ था, एक दिन भी किसी फैलो को वापस नहीं किया कि फैलो काम के नहीं हैं या ये हमारे दफ्तर में नज़र और आपके दफ्तर में कौन सा कोई चोरी थोड़ी हो रही है जो नज़र रख रहे हैं, वहां कोई गलत काम थोड़ी हो रहे हैं जो आपके दफ्तर पर नज़र रखेगा। हमारे दफ्तर में रोज़ हज़ारों आदमी आते हैं, हम तो किसी को शक की नज़र से नहीं देखते, हम तो बैठ कर कहते हैं चाय पीकर जाना, काम और बताना। आप भी ऐसे ही करते होओगे, तब आपका ये कहना कि वो शायद दफ्तर पर नज़र रख रहे थे,

भाईसाहब शब्दों को संभालकर बोलिये। हम लोग यहां सिस्टम के लिये काम कर रहे हैं और जब हम सिस्टम के लिये काम कर रहे हैं तो हमको धन्यवाद करना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि जब आपको पीएचडी जैसे लोग, एमएससी जो सबसे टॉप क्लास पढ़े-लिखे लोग अगर आपके दफ्तर में दे रहे हैं और विधानसभा दे रही है तो आपको बार-बार धन्यवाद करना चाहिये। इस विधानसभा ने आपको सबसे पहले ऑफिस दिया, आप अपने घर से ऑफिस चला रहे थे मैं अपने घर से नहीं चला पाता क्योंकि मेरा घर छोटा था। मैं उसमें ना दिन में सो सकता हूं ना रात को सो सकता हूं। लोग रात को 11.00 बजे से पहले जाना नहीं चाहते, सुबह 7.00 बजे दरवाज़ा खटखटाते हैं। इस विधानसभा ने हमको ऑफिस दिया। हमको एक मान-सम्मान से अपने घर में रात को सोने का मौका दिया है, हमको बार-बार धन्यवाद करना चाहिये। ये मुझे लगता है सबसे पहली विधानसभा है दिल्ली की और मैं माननीय केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि उनकी सोच ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा एमएलए साबित होने का मौका दिया है, इन्होंने बाद में हमको टैबलेट्स दिये। कभी सोचा, आप लोग हमसे बहुत पुराने हो, हम तो अभी तीन बार के बने हैं, आप तो हमसे पहले, हो सकता है 13 बार नहीं पर आठवीं बार जरूर बन गये होओगे पहले हमसे। आप तो आदिमानव हो चुके हो आजकल आप में से बहुत सारे तो। आपके ज़माने में तो अगर कोई ऐसी चीज़ कभी हुई हो तो हमें बता दो ना, भाईसाहब सिर्फ केजरीवाल जी की दिक्कत यही

है और इसीलिये ये उनके राडार पर हैं, इसलिये वो लोग और वो लोग क्यों, आप लोग, पर आप तो खैर आपको क्या कहें, आप तो कुछ हो ही नहीं, वो बहुत कुछ हैं इसलिये उनके राडार पर हैं कि ये नई–नई चीज़ कर क्यों रहे हैं। जैसे पीछे बीजेपी सरकार चल रही थी चलते रहते, स्कूल नहीं बनाते, हॉस्पिटल नहीं बनाते, मोहल्ला क्लीनिक ना बनाते, लोगों को घर बैठे सर्विस ना देते, महिला क्लीनिक की बात ना करते, 6 रुपये में 20 लीटर पानी की बात ना करते, बस फ्री नहीं करते, बच्चों को विदेश नहीं भेजते, टीचर्स को विदेश नहीं भेजते, तो ये अच्छे मुख्यमंत्री साबित होते। चूंकि इन्होंने लीक से हटकर काम करना शुरू कर दिया, आपको लगा ये आदमी खतरनाक है, ये गद्दी पर कब्जा कर सकते हैं, तो गद्दी का खतरा है। खतरा दिल्ली का नहीं है, दिल्ली तो उन्होंने समझ ली है दिल्ली कभी वापस नहीं आयेगी जब तक केजरीवाल जी जिंदा रहेंगे, अभी तो केवल केन्द्र का निशाना है, वहां बचाना है, वहां बात करनी है। इनसे सर्विस छिनो, फिर जल बोर्ड छिनो, फिर निकाय छिनो, फिर एपांइटमेंट छिनो, अब इलैक्शन कमिशन को छिनो, फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिज़ छीनो, अरे साहब कुछ भी छीनते रहोगे, परमानेंट नहीं हो, 2024 में दिखा देंगे। अब लोग भी समझने लगे हैं जो कल तक लोग बीजेपी को अच्छा बता रहे थे आज वो ही लोग बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं अंहकारी हैं, वो लगता है रावण है, कोई कहता है कंस है। आप ज़्रा पब्लिक में घूमकर देखो, अपने

ऑफिस की बात करते हो और 116 फैलो इतने बढ़िया लोग जो हर एमएलए को दिये गये वो केवल पब्लिक के फायदे के लिये दिये गये चूंकि पब्लिक का इसमें फायदा था इसलिये उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनरेबल मैडम, मुख्यमंत्री जी ने हमको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया था उसमें साफ–साफ लिखा था they shall not be paid any remuneration for this. They shall not be given any office, however they can claim the public transport for the purpose of going to that office. Public transport था बस में लटककर जाना। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब 2014–15 था जब बस में ही लटककर जाना था, हमारी सरकार तो थी ही नहीं, बस में लोग लटककर ही जा रहे थे। आज की बस होती तो भी हम मान लेते कि केजरीवाल जी ने अपने एमएलएज़ को डीटीसी की एयरकंडीन्ड बस में जाने का मौका दे दिया, बहुत बड़ा फायदा कर दिया। हालांकि अब तो उन्होंने महिलाओं को भी ये ऑपोरचुनेटी दे दिया, पर तब तो मान लेते हमें कुछ फायदा मिला था। उन्होंने तो हमें कुछ नहीं दिया इन्हीं की वजह से बहुत दिन हम लोग वहां मुकद्मा भुगतते रहे और आपको सबसे बड़े अचरज की बात बतायें ये कितने हमारे विरोधी हैं, राष्ट्रपति महोदय ने रात के 1.00 बजे गुजरात जाते हुये उस आर्डर पर साइन किये कि इन 13 मैम्बर्स की जो–जो.. 21 सॉरी, 21 मैम्बर्स की जो मैम्बरशिप है वो टर्मिनेट की जाती है, रात को 1.00 बजे। ये कितने अचरज की बात है! आप कहां की बात कर रहे हो और

ये फैलो हम कभी नहीं कहते वो बेचारे गरीबों की रोजी-रोटी पर लात लगी है। वो ना गरीब हैं, ना बेसहारा हैं, सबसे ज्यादा अव्वल पढ़े-लिखे लोग दिल्ली विधानसभा में फैलोशिप पर काम कर रहे थे। आप मैं से कोई हर एक एमएलए, अरे आप भी, आपके साथी भी एक आदमी बता दो कि मेरा फैलो incompetent था और मैंने उसको रह जाने दिया। आपने जब 4 साल तक उनको अपने यहां रखा है तो इस बात का फ्रू है कि आप लोगों ने उन 4 साल तक उनकी खूब ज्यादा यूटिलिटी को अपने फायदे के लिये इस्तेमाल किया है। आप लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिये, आपको इस सदन का धन्यवाद करना चाहिये, आपको स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहिये, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिये कि आपको फैलो के रूप में आपको एक सहायक मिला जिसने आपके काम को बहुत ज्यादा आसान और लोगों को फ्रेंडली कर दिया। मैं जानता हूं मेरे यहां कैसे काम करते थे।..

माननीया अध्यक्षः कम्प्लीट कीजिये।

श्री मदल लालः हमें एक बार उनको बताना होता था कृपया एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के नाम लिख दो, कृपया एक चिट्ठी मंत्री जी के लिये लिख दो, केवल एक चिट्ठी सीईओ के लिये लिख दो, उसके बाद हम भूल जाते हैं, 15 हज़ार के आदमी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे और ये इसीलिये जो बार-बार एक सवाल आ रहा है कि प्रिविलेज़ का मामला क्यों है, प्रिविलेज का मामला इसलिये है कि ये मामला विधानसभा की इस कमेटी ने,

उस कमेटी के बाद विधानसभा के सदन ने स्पीकर साहब के यहां मौजूद रहते हुये इस प्रस्ताव को पारित किया था और चूंकि ये प्रस्ताव इस विधानसभा का था, इस विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों ने जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं क्योंकि आपने उन फैलो को इस्तेमाल किया है, इसलिये परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपने भी उनकी एपोइंट्मेंट को सराहा, एक्सेप्ट किया इसलिये इनको हटाने का अधिकार किसी भी और अधिकारी को बिल्कुल नहीं है और अगर ऐसा है तो ये इस सदन की अवमानना है। ये सरकारी नौकर नहीं हैं, ये इस सदन के माध्यम से एपोंइटिड थे, लिहाजा ये सदन की अवमानना हुई है। इस सदन को इस बात के लिये उन सभी लोगों को पाठ पढ़ाना चाहिये जिन लोगों ने सदन की अवमानना की है, इसलिये मैं आपके माध्यम से एक प्रस्ताव रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विशेषाधिकार के इस मामले से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

''यह सदन सहमत है कि ये प्रथम दशष्टया विशेषाधिकार हनन का मामला है और सदन की अवमानना की गई है, अतः इस मामले को परीक्षण, जांच और रिपोर्ट के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये'', धन्यवाद।

माननीया अध्यक्ष: श्री मदन लाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है। इसी विषय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा भी एक मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है, अतः मैं विशेषाधिकार समिति को निर्देश देती हूं कि उक्त दोनों मामलों के संबंध में एक महीने में अपनी रिपोर्ट सदन पटल पर प्रस्तुत करें।

धन्यवाद प्रस्ताव, माननीय सदस्य जय भगवान उपकार जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जय भगवानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदया, जैसे की हम जानते हैं की हरियाणा के चारों तरफ जैसे हरियाणा, गुडगांव, खरखौदा, सोनीपत और इधर फरीदाबाद, इधर नोएडा के अंदर जो ज़मीनों के जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं लेकिन दिल्ली का जो किसान है वो अपने आपको असहाय सा महसूस कर रहा था, वो महसूस कर रहा है कि जब उसके आस-पास के जो राज्य हैं उनके अंदर किसानों की जो ज़मीनों के जो रेट हैं वो काफी

बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली के किसानों का जो ज़मीनों का जो रेट है वो काफी कम है लेकिन दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ज़मीनों के रेट जो पिछली सरकारों के द्वारा 2007 में 15 लाख से 53 लाख किये गये थे। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, अरविन्द केजरीवाल जी ने उन्हें उन सर्किल रेटों को 10 गुना बढ़ा करके दिल्ली के किसानों को मालामाल किया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के किसान के जो सर्किल रेट बढ़े हैं, इनसे जो दिल्ली का जो किसान है, वो अपने आपको बहुत ही गर्व से यह महसूस कर रहा है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार किसानों की मदद की है। चाहे मैं कहूं कि जिस प्रकार से यहां पर किसान आंदोलन हुआ, उसमें चाहे मैं पानी की बात करूं, चाहे मैं वाई-फाई की बात करूं, चाहे मैं किसान रसोई की बात करूं, हर तरीके से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहां के किसानों को मदद दी है, देश के किसानों को मदद दी है क्योंकि इस देश के अंदर किसान आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था जिसके अंदर किसानों को मदद की जरूरत थी और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की मदद करते हुए केन्द्र सरकार को जेल बनाने के लिए जमीन भी नहीं दी थी, अध्यक्ष महोदया।

अध्यक्ष महोदया, दूसरा जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर किसानों की जो फसल है वो बारिश से नष्ट हो गयी थी और पहली बार इसी सरकार ने एक हैक्टेयर जमीन पर करीब करीब 50 हजार

रुपए मुआवजा हमारी सरकार के द्वारा दिया गया, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, अरविन्द केजरीवाल जी के द्वारा दिया गया।

अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना ये है कि एक तो वो सरकार है जो किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के विकास के लिए काम कर रही है और एक वो सरकार है जो किसानों के ऊपर पत्थर फेंकवाती है। किसानों के खिलाफ तीन नये कानून लेकर आए थे, जिसमें सात सौ किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना ये है कि एक वो सरकार है जो लगातार ये चाहती है कि किसानों का कल्याण होना चाहिए और एक वो सरकार है जो किसानों के खिलाफ है।

तो अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किसानों की जमीनों के रेट जो सर्किल रेट है, वो 10 गुना बढ़ाए हैं, उससे हमारा जो दिल्ली का किसान है और जो भारतवर्ष का किसान है,.

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए कृपया।

श्री जय भगवानः वो उन्हें बड़ी आशा की दृष्टि से देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री बन करके और जल्दी से जल्दी पूरे देश के किसानों को ये राहत महसूस करायें।

तो जिस प्रकार से पूरे भारत का किसान ये चाहता है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जमीनों के रेट 10 गुना बढ़ाए गए

हैं, उस प्रकार से पूरे देश में भी बढ़ने चाहिए। तो मैं सदन के माध्यम से दिल्ली देहात के किसानों की तरफ से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि आज उनका जन्म दिन भी है, तो मैं इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली देहात के किसानों की तरफ से कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के किसानों के सर्किल रेट बढ़ाए हैं और दिल्ली देहात के किसान उन्हें तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत से किसान उनसे मिलना भी चाहते हैं और उनके लिए सभा भी करना चाहते हैं और उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बी.एस.जून जी।

श्री बी.एस.जूनः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, 2008 से दिल्ली में सर्किल रेट जो एग्रीकल्चर लैंड के थे, वे एज इट इज चल रहे थे। किसानों की दिल्ली देहात की एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि इनको रिवाईज किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रपोजल को अब आकर अप्रूव किया। न्यू दिल्ली और साउथ डिस्ट्रिक्ट का जो सर्किल रेट है, वो पांच लाख कर दिया, पांच करोड़ सॉरी, पांच करोड़ कर दिया। नोर्थ, वेस्ट, नोर्थ-वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का तीन करोड़ कर दिया। पहले जो 53 लाख रु0 पर एकड़ होता था।

अध्यक्ष महोदया, बहुत किसान परेशान थे क्योंकि मेरे यहां एक गांव हैं बिजवासन, उससे अक्रॉस द रोड एक गांव है हरियाणा का, वहां 12 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन का सर्किल रेट था, जबकि हमारे यहां सिर्फ 54 लाख एकड़ था, तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना उपकार किया है किसानों पर कि दिल्ली के किसान इससे बहुत खुश हैं और उनका धन्यवाद करते हैं और हम सभी जो भी रूरल बेल्ट से जो विधायक हैं, वो भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के जो किसान हैं, दिल्ली देहात को इतना बड़ा तोहफा, उपहार दिया, उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।

दिल्ली को जो है, ये डिमांड 2013 से मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग थी और उन्होंने कभी भी इसको अपोज नहीं किया बल्कि इसके फेवर में थे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर आफिस से कहीं न कहीं, कोई न कोई अड़चन आती रही। अब दिल्ली को तीन गांव में बांट दिया:- ग्रीन बेल्ट विलेज, अर्बनाइज विलेज और रूरल विलेज। तो हर गांव में जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड बची हुई हैं, उसका बैनिफिट किसानों को होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं किसानों की तरफ से और किसान भी खुद आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते, कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीया अध्यक्षः गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया और दिल्ली की किसानों की वर्षों की जो डिमांड थी क्योंकि अभी तक हमारी जमीन की जो सर्किल रेट थे करीबन 53-54 लाख रुपए पर एकड़ थे और जबकि आस पास के सटे हुए जो शहर हैं गुड़गांव हैं जैसा भाई साहब ने बताया, वहां पर कई गुना सर्किल रेट पहले से ही है। अब इसका क्या फायदा और क्या घाटे हैं, मैं इसका एक बहुत अच्छा फायदा बताना चाह रहा हूं। मेरे यहां पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था वर्ष 2019-20 में। एक किसान की जमीन का अधिग्रहण हुआ और उसको 52 लाख 60 हजार रुपए के हिसाब से उसकी जमीन का नोटिस.. सेक्शन चार हुए, सेक्शन छः हुए, सेक्शन नौ हुए और उस अधिग्रहण के खिलाफ वो किसान दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। करीबन 20 कॉलोनियां चार-पांच गांव में वो एसटीपी बनना था और अभी तक हाई कोर्ट के अंदर वो मामला लंबित है और उन कॉलोनियों में अभी तक सीवर लाइन नहीं डल पाई है क्योंकि किसान इस बात पर गुस्से में था कि जहां पर वो जमीन है, वहां तीन-चार करोड़ रुपए एकड़ का रेट है वहां पर रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। उसने वो रजिस्ट्रियां लेकर चैलेंज कर दिया सरकार को। जो ये नया सर्किल रेट लागू होगा, इससे इस तरीके की समस्या से भी निदान मिलेगा। आने वाले समय में सरकार के, डीडीए के जो भी कोई प्रोजेक्ट होंगे, उनमें इससे बाधा बिल्कुल

नहीं आएंगी। न कि सिर्फ 10 परसेंट सर्किल रेट बढ़ाये हैं, मुझे याद है 2015-16 की बात है, ओला बृष्टि से पूरे दिल्ली देहात की फसलें बर्बाद हुए। हम कई सारे एमएलए सीएम साहब के पास आए। हमने सर से कहा सर किसान बर्बाद हो गए, उनको मुआवजा चाहिए, तो बोले पहले क्या मिलता था। हमने कहा सर 1700 रुपए दिये थे साहिब सिंह वर्मा जी ने, तो बोले 5 हजार दे दें। मैने कहा सर बहुत खुश हो जाएंगे लोग, बोले ठीक है एक बड़ी सभा रखो। तो हमने बवाना में एक बड़ी सभा रखी और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गयी जब उन्होंने आकर 20 हजार रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा न कि सिर्फ ऐलान किया, तीन महीने में किसानों के अकाउंट में पैसा आ गया। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं 70 रुपया आए किसानों के खाते में 70 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, ये हालात उस गुजरात प्रदेश का है जहां पर तीस साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। देश का अकेला मुख्यमंत्री है, जो इस देश में सबसे बड़ा मुआवजा देने का काम अरविन्द केजरीवाल ने किसानों को किया है। अब मैं इससे और आगे बढ़ता हूं। मेरे यहां 35 गांव हैं। मेरे गांव से बच्चे खेलने के लिए शिवाजी स्टेडियम आते थे। दो घंटे, ढाई घंटे आने के और दो, ढ़ाई घंटे जाने के और entry मिल जाए तो गनीमत की बात है और आज मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मेरे खुद के गांव में 500 बच्चे आज हॉकी खेल रहे हैं, दिल्ली की

टीम वहां से बनती है। राष्ट्रीय टीम में खेले हैं और आज कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट चाहे वो सर्विसेस हो, नेवी हो, हमारे गांव देहात के बच्चे हर उस टीम के अंदर मिलेंगे और एक-डेढ़ लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये फायदा उस स्टेडियम से हुआ।

इसके अलावा अभी तीन चार गांव में हम ग्रामीण विकास बोर्ड से इन्डोर स्पोर्ट्र्स कॉम्पलेक्स बना रहे हैं, जो कभी गांव वालों ने सोचा भी नहीं था कि ये होगा, पोसिबल है, जिसका हम अगले दो महीने में काम शुरू करने जा रहे हैं। इससे आगे और बढ़ूं आजाद भारत के इतिहास में क्या कोई सोच सकता है देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे भी गांव हैं, जहां पर मोहल्ला क्लीनिक आज तक नहीं है। कुछ गांव में मोहल्ला क्लीनिक बच गए दो तीन गांव हैं, उनमें भी करने जा रहे हैं। लेकिन, दिल्ली देहात के करीबन 20 गांव मेरी विधान सभा की बात कर रहा हूं, 20 गांव में पहली बार स्वास्थ्य सेवा देने का काम इसी अरविन्द केजरीवाल सरकार ने किया जो कि अपने आपमें एक धार्म का काम भी है, पुण्य का भी काम है। कभी नहीं सोचा था कि खेतों से खेतों में जाने वाले रास्ते, गांव से गांव में जाने वाले रास्तों पर कभी सीमेंट के रोड बनेंगे, कभी उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगेगी। कभी आप साथियों को आने का मौका मिले तो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। नजफगढ़ विधान सभा, मटियाला विधान सभा, बवाना विधान सभा, मैं सैल्यूट करता हूं अपने सारे विधायक साथियों से जो आपने देहात के अंदर जो

काम करके दिखाया है। आज मैं चुनौती देता हूं, ऐसे स्कूल मैं अपने देहात में दिखा दूंगा कि जहां भी भाजपा रूलिंग पार्टी जिन राज्यों में है, एक स्कूल दिखा दे, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं दिल्ली सरकार जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ, राजनीति से आज इस्तीफा दे देंगे। एक भी, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है और चैलेंज किया था हमने गुजरात में कि एक स्कूल दिखा दें दिल्ली जैसा पूरे गुजरात के अंदर जहां 30 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सौ सौ किलोमीटर में स्कूल नहीं है। सूरत, जहां की आबादी करीबन करीबन 50 लाख है, एक 12वीं क्लास तक का स्कूल है, आप हैरान हो जाओगे एक। ये हालात उन राज्यों के हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया और दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं, उनको एन्वाइट कर रहे हैं। मटियाला विधाना सभा क्षेत्र में मैं जल्द हमारे वहां के किसान जो हैं, उनका स्वागत करेंगे, जल्द उनकी सभा भी वहां रखवा रहे हैं और आज उनका जन्म दिन हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही जनता की सेवा में लगे रहे। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 17 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 17 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।